KUMAUN GARHWAL
CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY
UTTARAKHAND

CHAMBER HOUSE, INDUSTRIAL ESTATE, BAZPUR ROAD, KASHIPUR, DISTT. U. S. NAGAR (UTTARAKHAND)
PHONE : (05947) 262478, E-mail : kgcci10@gmail.com, Website : www.kgcci.in

केजीसीसीआई / पी / 490 / प्री–बजट / 2022–23 दिनाँक : 14.05.2022

विषय : उत्तराखण्ड राज्य के समन्वित विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु जारी होने वाले बजट में शामिल किए जाने हेतु कुछ महत्त्वपूर्ण सुझाव

मान्यवर,

कुमायूँ गढ़वाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री (केजीसीसीआई) वर्ष 1987 में स्थापित औद्योगिक विकास को समर्पित उत्तराखण्ड की अग्रणी औद्योगिक संस्था है जो कि उद्योगों, सरकारी विभागों एवं सरकार के साथ सामंजस्य स्थापित कर राज्य के औद्योगिक विकास के लिए सतत् प्रयत्नशील है।

उत्तराखण्ड राज्य के समन्वित विकास हेतु वित्तीय वर्ष 2022–23 हेतु जारी होने वाले बजट में शामिल किए जाने हेतु हम आपके समक्ष निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत करते हैं–

1. **राज्य में विभिन्न उद्योग नीतियों के अन्तर्गत स्थापित उद्योगों के बिजली बिलों में छूट, बैंक ऋण पर ब्याज में छूट इत्यादि दावों के भुगतान के सम्बन्ध में।**

   मान्यवर, आपको अवगत कराना है कि राज्य में उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर औद्योगिक नीतियाँ जारी की जाती हैं। इन्हीं औद्योगिक नीतियों में वर्णित प्रोत्साहनों से आकर्षित होकर उद्यमी अपने उद्योगों की स्थापना करते हैं।

   प्रायः देखने में आता है कि केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी औद्योगिक नीतियों के अन्तर्गत प्रदान किए जाने वाले प्रोत्साहनों के दावों के भुगतान हेतु उद्यमियों को सम्बन्धित

विभागों के निरन्तर चक्कर काटने के बावजूद भी उनके दावों का समय से भुगतान सम्भव नहीं हो पाता जिससे उद्यमियों को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है।

वर्तमान में राज्य में मेगा टैक्सटाईल पार्क पॉलिसी, 2014, मेगा इण्डस्ट्रियल एवं इन्वेस्टमेण्ट पॉलिसी, 2015 केन्द्र सरकार द्वारा घोषित "हिमाचल प्रदेश (हि.प्र.) एवं उत्तराखण्ड हेतु औद्योगिक विकास स्कीम, 2017 के अन्तर्गत स्थापित उद्योगों के पावर सब्सिडी, ब्याज सब्सिडी एवं अन्य प्रोत्साहनों के दावे लम्बित हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि राज्य के औद्योगिक विकास को ध्यान में रखते हुए उद्योगों द्वारा प्रस्तुत औद्योगिक नीतियों में प्रदत्त छूट दावों का समय से भुगतान कराए जाने हेतु आगामी बजट में समुचित प्रावधान कराया जाना चाहिए ताकि राज्य के उद्योग सुचारू रूप से चलते रहें।

2. **वित्तीय वर्ष/कर निर्धारण वर्ष 2021–22 तक के बकाया व्यापार कर की स्थिति में स्वीकृत/सृजित कर जमा कराये जाने पर ब्याज एवं अर्थदण्ड माफी हेतु योजना लाये जाने के सम्बन्ध में।**

मान्यवर, राज्य सरकार द्वारा जनहित में निर्णय लेते हुए इकाईयों की ओर वित्तीय वर्ष/कर निर्धारण वर्ष 1988–89 से वित्तीय वर्ष/कर निर्धारण वर्ष 2021–22 तक के समस्त करों की पुरानी बकाया जिसे कतिपय कारणों से सरकार वसूल नहीं कर पाई है तथा जिसके विरुद्ध विवाद की स्थिति में कुछ व्यापारियों के केस कोर्ट में भी चल रहे हैं। इससे समय एवं धन का भी अपव्यय हो रहा है। व्यापार कर की ऐसी बकाया के समापन एवं ब्याज/अर्थदण्ड माफी हेतु एक योजना लाये जाने की आवश्यकता है जिससे कर की वसूली भी हो जाए तथा व्यापारी कोर्ट इत्यादि के चक्कर लगाने से भी बच सकें।

इसके अन्तर्गत बकाया व्यापार कर की मूल धनराशि जमा करा कर ब्याज एवं अर्थदण्ड को माफ किए जाने की योजना लाए जाने की आवश्यकता है। इसके साथ ही जिन उद्यमियों/व्यापारियों द्वारा व्यापार कर की मूल धनराशि पूर्व में ही जमा करा दी गयी है उन पर देय ब्याज एवं अर्थदण्ड को भी माफ किया जाना चाहिए।

मान्यवर, इस सम्बन्ध में सरकार पूर्व में दो बार योजना ला भी चुकी है परन्तु जटिल शर्तों के कारण न तो इकाईयाँ इसका लाभ ले पायी हैं और न ही सरकार को कर की वसूली हो पायी है। अतः आपसे अनुरोध है कि इस योजना को लचीले नियमों के तहत लाया जाना चाहिए।

3. प्लास्टिक रिसाइक्लिंग उद्योगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने हेतु प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष बनाए जाने के सम्बन्ध में।

मान्यवर, स्वच्छ भारत एवं पर्यावरण संरक्षण हमारी प्राथमिकता है और प्लास्टिक कचरा हमारी समस्या है इसीलिए आपसे निवेदन है कि प्लास्टिक रिसाइक्लिंग उद्योगों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष बनाया जाना चाहिए ताकि आधुनिकीकरण के तहत बेहतर से बेहतर प्रौद्योगिकी को इस्तेमाल करके अच्छा प्रोडक्ट बनाया जा सके जैसा कि टैक्सटाइल सेक्टर को RTUFF के रूप में आधुनिकीकरण के लिए दिया जाता है।

4. प्लास्टिक उद्योगों को रिसाईक्लिंग के अनुसार रिन्युएबिल एनर्जी सर्टीफिकेट दिए जाने के सम्बन्ध में।

मान्यवर, वर्तमान में राज्य में प्लास्टिक रीसाइक्लिंग उद्योगों को बढ़ावा देने की आवश्यकता है, अतः आपसे निवेदन है कि प्लास्टिक रीसाइक्लिंग उद्योग को, जितना प्लास्टिक recycle करे, उस हिसाब से renewable एनर्जी सर्टिफिकेट दिया जाना चाहिये जिससे कि प्लास्टिक रीसाइक्लिंग उद्योग प्रोत्साहित होंगे।

5. किसानों से खरीदे गए धान का समय से भुगतान कराए जाने हेतु बजट में प्रावधान किए जाने के सम्बन्ध में।

मान्यवर, हमारी राईस मिल सदस्य इकाईयों द्वारा अवगत कराया गया है कि सरकार द्वारा राईस मिलों को कमीशन एजेण्टों के द्वारा खरीदे हुए धान का भुगतान 6–6 महीने में किया जा रहा है जिससे कमीशन ऐजेंटों एवं राईस मिलों को अत्यधिक वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है।

इस सम्बन्ध में आपसे अनुरोध है कि आगामी बजट में यह प्रावधान किया जाना चाहिए कि कमीशन ऐजेंटों द्वारा खरीदे गए धान का भुगतान उन्हें 15 दिन के अन्दर ही कर दिया जाए ताकि स्थानीय स्तर पर कार्यरत राईस इण्डस्ट्री पर किसी प्रकार का दुष्प्रभाव न पड़े तथा वह सुचारू रूप से चलती रहे साथ ही कमीशन एजेंटों को भी वित्तीय संकट का सामना न करना पड़े।

6. राज्य सरकार द्वारा चावल के भण्डारण हेतु पर्याप्त क्षमता के गोदामों का निर्माण कराए जाने के सम्बन्ध में।

मान्यवर, हमारी सदस्य राईस मिल इकाईयों द्वारा अवगत कराया गया है कि सरकार के पास चावल उतारने हेतु पर्याप्त क्षमता के गोदाम उपलब्ध नहीं है।

अतः आपसे अनुरोध है कि राज्य सरकार द्वारा चावल के भण्डारण हेतु 2 लाख मीट्रिक टन के नए गोदामों का निर्माण अथवा उपयुक्त स्थानों पर गोदाम किराए पर लिए जाने का प्रावधान किया जाना चाहिए।

7. कृषि मन्त्रालय द्वारा बाहर से आने वाले धान से बने चावल पर दुबारा से मण्डी समिति की माँग को खत्म कराए जाने के सम्बन्ध में।

मान्यवर, आपको अवगत कराना है कि कृषि मन्त्रालय के द्वारा बाहर से आने वाले धान से बने चावल पर दुबारा से मण्डी समिति की माँग की जा रही है जो कि चावल व्यापारियों के हित में नहीं है।

अतः आपसे अनुरोध है कि कृषि मन्त्रालय द्वारा बाहर से आने वाले चावल पर दुबारा से की जा रही मण्डी समिति की माँग को खत्म कराया जाना चाहिए।

8. राज्य में निर्यात को बढ़ावा देने हेतु बन्दरगाह से माल ढुलाई के खर्च की भरपाई हेतु बजट में परिवहन सब्सिडी का प्रावधान किए जाने के सम्बन्ध में।

मान्यवर, आपको अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड राज्य पोर्ट (बन्दरगाह) से कम से कम 1,500 कि.मी. दूर है। गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना आदि बन्दरगाह के निकटवर्ती राज्यों में स्थित उद्योगों की तुलना में उत्तराखण्ड के निर्यातोन्मुखी उद्योगों का प्रतिस्पर्धा में टिक पाना मुश्किल हो गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि राज्य में निर्यात को बढ़ावा देने हेतु उद्योगों को बन्दरगाह राज्य से माल की ढुलाई के खर्च की भरपाई हेतु बजट में परिवहन सब्सिडी का प्रावधान किया जाना चाहिए।

9. राज्य के उद्योगों को पूर्व की भाँति रियायती दरों पर डीजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराए जाने के सम्बन्ध में।

मान्यवर, आपको अवगत कराना है कि पहले उद्योगों को कम कीमत पर डीजल उपलब्ध होता था अर्थात् पूर्व में उद्योगों के लिए डीजल की उपलब्धता मार्केट रेट से 12 से 14 प्रतिशत कम पर थी। वहीं अब उद्योगों के लिए डीजल की दरें मार्केट रेट से 8 से 9 प्रतिशत अधिक कर दी गयी हैं। इस प्रकार उद्योगों के लिए डीजल की कीमत बाजार भाव से प्रभावी रूप से 21 प्रतिशत अधिक हो गयी हैं। वहीं दूसरी ओर यूपीसीएल द्वारा उद्योगों की विद्युतापूर्ति में भी निरन्तर कमी की जा रही है जिससे उद्योगों को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि अब उत्तराखण्ड में उद्योगों का सुचारू रूप से चल पाना तथा अन्य राज्यों की तुलना में प्रतिस्पर्धा में बने रहना मुश्किल हो गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि राज्य के औद्योगिक विकास को ध्यान में रखते हुए उद्योगों को पूर्व की भाँति रियायती दरों पर डीजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराए जाने हेतु बजट में प्रावधान किया जाना चाहिए।

10. कन्ज्यूमेबल्स पर इनपुट टैक्स क्रेडिट दिए जाने के सम्बन्ध में।

मान्यवर, आपको अवगत कराना है कि कम्पनियाँ कन्ज्यूमेबिल्स पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ ले रही हैं जिसके लिए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उन्हें विधिवत् रूप से अनुमति भी दी जा रही है। इसके विपरीत बाद में विभागीय अधिकारी जब ऑडिट कर रहे हैं तो वे इनपुट टैक्स क्रेडिट को ब्याज और पेनल्टी सहित वापस माँग ले रहे हैं। यह न्यायोचित नहीं है। जब एक कर निर्धारण अधिकारी ने कन्ज्यूमेबल्स पर इनपुट टैक्स क्रेडिट स्वीकृत कर दिया तो ऑडिट करने वाले ब्याज और पेनल्टी सहित इनपुट टैक्स क्रेडिट वापस करने की माँग नहीं कर सकते।

अतः आपसे अनुरोध है कि कन्ज्यूमेबल्स पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा स्वीकृत किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ कम्पनियों/व्यापारियों को मिलना चाहिए। ऑडिट वालों के द्वारा उसे वापस करने की माँग नहीं की जानी चाहिए।

11. राज्य सरकार द्वारा उद्योगों को सीजीएसटी का 42 प्रतिशत अंश अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में।

मान्यवर, आपको अवगत कराना है कि देश में जीएसटी प्रणाली लागू होने के बाद राज्य के उद्योगों को मिलने वाला सेन्ट्रल एक्साइज का लाभ मिलना बन्द हो गया है। इसके अन्तर्गत केन्द्र द्वारा उद्योगों को 58 प्रतिशत अंश की प्रतिपूर्ति की जा रही है परन्तु 42 प्रतिशत अंश उद्योगों को स्वयं वहन करना पड़ रहा है जिससे राज्य के उद्योगों को आर्थिक हानि उठानी पड़ रही है। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि उद्योगों को सीजीएसटी का शेष 42 प्रतिशत अंश राज्य सरकार द्वारा उद्योगों को वापस किया जाना चाहिए।

इस सम्बन्ध में हमारा सुझाव है कि यदि राज्य सरकार किसी कारणवश यह अंश उद्योगों को वापस करने में असमर्थ है तो ऐसी अवस्था में सीजीएसटी के 42 प्रतिशत अंश की प्रतिपूर्ति केन्द्र सरकार से कराये जाने हेतु शासन स्तर से कार्यवाही की जानी चाहिए।

आदर एवं आभार सहित

वास्ते **कुमायूँ गढ़वाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री**

Vikas Jindal

(विकास जिन्दल)

अध्यक्ष

उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फैडरेशन लि0

मुकेश सिंह बोरा
प्रशासक

आँचल

मोटल चौराहा, हल्द्वानी (नैनीताल)
263139 (उत्तराखण्ड)

9412129407
6398518998

mukeshbora197676@gmail.com

पत्रांक: memo/2022 दिनांक: 14-5-2022

सेवा में,

मा0 मुख्य मंत्री जी,
उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून।

महोदय,

अवगत कराना है कि दुग्ध उत्पादकों, दुग्ध संघों एवं फैडरेशन के साथ–साथ संघ व फैडरेशन के अध्यक्षों के हितों के लिए निम्नानुसार कल्याणकारी योजनायें कियान्वित कराने हेतु शासकीय कार्यों को कराया जाना उचित होगा–

1. प्रदेश के दुग्ध उत्पादकों को सरकार द्वारा वर्तमान में रू0 4.00 प्रति लीटर की दर से दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन राशि प्रदान किया जा रहा है, जो दुग्ध उत्पादकों के हित में सराहनीय है। किन्तु, मा0 मुख्य मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार की घोषणानुसार, उक्त प्रोत्साहन राशि को रू0 5.00 प्रति लीटर करने हेतु शासकीय आदेश निर्गत किया जाय तथा इसे प्रभावी करवाया जाय।
2. दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन राशि सरकार द्वारा समय से प्राप्त नहीं हो पा रहा है तथा माह मई, 2021 से वर्तमान तक प्रोत्साहन राशि बैकलॉग में चल रहा है, जिसके लिए शासकीय आदेश प्रतीक्षित है। अतः अनुरोध है कि दुग्ध उत्पादकों के हितों को ध्यान में रखते हुए, **बैकलॉग की धनराशि सहित माह मई, 2021 से मई, 2022 तक की प्रोत्साहन राशि का एकमुश्त भुगतान करने हेतु शासकीय आदेश निर्गत किया जाय** तथा इस प्रकार की व्यवस्था करवाई जाय कि **कम–से–कम त्रैमासिक रूप से दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध मूल्य प्रोत्साहन राशि का भुगतान दुग्ध उत्पादकों को किया जा सके।**
3. मा0 मुख्य मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार की घोषणानुसार, पर्वतीय क्षेत्रों की दुग्ध समितियों के सचिवों को रू0 0.50 के स्थान पर रू0 1.00 प्रति लीटर की दर से तथा मैदानी क्षेत्र की दुग्ध समितियों के सचिवों को रू0 1.00 प्रति लीटर की दर से सचिव प्रोत्साहन राशि का भुगतान कराने हेतु शासकीय आदेश निर्गत किया जाय।
4. प्रदेश में पशुचारा, खासकर भूसे की अधिक किल्लत है, जिसके कारण भूसे की कीमत अत्यधिक है। इस कम में अनुरोध है कि पर्वतीय क्षेत्रों के दुग्ध उत्पादकों के लिए इसे घस्यारी योजना से जोड़ते हुए, कम–से–कम 75 प्रतिशत अनुदान पर भूसा, पशुआहार एवं साईलेज़ दुग्ध उत्पादकों को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित कराने की व्यवस्था कराई जाय, इससे पर्वतीय क्षेत्रों के दुग्ध उत्पादकों को दुग्ध व्यवसाय से जोड़ने में सहायता मिलेगी तथा इससे पर्वतीय क्षेत्रों से पलायन को भी रोका जा सकता है। उक्त योजना को लागू कराने में शासन पर अधिक व्यय भी वहन नहीं करना पड़ेगा तथा पर्वतीय क्षेत्रों के दुग्ध उत्पादकों को इससे बहुत राहत मिलेगा।

निवास: ग्राम व पोस्ट- [illegible] भीमताल जिला- नैनीताल।

उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फैडरेशन लि0

मुकेश सिंह बोरा
प्रशासक

आँचल

मंगल पड़ाव, हल्द्वानी (नैनीताल)
263139 (उत्तराखण्ड)

9412129407
9998513998

mukeshbora197676@gmail.com

पत्रांक:.................................... दिनांक:....................................

5. प्रदेश के अन्य जनप्रतिनिधियों; यथा–जिला पंचायत अध्यक्ष, बी0डी0सी0 मेम्बर्स, ग्राम प्रधान आदि; की भाँति प्रदेश के दुग्ध संघों एवं उत्तराखण्ड सहकारी डेरी फैडेरेशन के अध्यक्षों को भी नियत मानदेय दिलवाने की व्यवस्था करवाई जाय।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त बिन्दुओं पर जनहित/दुग्ध उत्पादकों के हितों में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा की जाय।

(मुकेश बोरा)
अध्यक्ष/प्रशासक

पत्रांक: /तद्दिनांक।

<u>प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–</u>

1. सचिव, डेरी विकास, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. मा0 कैबिनेट मंत्री जी, पशुपालन, दुग्ध विकास, मत्स्य, गन्ना विकास, प्रोटोकॉल, कौशल विकास एवं सेवायोजन, उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून।
3. मा0 कैबिनेट मंत्री जी, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड सरकार, देहरादून।

(मुकेश बोरा)
अध्यक्ष/प्रशासक

[illegible] सिंह [illegible], [illegible], [illegible], [illegible]
7857228629

1. खरीफ धान को कम करने के लिए मक्का की MSP राज्य द्वारा निर्धारित की जाए एवं क्षेत्र को बढ़ाने के लिए मक्का की खेती पर अनुदान दिया/ तथा सरकारी खरीद की जाए।

2. क्षेत्र में बासमती का उत्पादन बढ़ाने के लिए बासमती की MSP एवं मार्केटिंग की व्यवस्था की जाए।

3. उधम सिंह नगर जनपद में भूमि जल का स्तर लगातार गिर रहा है जिसके लिए इसे नियन्त्रित किया जाना चाहिए।

4. गाँवों में उपलब्ध तालाबों के जीर्णोद्धार की योजना लायी जाए तथा इसमें मछली पालन शुरू कराया जाए जिससे भूमि जल स्तर में सुधार होगा तथा स्थानीय नागरिकों को रोजगार भी मिलेगा। नये तालाब निर्माण पर भी अनुदान दिया जाए।

5. सोलर पम्प लगाने पर राज्य से 30% की जगह 40% प्रतिशत अनुदान दिया जाए जिससे किसानों की बिजली एवं डीजल पर निर्भरता घटे।

6. किसानों द्वारा क्रय कृषि यन्त्रों पर पॉलीहाउस की भाँति अनुदान 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 80 प्रतिशत की जाए जिससे अधिक से अधिक लघु एवं सीमान्त

Gmail Uttarakhand Budget <uttarakhandbudget@gmail.com>

Regarding agriculture Loan exemption/waiver
1 message

dharmandra singh <dsinghesa7@gmail.com> Thu, Apr 28, 2022 at 8:39 AM
To: "uttarakhandbudget@gmail.com" <uttarakhandbudget@gmail.com>

Honourable CM sir,

I am very delighted to see the announcement of first budget of re-elected BJP gov under our visionary honourable CM Dhami Ji.
I know honourable CM is very keen to sort out the problem of small farmer, who are always in the pain of loan debt for their livelihood.

I belong to Kisan family and I have two siblings and my father have 1.5 acre agriculture land .I saw his face in pain always for our basic need and our early education.He is still in agriculture loan debt .

I here want to say that pls do needful for agriculture loan waiver/exemption for small farmer.

CM sir I belong to your constituency Khatima .I hope for your kind consideration for this matter.

Rgds
Dharmedra singh S/O Mangla Singh Maurya
Village-Khudaganj/Bhagchuri
Khatima.

Gmail

Uttarakhand Budget <uttarakhandbudget@gmail.com>

Budget 2022-2023

1 message

Dinesh Negi <dineshnegi852@gmail.com> Thu, Apr 28, 2022 at 8:52 AM
To: "uttarakhandbudget@gmail.com" <uttarakhandbudget@gmail.com>

Hello

If you are really concerned about the development of locals ,work on the issues like domicile and land law ..

Rest is vendetta

Regards
Dinesh negi

Gmail

Uttarakhand Budget <uttarakhandbudget@gmail.com>

ड्रीम बजट ऑफ उत्तराखंड

1 message

Green Economics <nexigen@ires.org.in>
To: "uttarakhandbudget@gmail.com" <uttarakhandbudget@gmail.com>

Thu, Apr 28, 2022 at 9:10 AM

मान्यवर
आपका यह कार्य सराहनीय है जैसा कि मैंने पिछले तीन-चार वर्षों में देखा हमारी प्राइमरी स्कूलों के लिए बजट नहीं है मेरा आपसे अनुरोध है की प्राइमरी स्कूलों के रखरखाव के लिए उनकी छतों पर सोलर पावर प्लांट लगाए जाए और इसके लिए धन माइक्रो इरिगेशन के पास है जिन स्फूर्ति योजना में सोलर वाटर पंप केंद्र सरकार के आए हैं जिसका उत्तराखंड के पहाड़ों पर उपयोग नगण्य है अगर इस फंड को हम अपने स्कूलों की छतों पर लगाते हैं हमारे बच्चे बिजली में पढ़ेंगे और स्कूल की कुछ अतिरिक्त आय भी होगी जिससे स्कूल के रखरखाव में कार्य होगा मान्यवर से मेरा एक अनुरोध यह भी है कि हम अपनी लायबिलिटी या कम करें और ऐसैट्स को बढ़ाएं हमारे बजट में ज्यादातर लायबिलिटी असेट्स कम होते जा रहे हैं हम ₹100 में ₹ ₹88 खाली समाज को खुश करने में खर्च कर दे रहे हैं हम विकास कैसे करेंगे हम भिखारी होते जा रहे हैं अगर हमें पहाड़ पर खुशहाली और रोजगार पैदा करने हैं तो हमें स्थाई कॉल सेंटर खोलिए प्रत्येक जनपद में हमारे बच्चे हिंदी अच्छी बोल लेते हैं केंद्र सरकार से हम अपने कॉल सेंटर्स के लिए काम मांग सकते हैं सारे कॉल सेंटर अभी बेंगलुरु से चल रहे हैं

मान्यवर हमारे प्रदेश का युवा अच्छा शिक्षित है और अपने जनपदों में कार्य भी करना चाहता है अगर आप बिजली और ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क दे दे उत्तराखंड को खाली कॉल सेंटर के बल पर हम विश्व से डॉलर भी कमा सकते हैं और आपसे अनुरोध है आपने सही सलाहकार रखिए इस उत्तराखंड को बर्बाद करने वाले सलाहकार ही हैं मैं वालंटियर अपनी सेवाएं दे सकता हूं इसके बदले में ना मुझे टेंडर चाहिए और ना ही कोई पद आपके प्रदेश का एक समर्पित नागरिक
जय हिंद वंदे मातरम
चंद्रभूषण तिवारी

Gmail

Uttarakhand Budget <uttarakhandbudget@gmail.com>

बजट सुझाव

1 message

Harphool Singh <hsinghdhundhara@gmail.com>
To: "uttarakhandbudget@gmail.com" <uttarakhandbudget@gmail.com>

Thu, Apr 28, 2022 at 10:21 AM

उत्पादन प्रोत्साहन होना राज्य हित में होगा| सभ्य जनों के निवेश को आमंत्रित किया जाये |
गाँव और स्थानीय गरीबों को स्थाई रोजगार मुहैया करवाने वाली उत्पादन ईकाईयों को प्रोत्साहित किया जाये|
पशुपालन व जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाए|

Gmail

Uttarakhand Budget <uttarakhandbudget@gmail.com>

Request from Youth

1 message

24 A K <apoorv.aisec@gmail.com> Thu, Apr 28, 2022 at 12:20 PM
Bcc: uttarakhandbudget@gmail.com

Dear Sir,

Greetings of the day!!!

- Single exam for all competitive exams for Private and Government Organizations with Exam fee of less than Rs.500.
- Any religious Temple/Mosque should have a school/college or Hospital in Built to get valid permission.
- Focus more on Youth & Job by deploying all youth force directly to job even if its temporary because their energy needs some direction & opportunities.
- Follow Delhi model of education
- Focus only on development rather than any other religious politics.
- Basic Nursing & self defence should be a part of basic education.
- Any ralis and loudspeaker should be minimalist.
- Changing names should be banned as it leads to loss of crores of stationary
- Every decision should be made according to **Education & Development.**
- Also work for the General category, we don't have enough money to fill every exam form, even though the opportunities are so few.

Thanks & Regards,

Apoorv Kimtee
+91 8770045484
+91 89827 63396
Apoorv.aisec@gmail.com

Gmail

Uttarakhand Budget <uttarakhandbudget@gmail.com>

Health

1 message

sonu maa <sonumaa1111@gmail.com> Thu, Apr 28, 2022 at 12:55 PM
To: "uttarakhandbudget@gmail.com" <uttarakhandbudget@gmail.com>

Please specify nursing and pharmacy vacancy budget
Contractual policy ko khatam karo
NHM ka or contractual ka cadre banao
Old pension lagu karo

Gmail

Uttarakhand Budget <uttarakhandbudget@gmail.com>

Suggestions regarding budget

1 message

ritesh gosain <ritesh9493@gmail.com> Thu, Apr 28, 2022 at 1:32 PM
To: "uttarakhandbudget@gmail.com" <uttarakhandbudget@gmail.com>

Respected sir I want to say that please giver rebate and announce some relaxation to those who are earlier used to live in uttrakhand but due to some issues they left the state for work or education but now they want to start business in their hometown so give some rebate
Thanks
Ritesh gusain
Pauri Garhwal
Uttrakhand

Gmail   Uttarakhand Budget <uttarakhandbudget@gmail.com>

Suggestion on Budget of 2022-23

1 message

Nandan Dhauni <nasa1537@gmail.com>   Thu, Apr 28, 2022 at 2:13 PM
To: uttarakhandbudget@gmail.com

Dear Sir/ Madam,
with due respect, I would like to thank Govt of Uttarakhand for giving opportunity to its citizens for asking suggestion on budget for F.Y. 2022-23. I am attaching herewith my suggestions which may be useful for Govt in preparing budget for FY 2022-23.

Thanks & Regards

Yours Faithfully

Nandan Singh Dhauni
Kathgodam, Nainital
Mob 8005445261

---

budget suggestions .pdf
1863K

Uttarakhand Budget for F.Y. 2022-23

We, the people of land of Gods and Goddess are blessed with a magnificent landscapes which are providing us a safe heavenly abode. The utmost motto and aim of our state government should always be betterment and upliftment of the people of this land. I am very much concerned about the fact that in spite of enrichment in resources we, are lacking in development.

With due respect , I would like to submit the following suggestion for annual budget of Govt of Uttarakhnad for F.Y. 2022-23.

Budget Suggestion:-

(a) **Revenue Receipt**

Revenue receipt is mother of development. Our state is lacking in revenue generation. Our annual expenditure is about 60,000 crores whereas we are able to generate only 15,000 Cr. of revenue i.e. only 26% of revenue in respect of annual expenditure and rest of expenditure in met out of Central Govt Funds. We are expending more on expenditure of revenue nature and less on Capital outlay. Unless we do not make capital investment/expenditure in good proportion , how can we expect good revenue generation in coming years.

(b) **Horticulture** -We need dedicated planned capital outlay for exploring Horticultural programmes. MOU can be made with domestic and foreign investors. We have GB Pant Agriculture University at Pantnagar. We should utilise it for making necessary research and developing fruit breeds which may suitably grown in Uttarakhand. A vast awareness programme for promoting Horticulture and extending helping hands to the people to start horticultural activities in hills villages are required to be done by State Ministry of Agriculture.

(c) **Water resources management in Hills- A** dedicated planned capital outlay for water resources management particularly in hill districts is needed. Each village in entire Uttarakhand region must have water abundance . Our state is still in dismay condition despite of facts that all the majors rivers of this nation are originating from here. Fulfilment requirement of irrigation in hill villages will automatically forbid migration and will generate opportunity for self employment. Presently, villagers are not able to grow even vegetables due to shortage of water and most of the land in villages in hill area is lying barren since rainy season pattern has changed and there is scarcity of drinking and irrigation water.

(d) **Revenue Expenditure Vs Capital Expenditure**- Government should minimise revenue expenditure and optimise Capital expenditure. Only capital expenditure will give fruitful results in coming years. As per the annual budget of F.Y. 2021-22 , we have revenue expenditure of Rs. 44,000 crores whereas capital expenditure is only 14,000 Crore. We do

Gmail Uttarakhand Budget <uttarakhandbudget@gmail.com>

उत्तराखंड बजट में से अपने क्षेत्र के पिछड़ा पन होने से कुछ राशि क्षेत्र के विकइके लिए स्वीकृत करके पलायन को रोकने के लिए अनुरोध ।

1 message

sushil maithani <sushilmaithani261@gmail.com> Thu, Apr 28, 2022 at 2:20 PM
To: "uttarakhandbudget@gmail.com" <uttarakhandbudget@gmail.com>, "dmpaurigarhwal@gmail.com" <dmpaurigarhwal@gmail.com>, sdmkotdwar@gmail.com, vidhansabhaadhyakshuttarakhand@gmail.com

सेवा में,
श्रीमान विधानसभा अध्यक्षा महोदया,
उत्तराखंड सरकार
मैडम सादर प्रणाम,
महोदय मैं आपके पूर्व विधान सभा क्षेत्र 36 यमकेश्वर विधान सभा का नागरिक हूं, और आपके माध्यम से मैं सरकार को ये सूचित करना चाहता हूं कि आपके द्वारा किए गए कार्य विधानसभा के लिए बहुत अच्छे थे, किंतु आप एक साथ बहुत सारे कार्य तो कर नहीं सकते थे, कुछ कार्य छूट गए हैं जिनको की अब पूरा किया जा सकता है,
जिससे की मेरा क्षेत्र पोखाल मंडल के अन्तर्गत मालिनी घाटी में ग्राम सभा बिजनूर, सोड़, मंज्याडी, लथोखी, सौंटीयाल धार, किमसेरा, पूरा क्षेत्र विकास में पिछड़े हुए हैं।
ओर इतने पिछड़े हुए हैं की हर साल यहां से पलायन होता ही जा रहा है जो की बड़ी दुख की बात है,
जब भी अपने क्षेत्र से पलायन देखता हूं तो बहुत रोना आता है की क्या इसीलिए हमने अपना उत्तराखंड राज्य की अलग मांग की,
क्या राजा भरत की जन्मस्थली सुख सुविधा के अभाव से एक दिन पलायन के भेंट चढ़ जाएगा।
जहां महर्षि कण्व का आश्रम हुआ करता था क्या वो धरती एक दिन पलायन से समाप्त हो जायेगी।

1- सन् 1990 की दशक की बनी हुई सड़क अभी भी नदी में ही है गाड़ी नदी के रास्ते होकर की गांवों तक जाती हैं, और आजतक सड़क पक्की तक नही हो पाई।
2- नेटवर्क सुविधा कुछ भी नहीं है फोन आज भी खूंटियों पर टंगे हुए हैं। कभी कभी तो पूरे पूरे हफ्ते तक नेटवर्क नही आते।
3- स्वास्थ्य सुविधा तो बिल्कुल भी नही है नाम के लिए एक CHC पोखाल है उसमे भी डॉक्टर है न मशीन।
4- शिक्षा के नाम पर एक इंटर कॉलेज है जहां पर शिक्षकों की अपनी मर्जी है आए तो ठीक है न भी आए तो कोन पूछ रहा, क्योंकि अधिकारी लोग कभी छापा मारते ही नही।
5- बेरोजगारी लगभग 95% है क्षेत्र के युवा या तो बेरोजगार हैं या फिर रोजगार के लिए पलायन कर चुके हैं।
महोदय मुझको आशा है की इस बजट में आप मेरे क्षेत्र मालनी क्षेत्र का ध्यान अवश्य रखोगे जिससे की यहां से पलायन रुक जाएगा।

धन्यवाद
सुशील मैठाणी
ग्राम सभा - बिजनूर
पोस्ट ऑफिस - मोंडई
वाया - कांडाखाल
विकास खंड - दुगड्डा
तहसील - कोटद्वार
जिला जेड पौड़ी गढ़वाल
उत्तराखंड 246144
फोन नंबर - 8429021165,
7983552314

Gmail

Uttarakhand Budget <uttarakhandbudget@gmail.com>

आपका बजट आपका सुझाव

1 message

Sandeep Narayan <narayandoon@gmail.com>
To: uttarakhandbudget@gmail.com

Thu, Apr 28, 2022 at 5:36 PM

Dear Sir,
wrt the subject:

suggestion :-- जिन अधिकारीयों के पास एक से ज्यादा विभाग हैं उन्हें केवल एक ही गाड़ी आवंटित होनी चाहिए जिससे की गाड़ियों के रख - रखाव के खर्च में कमी आएगी साथ ही साथ अतिरिक्त चालकों का खर्च भी बचेगा।

with regards,

Sandeep Narayan

Gmail

Uttarakhand Budget <uttarakhandbudget@gmail.com>

Suggestion for Budget

1 message

PRABHAKAR KATHAYAT <prabhakarkathayat17@gmail.com> Thu, Apr 28, 2022 at 6:37 PM

To: uttarakhandbudget@gmail.com

Budget for farming and assistance in forest, so that people utilise the land along with forest department.

Regards

Gmail Uttarakhand Budget <uttarakhandbudget@gmail.com>

(no subject)
1 message

Suman Bhainsora <sumanbhainsora6@gmail.com>
To: uttarakhandbudget@gmail.com
Thu, Apr 28, 2022 at 7:08 PM

Respected team,

The step of involving public participation is heartily welcome step in direction of good governance and fulfillment of democratic principles.

Suggestions are as follows-

1. In direction of infrastructure especially roads .

Proper infrastructure and good connectivity will help state to boost last mile connectivity along with boost to investment in state.
Most of the roads in state (including state and national highways) either are filed with potholes and damaged or requires repairing badly.

This not only increases no of RTA(Road traffic accidents) but also effects tourism sector of state.

Thus budget allocation towards roads would ensure better connectivity of state.

2. In direction of occupational health safeguard.

In our state we still see mannual scavenging despite even many guidelines steps have not been taken in this direction.
Many people of particular section still are forced for sewer cleaning without proper equipment and gears.

Thus proper finance in direction of welfare of such people should be our priority untill we are far away from replacing this menial task with automation.

3. Towards Girls education especially in secondary School.

Many girls in our state still faces boundation to education because of menstruation process especially in rural areas. Thus like 'BAHINI SCHEME' of Sikkim govt,our state government in collaboration with private agencies could also aim to provide 100 percent access to free and safe sanitary pads to secondary and senior secondary School going girls. As in rural areas vending machine providing sanitary napkin at some cost via vending machine had failed , because of lack of awareness regarding menstrual hygiene also high poverty rate.

Hope government could incorporate above suggestions for welfare of public and improving standard of living of it's subject.

Thank you.

With regards
Dr. Suman bhainsora

Gmail

Uttarakhand Budget <uttarakhandbudget@gmail.com>

(no subject)

1 message

Shubham Semwal <shubhamvnsemwal@gmail.com> — Thu, Apr 28, 2022 at 8:57 PM

To: "uttarakhandbudget@gmail.com" <uttarakhandbudget@gmail.com>

We want a UPSC coaching centre in Srinagar.
OR
A free UPSC coaching in Dehradun for all Categories.

Gmail

Uttarakhand Budget <uttarakhandbudget@gmail.com>

सुझाव

1 message

Harphool Singh <hsinghdhundhara@gmail.com> Thu, Apr 28, 2022 at 10:07 PM
To: uttarakhandbudget@gmail.com

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग नीति में रायपुर ब्लॉक के पर्वतीय क्षेत्रों में सब्सिडी के विस्तार पर अवश्य विस्तार दिया जाए पूरा क्षेत्र आबाद हो जाएगा

Gmail

Uttarakhand Budget <uttarakhandbudget@gmail.com>

My suggestions.

1 message

BALBIR SINGH <dharmwanbalbir60@gmail.com> Fri, Apr 29, 2022 at 6:40 AM
To: uttarakhandbudget@gmail.com
Cc: cm-ua@nic.in, dm-rud@nic.in, dmrudraprayag@gmail.com

Dear Sir,

As desired by you, I am attaching letter drafted after my recent visit to my village - Ukhimath.

I have suggested only two points for better future of hill people.

If you will follow these points then unemployment and migration will stop from hills and the souls of those who lost their lives for creation of this Uttarakhand will rest in peace.

Thanks.

Balbir Singh

98187 87411, 79828 73900

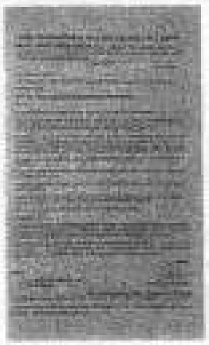

IMG_20220428_080915~2.jpg
1253K

BALBIR SINGH DHARMWAN , M.Sc(GEOLOGY), MIGS (LM) , CHINHIT RAJAY PRAPTI ANDOLANKARI, VILLAGE – MANGOLI ,ONKARESHWAR WARD NO.-3 , UKHIMATH , DISTRICT -RUDRAPARAYAG , UTTARAKHAND , PIN CODE -246 469, TEL : 98187 87411 , 73828 73300, E-mail. : dharmwanbalbir60@gmail.com

To   Speed Post   Dated : 22.04.2022

Mr. Pushkar Singh Dhami

Chief Minister of Uttarakhand, 4 Subhash Road, Uttarakhand Secretariate (Temporary), New Building 4th Floor,

Dehradun – 248 001

Subject : My recent visit , observations and suggestions to Government of Uttarakhand .

Dear Sir,

During my recent visit I was at village for ten days . I visited many places and observed / find following:

1.Most of the government employee are leaving their work place on Friday and coming back by Monday evening or on Tuesday , if somebody ask about their whereabout then ou staff say he /she went for meeting further / public enquire tried some of them are taking leave for whole week or remain absent and people are facing problem.

2.Chardham Yatra will start from next Month , I show there are many pits and other problems on roads , Work of All Weather Road is in progress which has faulty design specially they are constructing "Covered Drains" at both side of road width at some places the drains are not at the end of the acquired land where land is left out upto 10 feets , I show in these drains not a single drop of water is going all water from hill is coming on roads , during rains roads looks like a nalla / drain ?

3.Chardham Yatra is about to start but there is no mobile network even on highway roads up to 10 Kms. which is very serious issue. ?

4.There is no particular place for bus and taxi stop, drivers are stopping vehicles after every 5 - 10 m. due this problem 1.0 Km distance is crossed in 1 Hr.

5. People done encroachment on roads by putting their articles , constructed building structure so that people are facing problem in travelling.

6. Before year 2000 at Ukhimath Tehsil HQ Government hospital surgery and plastering etc. use to be there , but now for these people are going Srinagar or Dehradun and Ukhimath hospital become referral hospital only.

7.There is no proper electric supply , people don't know when the light will come and go ?

My suggestion's to you:

1. Shift the state capital to "Gairsain (Permanent Capital)" where from over 7 years Vidhansabha Bhawan and residence for all are ready, then why shifting of capital is pending from Temporary Capital to Permanent Capital by delaying this you are fooling the people of Hills and cheating to souls of those who lost their lives for creation of Uttarakhand.

2.Don't allow the air travel of any MLA's , Minister / Neta's & Government employ . Everybody must travel by roads in hills doing this they will get acquainted with problems in hills for which Uttrakhand was demanded, otherwise for general people Uttar Pradesh was much better than now, at least there were much more job opportunities etc.

Your's Faithfully,

[signature] 22/04/2022

Copy to

1. Mr. Satpal Maharaj,Tourism Minster.
2. DM Rudraprayag

(BALBIR SINGH DHARMWAN)

M.Sc (Geology) ,Ex. Research Fellow : i) Garhwal University ,Srinagar & ii) School of Environment al Sciences , JNU , New Delhi,Ex. Consultant of : Ministry of Environment and Forest (MoEF) For : i) Team Leader for Monitoring Tree Plantation of Dist. Badaun , U.P. , & [illegible] ii) EIA/EMP Domain Consultant for Soil & Geology. & Chinhit Rajya Prapti Andolnkari.

Gmail Uttarakhand Budget <uttarakhandbudget@gmail.com>

Budget for roads and highways
1 message

MAHENDER KANDPAL <mkkandpal@yahoo.co.uk> Fri, Apr 29, 2022 at 7:53 AM
Reply-To: MAHENDER KANDPAL <mkkandpal@yahoo.co.uk>
To: "uttarakhandbudget@gmail.com" <uttarakhandbudget@gmail.com>

Sir,

Infrastructure such as good quality roads and highways is backbone of development of state. Needless to say that till date NH 121 from Ramnagar and onwards has not been widened. It is requested to make sufficient budgetery provision for constructing roads to connect all villages and widening of highway such as NH 121.

Besides above, sufficient budget be provided on time for following:-

1. Widening of NH 121 from single lane to double lane;

2. Connecting road from Goreecheera (situated on NH 121) to villages namely Nansyon, Pajera and Tandola, Pauri Garhwa, Uttarakhand under jurisdiction of PWD, Baijro; and

3. Lake at Syonsi and Satpuli, Pauri Garhwal, Uttarakhand.

For development of state, making budget provision and providing funds on time must be on priority to make Uttarakhand No.1 state by 2025.

Hope, above requests would be considered for development of Uttarakhand.

Jai Hind.

Gmail

Uttarakhand Budget <uttarakhandbudget@gmail.com>

---

budget

1 message

अंकित कुमार प्रजापति <samuhakp@gmail.com>
To: uttarakhandbudget@gmail.com

Fri, Apr 29, 2022 at 12:20 PM

स्नातक पास बेरोजगार को पेन्सन मिलनी चाहिए

Gmail

Uttarakhand Budget <uttarakhandbudget@gmail.com>

Budget suggestions

1 message

Arjun Sharma <arjun.n.k.sharma@gmail.com> Fri, Apr 29, 2022 at 3:05 PM

To: "uttarakhandbudget@gmail.com" <uttarakhandbudget@gmail.com>

Cc: cm-ua@nic.in

Dear sir, horticulture,olericulture sustainable development projects,planning and implementation. Eg how we can bring,develop and provide high quality genetic material to our walnut,apple,and other temperate fruit growers and work on mission mode to plant,nurture min one lakh such high breed fruit plants in uk in first year of bjp @2.0 and in five years show fruits of our labour on faces of interested young farmers of our state .and give great credibility to social political and economic development agenda of our bjp governance .best regards n.k Sharma agri advisor . Mobile 900 4493660 .vill pandegaon po kolabagh nainital 263159

Gmail

Uttarakhand Budget <uttarakhandbudget@gmail.com>

उत्तराखंड बजट-सुझाव

1 message

Ambadutt Pant <pantambadutt@gmail.com> Fri, Apr 29, 2022 at 4:47 PM
To: uttarakhandbudget@gmail.com

उपरोक्त के संदर्भ में निम्न सुझाव प्रस्तुत है।
गर्मी अथवा अन्य सीजनों में मसूरी,नैनीताल व अन्य पर्वतीय पर्यटन स्थलों में पर्यटकों के कारण गाड़ियों की संख्या इतनी अधिक हो जाती है की उनका संचालन करना कठिन ही नहीं अपितु असंभव हो जाता है। इस सम्बन्ध में निम्न सुझावों पर ध्यान केन्द्रित करना चाहता हूं।
1.मसूरी के लिए-
देहरादून में बहुमंजलीय पार्किंग स्थल बनाया जाए जहां पर पर्यटक अपने वाहन पार्क कर सकें।
2.पर्यटकों की सुविधा हेतु स्थानीय टैक्सी का उपयोग किया जाए।
इन सुझावों को कारगर किए जाने से पर्यटक स्थल को साफ-सुथरा रखा जा सकता है तथा स्थानीय वासियों को रोजगार भी उपलब्ध हो सकेगा।

इसी तर्ज पर नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा के लिए हल्द्वानी में बहुमंजलीय पार्किंग स्थल का निर्माण किया जा सकताहै।
प्रस्तुतकर्ता।

अम्बादत्त पंत

Gmail

Uttarakhand Budget <uttarakhandbudget@gmail.com>

Red FM 93.5 Proposal for BUCHAT RAJKOSHIYA NEDESALAY

1 message

Aahish Kumar Sharma <ashish.sharma@redfm.in> Fri, Apr 29, 2022 at 7:52 PM
To: "uttarakhandbudget@gmail.com" <uttarakhandbudget@gmail.com>
Cc: Rajat Shakti <rajat.shakti@redfm.in>

To,

The

DIRECTOR

UCHAT RAJKOSHIYA NEDESALAY

Dehradun

Red FM 93.5, it is the largest FM station with a PAN India presence of 71 station networks, reaching every nook and corner of the country. It is the only FM channel of the country which enjoys the maximum % of the loyalty listener-ship. The only station to have established an emotional connect with the audience. The emotional connect is nurtured on air by our "Bajaate Raho" attitude. Red FM ensures true national presence through coverage in top 10 markets, top 8 states, 14 state capitals, 17 Hindi speaking markets spread across North and West with considerable footprints in South and East.

RED FM PROPOSAL FOR DAVP Dehradun (Uttarakhand)							
Day	**Time band**	**Sec**	**Days**	**Spot/day**	**Tot sec**	**Rate/10sec**	**Gross cost(INR)**
Mon-Sun	0700-1200	60	30	23	41400	52	2,15,280
Mon-Sun	1200-1700	60	30	23	41400	52	2,15,280
Mon-Sun	1700-2200	60	30	23	41400	52	2,15,280
TOTAL				**69**	**124200**	**52**	**6,45,840**
Dehradun - Dehradun, Mussoorie, Vikashnagar, Selaqui, Rishikesh, Roorkee, Devprayag, Some Part of Garhwal Hills, Ponta Sahib					**TOTAL**		**6,45,840**
					18%		**1,16,251**
					NET AMOUNT		**7,62,091**

DAVP RATE-REDFM-93.5

Station	**Station**	**Time band - Rate**		
		7 am - 11 am	**11 am - 6 pm**	**6 pm - 11 pm**
Delhi	Delhi	863.00	599.00	666.00

Chandigarh	Chandigarh	52.00	52.00	52.00
Lucknow	Lucknow	255.00	203.00	255.00
Varanasi	Varanasi	121.00	80.00	80.00
KANPUR	KANPUR	246.00	337.00	442.00
Jaipur	Jaipur	164.00	137.00	123.00
Bangalore	Bangalore	331.00	254.00	248.00
Hyderabad	Hyderabad	437.00	225.00	250.00
Chennai	Chennai	707.00	315.00	995.00
Kolkata	Kolkata	797.00	759.00	699.00
Pune	Pune	139.00	81.00	99.00
Mumbai	Mumbai	531.00	516.00	757.00
Ahmedabad	Ahmedabad	240.00	216.00	163.00
Dehradun	Uttarakhand	52.00	52.00	52.00
	Total	**4,935.00**	**3,826.00**	**4,881.00**

We offering a Davp rates Rs 52 /10 secs and we are not charging production cost of all the production and Voice over done which is normally advices as per the guidelines of Ministry of Information and Broadcasting and DAVP too. Considering the fact that both the entities govt & RED FM too has a social responsibility towards to the society.

The proposed campaign details are as under for your kind reference and go ahead to proceed further.

Thanks and Regards

Ashish Kumar Sharma

Team RED FM – Dehradun

Contact – 9837021653

Email id-ashish.sharma@redfm.in

Dehradun DAVP Certificate (2).pdf
440K

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING
BUREAU OF OUTREACH AND COMMUNICATION (BOC)
2nd Floor, Soochna Bhawan, Phase 5, C.G.O. Complex, New Delhi-110003

File No. DD(AV)/Misc-11/Pvt FM Empanelment 2019 Dated: 13th September, 2019

To,

South Asia FM Limited,
Murasoli Maran Tower,
73, MRC Nagar Main Road, MRC Nagar,
Chennai – 600028

Subject: Empanelment of Private FM station and offering of rates–reg.

Sir,

This is with reference to BOC's advisory **DD(AV)/Misc-11/Pvt FM Empanelment 2019** dated 17.06.2019 on above mentioned subject. We are pleased to inform you that DG, BOC has approved following rates for 10 seconds spot (Gross in Rs.) as per the terms and conditions mentioned below :-

Radio Station	City/Town	7 AM - 11 AM	11 AM - 6 PM	6 PM - 11 PM
Red FM 93.5	Dehradun	52	52	52

Terms and Conditions:

1. You should convey acceptance to this offer letter within 15 days from the date of this letter.
2. 15% agency commission will be deducted by BOC from the gross rate mentioned above.
3. GST will be paid by BOC at applicable rates.
4. The released spot should be distributed equally by your station in a particular time band unless otherwise specified by BOC.
5. BOC reserves the right to make deduction in the bill, if the spot(s) is/are not aired as specified in the Release Order.
6. BOC reserves the right of mid-term review of rates.
7. Bills (Online as well as Physical) have to be submitted within 30 days of completion of campaign.
8. These rates are kept ready by BOC so that no time is lost in formalities as and when the execution of job is required. Offering of rates is not an assurance of work.
9. The Pvt. FM station must accept the policy guidelines for Pvt. FM stations notified by BOC vide advisory no. 22204/1/2013/EAC/AV Part File/Volume B dated 31.08.2016 and their acceptance of this offer letter will automatically mean that they accept the aforementioned policy guidelines.
10. The empanelment will be valid for a period of 10 years.

Yours Sincerely,

(Anurag Jain)
Deputy Director (AV)

To be filled in by Pvt. FM Radio Stations

We accept above mentioned gross rate, terms & conditions and policy guidelines pertaining to empanelment of Pvt. FM Stations and fixation of rates for Government advertisement issued vide BOC's (erstwhile DAVP) advisory no. 22204/1/2013/EAC/AV Part File/Volume B dated 31.08.2016.

Name of Radio Station/Organisation: Red FM 93.5 - Dehradun | South Asia FM Ltd.
Name of the Authorized Signatory: Rohit Lal
E-Mail ID of Authorized Signatory: Rohit@redfm.in
Mobile No. of Authorized Signatory: 09810800685

Signature of Authorized Signatory with Office Seal

SOUTH ASIA FM LTD. CHENNAI

Gmail Uttarakhand Budget <uttarakhandbudget@gmail.com>

My view on upcoming BUDGET PROVISION

1 message

kuldeep singh <kuldeepsinghitv@gmail.com> Fri, Apr 29, 2022 at 11:27 PM
To: uttarakhandbudget@gmail.com

Respected CM,
Development of Tourism & Organic Farming will be our Core Business in Future & How we can develop & maintain our NEW & EXISTING Tourist - Spots according to WORLD Class standards, We May FOCUS on the followings direction in the upcoming UTTARAKHAND Budget; Like:-

√A) DEVELOPMENT of TOURISM:
1. It is required to be made & strictly followed the GUIDELINES of unnecessary ENCROACHMENT on "Tourist Spots" (Fixed the Limits, 50 Meter - Minimum to 100 Meter - Maximum; surrounding of Tourist Spots ... in view to maintain BEAUTIFICATION

2. Within Tourist Spots, provision should be made for Electric - Rickshaw, Bi-Cycles etc., which will be operated by LOCAL villagers ONLY (Provision for Loaning facilities; if required to LOCAL villagers) ... in view of ENVIRONMENT PROTECTION & EMPLOYMENT

3. Within Tourist Spots, provision of Conveyance facilities to upcoming tourists should be permitted ONLY for LOCAL villagers ... in view of EMPLOYMENT

4. Provision for small tender should be permitted ONLY for LOCAL villagers at Tourist Spots ... in view of EMPLOYMENT

5. PLASTIC'S use should be completely BAN & PUNISHABLE ... in view of ENVIRONMENT PROTECTION

6. PARKING & TOILET facilities should be facilitated by the GOVERNMENT; prior to developing Tourist Spots & Local villagers involvement are required in such activities ... in view of EMPLOYMENT

√B) DEVELOPMENT of FARMING:
1. Supports & Encouraged are required to VILLAGERS for switching - over regarding their Farming CROPS to ORGANIC FARMING Completely & BUDGET PROVISION is required, in respect of ENCOURAGE type of Bonuses to FARMERS

2. Idea of the New FRUIT's Plantation TECHNIQUE should be ADOPT from **Vietnam, Israel** etc. Countries & it's germination is required according to SOIL Testing & BUDGET PROVISION is required

3. Packaging and Transportation facilities should be generated for growing products at sites & BUDGET PROVISION is required

√C) RESOURCES UTILITIES:
1. Utilization of PINE / Chird TREES otherwise, replace these trees in another FRUITS/ Better UTILITY TREES with planned- way & BUDGET PROVISION is made accordingly

2. Provision of Garbage utilizations are required to be extended up to REMOTE & SMALL Locations / Villages as well, in view of ENVIRONMENT PROTECTION

3. PROTECT to EARTH/ UTTARAKHAND from BUILDERS, Which are drastically DAMAGING our EARTH & UTTARAKHAND ENVIRONMENT as well.

4. BUILDERS are UTILIZING our RESOURCES, without LIABILITIES of HUMAN Costing; as seen & thinking "NO LIABILITIES has FRAMED by GOVERNMENT till now in this regards ... ***should be made provision Immediately since long back***

4. PROVISION to PROTECT of small WATER RESOURCES, which has already been damaged / will be damaged due to NEW upcoming Construction ACTIVITIES Like; **National Highways, Industries & others upcoming development PROJECTS** in Future ... it's ESSENTIAL to develop UNDERGROUND WATER - TANK / WATER STORING facility at these LOCATIONS (Approach should be made by STATE & CENTRE GOVERNMENT)

5. Khaali HILL's LAND should be utilized for generation of UNCONVENTIONAL ENERGY SOURCES Immediately Like; installation of SOLAR PANEL, WIND ENERGY Networks m/c etc. ... Generation of EMPLOYMENT

We have lost so much time to form a better State of Uttarakhand. FORTUNATELY, We still HOPE for betterment of my State & Submitted my above views for consideration on upcoming BUDGET PROVISION please

(KULDEEP SINGH)
Village: GULDI - MANIYAR,
Post: Chamba, Distt. Tehri - Garhwal
(UTTARAKHAND)
(M)7895970111

Gmail

Uttarakhand Budget <uttarakhandbudget@gmail.com>

बजट के लिए सुझाव

1 message

SANJAY RAWAT <sanjaysinghrawat@hotmail.com>
To: "uttarakhandbudget@gmail.com" <uttarakhandbudget@gmail.com>

Sat, Apr 30, 2022 at 11:27 AM

श्रीमान,

1. ग्रामीण मोटर मार्गो के लिए अलग से बजट की व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि अलग अलग योजनाओं में ये मार्ग बना तो दिए गए है पर इनकी रख रखाव की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है.

2. पहाड़ी गाँव को 1 महिना 1 JCB दी जाये जिससे वो खाल, खेत और खेल का मैदान बना सके. खाल बरसात का पानी जमा करके सिंचाई के लिए, खेत सीढीनुमा छोटे खेतों को काटकर बड़े खेत बनाने के लिए जिससे खेती करना आसान हो और खेल का मैदान युवावो को खेल को seriously और carrier बनाने के लिए. 1 JCB 5 साल में 60 ग्राम पंचायतों और 10 JCB पूरे जिले में खुशहाली ला सकती है, पलायन रोक सकती है रोजगार और खिलाडी पैदा कर सकती है, किसानों की पैदावार बढ़ा सकती है.

3. पहाड़ी खेती में पैदावार कम है पर अच्छी बात ये है की वो जो उगाते है वो सब स्वाभाविक रूप से आर्गेनिक होता है और उसका मूल्य बाजार में सामान्य से चार गुना अधिक है जरूरत है तो किसानों को जागरूक करने की, उनके आर्गेनिक उत्पाद को एक बाजार देने की बजट में हर जिले में एक मंडी दे जो किसानो के उत्पाद को दिल्ली जैसे बाजार में पंहुचा सके तो किसान चार गुना कमा पायेगा

4. सतपुली में बहुत अच्छा Scope है की PPP मॉडल पर एक Amusement Park बनाया जाए जो दिल्ली NCR से करोडो Tourists को attract करेगी, पर्यटन बढ़ेगा

5. UP के CM से आपकी घनिस्टता देखकर विचार आया की आप उत्तराखण्ड का पानी UP से पाइप लाइन बिछाकर मिनरल वाटर के रूप में दिल्ली NCR में क्यों नहीं बेच रहे ?

इसी तरह के हज़ारों सुझावो के लिए, ...

आपका

Sanjay Rawat

Pauri Garhwal

बजट के सम्बन्ध में सुझाव सम्बन्धित

1. सबसे पहले सड़कों के लिये बजट को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
2. टनकपुर - बागेश्वर रेल लाइन जिसके लिए कई वर्षों से संघर्ष चल रहा है, उसे पूर्व में हुए सर्वे के आधार पर रेलवे लाइन बिछाने के लिए बजट आवंटित किया जाना चाहिए।
3. कृषि विभाग में मानचित्रक रखे गए हैं, जिनका कार्य ज्यादा नहीं होता, क्योंकि इसमें निर्माण कार्य कम किये जाते हैं, अतः इन्हें अन्य विभागों जैसे लोक निर्माण विभाग में प्रतिनियुक्ति कर, उनसे कार्य कराया जा सकता है एवं उनके वेतन का बजट अन्य कार्यों में प्रयोग किया जा सकता है।
4. शिक्षकों को जो टेलीफोन बिल का भत्ता मिलता है, और यदि वह विवाहित और साथ है तो दो पेंशन मिलेगी, ये नियम बंद किया जाना चाहिए।

Gmail Uttarakhand Budget <uttarakhandbudget@gmail.com>

Fwd: Budget 21-22

1 message

Jagmohan Budakoty <jagmohanbudakoty59@gmail.com> Fri, May 6, 2022 at 11:06 AM
To: uttarakhandbudget@gmail.com

---------- Forwarded message ---------
From: **Jagmohan Budakoty** <jagmohanbudakoty59@gmail.com>
Date: Fri, May 6, 2022, 11:00 AM
Subject: Budget 21-22
To: <uttakakhandbudget@gmail.com>

Dear sir,

Development project r t b made with an aim to rich returns. Like :-

A bridge on the river/fly over can b used as lake,hydel project(small) car parking(paid), commercial market,banks etc.
State highway r t b made by-pass and a commercial market,residential and commercial mall.
Lakes r to be surrounded by pakka matteled road, market and garden.
Generation of fund. Market rate rent can b charged from Illegal encroachments
Since and.till vacation.

In case any appeal by anyone against project to stay, whole expenditure incurred till stay on the development project
r y b born by the appealant.

Thanx and regards

Jagmohan prasad Budakoty

Gmail   Uttarakhand Budget <uttarakhandbudget@gmail.com>

Budget points : Suggestions

1 message

laxman.sga@gmail.com <laxman.sga@gmail.com>   Tue, May 10, 2022 at 9:36 AM
To: uttarakhandbudget@gmail.com

Dear Sir/Madam,

We are thankful to you for giving us a chance to participate budget programme for suggestions. Following are our suggestions in different area :

1. Water

a. At present there is a shortage of water in Kumoun area especially at Almora District and its different blocks. Bhikyasen block is one of them . Modi Ji's har ghar Jal & Nal yogjna is remarkable but not enough which resulting no water in the Taps.

We suggest you to kindly ensure proper water to every villager through natural resources or by installing pumping stations. Water is very essentail needs ot every human being and every lives including animals. Creating a better water availability atmosphare many our peoples would be intrested to visit villages frequently.

2. Roads & Bridges

a. Construction of Roads and Bridges are going very slow at village level and wrost condition of highways from Ram Nagar to Massi, Road is in very bad shape and still unrepaired, which creates a bad message to our visitors in the state.
b. Construction of new road from Marchula to Jainal, is still under construction.

We are awaiting for fast construction of Roads and Bridges whereever required so that we can attract visitors in the state.

3. Hospitals

a. There are no hospitals in the block level or either shortage of proper doctor and medical infractures .

We suggest to ensure proper staff of hospital at block level with maximum treatment. No one should move to Delhi/other states for treatment.

4. Education

a. Education level in the state should be upgraded with providing government courses at block level.

5. Stop migration through Industry development

a. We suggest to develop industrial area in the hills to provide jobs to villagers and their children to stop migration from the state

Best Regards,

Laxman Singh

Gmail

Uttarakhand Budget <uttarakhandbudget@gmail.com>

Budget 21-22

1 message

Jagmohan Budakoty <jagmohanbudakoty59@gmail.com>
To: uttarakhandbudget@gmail.com

Fri, May 6, 2022 at 11:17 AM

Dear sir

Development project r t b made with an aim to rich returns. Like:-
A bridge/flyover can b used as lake,hydel project(small),car parking (paid) as well as market.
Lake surrounded by a mettled road,garden and commercial market.
State highway r t b made by-pass and commercial market, mall and residential
Area can b developed parallel to road.

In case any appeal against project to stay all expenses before stay r t b born by appealant.

Regards
Jagmohan prasad Budakoty

Gmail Uttarakhand Budget <uttarakhandbudget@gmail.com>

A suitable provision of Budget for the utilization of the Hot springs for the betterment of the state's economy

1 message

Bagri Sc <prof.bagri@gmail.com>
To: uttarakhandbudget@gmail.com

Sat, Apr 30, 2022 at 1:49 PM

Dear Sir/ Madam

In view of the subject mentioned adobe, it is requested to consider the following suggestions in the state' s upcoming budget

Utilization of Hot water springs of Uttarakhand

Hot water springs also known as 'thermal springs' or 'hot water *kunds*' are generally found in the geophysical belt of the Upper Himalayan regions of Uttarakhand. Out of the total hot springs , some of the hot springs like Gangani, Suryakund and Rishikund(Uttarkashi),Gaurikund(Rudraprayag),Tapovan (Chamoli), Naradkund(Badrinath), Sahastradhara(Dehradun), Nachni, Madkot and Tapovan(Pithoragarh) are most significant. Hot springs are common along the banks of Gori and Kali rivers in Pithoragarh district besides having their presence in Pindar valley in Almora district.

Suggestions: A suitable provision of budget be made to use the water of hot springs for heating Greenhouses' for horticulture production, heating fish ponds in aquaculture or hydronic warming of Government or Private hospitals or Use of recreational bathing in swimming pools during tourist season.

2- To promote health tourism, the state government can make the provision of chemical analysis in order to ascertain the curative value of hot water in healing various ailments and diseases . In Japan , a spring is considered therapeutic only if the spring waters arrive on the surface at a temperature of at least 25 degree Celsius and contain at least a minimum concentration of certain mineral components

2- Hot springs water can also be exported to other countries provided it meets the standard of the amount of minerals a government has prescribed for imported hot springs water. There are so many hot springs water brands available in the market and are exported. Among such brands, *Perrier* and *Eviam* from France,*San Pellegrino* from Italy ,and *Bad Pyrmonter* from Germany are imported from a large number of countries.

Thanking you

Prof. S.C.Bagri

--

S.C Bagri, Ph.D, Former Prof & Dean of Centre for Mountain Tourism and Hospitality Studies, HNB Garhwal University and Former Vice Chancellor of Himgiri Zee University +919412079836

http://www.hzu.edu.in/images/Himgiri.jpg zee logo

Gmail

Uttarakhand Budget <uttarakhandbudget@gmail.com>

(no subject)

1 message

Endor Gaming <riogames2624@gmail.com> Sat, Apr 30, 2022 at 5:51 PM
To: "uttarakhandbudget@gmail.com" <uttarakhandbudget@gmail.com>

Hello sir,
This is Ayush Agarwal, lives in your state, khatima as We should focou on reservation seat in education should be boycotted, so that ever one get right opportunity. We should also focus in Taios...
Sir as I want to discuss some idea with you if give me the opportunity I will not waste your time..
Thanku
Regards
Ayush

Gmail

Uttarakhand Budget <uttarakhandbudget@gmail.com>

वित्तीय वर्ष 2022 - 23 के बजट निर्माण प्रक्रिया में सुझाव लगातार गिरती शिक्षा व्यवस्था के संबंध में,

1 message

Vijay kala <vijaykala99@gmail.com> Sun, May 1, 2022 at 10:33 AM
To: uttarakhandbudget@gmail.com

माननीय महोदय सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आप ने वित्तीय वर्ष 2022- 23 के बजट निर्माण प्रक्रिया में सुझाव देने के लिए आमंत्रित किया ।

माननीय महोदय मेरा सुझाव यह है कि जो हमारे राज्य की शिक्षा प्रणाली है उसमें परिवर्तन करने की बहुत आवश्यकता है आज हमारे सरकारी स्कूलों (प्राथमिक अथवा माध्यमिक स्कूलों) की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है । मान्यवर इस बजट में शिक्षा व्यवस्था पर जोर देना होगा। इसमें कुछ बातें शामिल किया जाए जो निम्न प्रकार से हैं।

मान्यवर विद्यालय को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने की जिम्मेदारी विद्यालय के प्रधानाचार्य की होती है यदि विद्यालय में सभी शिक्षकों को यह आदेश जारी किया गया कि वह समय पर विद्यालय पहुंचे और प्रतिदिन विद्यालय में मौजूद रहे लेकिन देखा यह जाता है कि कुछ विद्यालयों में ना तो शिक्षक रहते हैं और ना ही प्रधानाचार्य । महोदय कुछ स्कूल/ विद्यालय ऐसे हैं जिनमें बच्चों की संख्या लगातार घटती जा रही है। ऐसा भी नहीं है कि सभी स्कूलों/ विद्यालयों की हालत खराब ही हो कुछ विद्यालय है ऐसी भी है जिनमें प्रधानाचार्य और शिक्षकों की सूझ - बूझ से काफी हद तक विद्यालयों की स्थिति ठीक है।

मेरे विचार से इसका दोष सिर्फ और सिर्फ हमारी शिक्षा व्यवस्था और हमारे शिक्षक वर्ग की है। महोदय एक आदेश यह भी जारी किया जाए की जो भी शिक्षक सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं उनको अपने बच्चों को भी सरकारी स्कूलों में ही प्रवेश दिलाना होगा और समय-समय पर गांव व शहरों में जन संपर्क करके लोगों को अपने बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूलों में कराने के लिए प्रेरित करना होगा।

अतः अधिक ना लिखते हुए मैं अपनी शब्दों को यहीं समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय महोदय आप इस विषय में ठोस कदम उठाएं और उत्तराखंड राज्य को 100% शिक्षित/साक्षर राज्य बनाएं।

धन्यवाद

विजय काला
ग्राम व पोस्ट - मांडई
ग्राम सभा- बिजनूर
जिला- पौड़ी गढ़वाल
उत्तराखंड 246144

Gmail

Uttarakhand Budget <uttarakhandbudget@gmail.com>

suggestion for budget formulation

1 message

Anoop_Ascent <anoop_ascent@aol.in>

Sun, May 1, 2022 at 11:01 AM

Reply-To: Anoop_Ascent <anoop_ascent@aol.in>

To: "uttarakhandbudget@gmail.com" <uttarakhandbudget@gmail.com>

Our Uttrakhand have all things from flora to fauna.

For job prospect we have many opportunities from tourism to agriculture.

There are some suggestions for budget formulation:

1) Make some provision migration reverse policy and talent attracting schemes for local who migrate to many cities at previous decades and become residents of that particular cities.

2) Our education system is very different from any other states of India but their is little bit improvement required i,e Teacher which teaches in each village school give him option to reside at 5-10 Km radius of the school and remaining time would devote towards teaching extra co-curricular programs including governments sponsored schemes for improvement and job prosperity at agriculture and other allied activities.

3) State level programs should be introduced to save standing crops destruction by wild animals.

<u>Solution</u> : Appoint youths of group of some villages and guard them one by one to protect the crops by shielding and guarding the border and crop area with that installing solar energy made streetlight/floodlights. This saves cost of power as well as control of youth migration of youths. The wages of
these youth would be shared by each villages but under supervision of Government personnel i,e nearby school teacher.

4) Promote entrepreneurial specially to locals which got settle in urban area.

Regards

Anoop Rana

8447732267

Gmail Uttarakhand Budget <uttarakhandbudget@gmail.com>

आपका बजट, आपका सुझाव

1 message

Dinesh Verma <dinesh.verma63@rediffmail.com> Fri, May 6, 2022 at 4:19 PM
To: uttarakhandbudget@gmail.com

Respected Sir,
Kindly find the attachment.

Regards,

Dinesh Chandra Verma
House No-35, Cross-9
Tapovan Enclave
Raipur Road
Dehradun

Scan_20220506_115808.pdf
5383K

आपका बजट, आपका सुझाव

बजट 2022–23 हेतु निम्न सुझाव सादर विचारार्थ प्रेषितः–

i) प्रदेश की दिशा का निर्धारणः–

सरकार को अपनी दीर्घकालीन नीति के तहत अपना रोडमैप तैयार किया जाना चाहिए, जिसके तहत आगामी 05 वर्षों हेतु सरकार को अपनी प्राथमिकता निर्धारित करनी होगी अर्थात प्रदेश पर्यटन प्रदेश अथवा ऊर्जा प्रदेश अथवा जैविक/प्राकृतिक खेती प्रदेश अथवा औषधि प्रदेश अथवा औद्यानिक प्रदेश में से किसी एक अथवा दो को अपनाकर, प्रदेश को (चयनित..................) प्रदेश घोषित करते हुए आगामी 05 वर्षों में, इन चयनित क्षेत्रों में अधिक धन आवंटन कर प्रदेश की दिशा निर्धारित की जानी चाहिए।

ii) **पलायन रोकने हेतु वित्तीय सहायताः–**

1. जिन जनपदों से सर्वाधिक पलायन (पलायन रिपोर्ट के अनुसार, जनपद पौड़ी एवं अल्मोड़ा) हुआ है, इन जनपदों के लिए रोजगार सृजन, ग्राम निवासियों की आर्थिकी में वृद्धि हेतु राज्य सैक्टर की रोजगार सृजन एवं आर्थिकी में वृद्धि सम्बन्धित संचालित योजनाओं में 10 प्रतिशत विशेष राज्य सहायता/अधिक धन आवंटन।

2. सर्वाधिक पलायन वाले जनपदों हेतु जिला योजना में 10 प्रतिशत अधिक धन आवंटन जिसमें रोजगार सृजन एवं अवस्थापना सुविधा तथा आर्थिकी में वृद्धि जैसी कार्य योजनाओं में खर्च किये जाने की बाध्यता हो।

iii) **स्वैच्छिक चकबन्दी हेतु वित्तीय सहायताः–**

1. ऐसी ग्राम सभायें जो चकबन्दी (स्वैच्छिक चकबन्दी) कराना चाहती हैं, उन्हें विशेष आर्थिक पैकेज।

   अथवा

   स्वैच्छिक चकबन्दी कराने वाली ग्राम सभाओं को "मॉडल ग्राम सभा" के निर्माण हेतु कार्य योजनानुसार अधिक धन आवंटन।

2. स्वैच्छिक चकबन्दी कराने वाली ग्राम सभाओं में राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के संचालन में विशेष प्राथमिकता एवं पूर्व घोषित राज्य सहायता में 10 प्रतिशत अधिक का अंशदान घोषित करने से स्वैच्छिक चकबन्दी को बढ़ावा मिलेगा, जिससे क्षेत्र के निवासी एक मुश्त जमीन पर खेती करने से लाभान्वित होंगे/बंजर हो चुकी कृषि योग्य भूमि पुनः पूर्व स्थिति में आ सकेगी एवं ग्राम वासियों की आजीविका/आय में वृद्धि का सपना पूर्ण होगा।

3. विभिन्न स्रोतों (केन्द्रपोषित/केन्द्रीय योजनाओं, वाह्य सहायतित परियोजना, राज्य सरकार की योजनायें, जिला योजना, राज्य वित्त आयोग, सांसद निधि/विधायक निधि) के माध्यम से धन आवंटन के फलस्वरूप योजना कार्यों में Duplicacy/

अनियमिततायें तथा कार्यों की प्राथमिकताओं के अनुरूप ससमय धन आवंटन न होने/विभिन्न स्रोतों से पृथक–पृथक धन आवंटन के फलस्वरूप कई बार नवसृजित कार्यों को तोड़कर/हटाकर पुनः कार्यों को पूर्ण किया जाता रहा है। फलस्वरूप धन के अपव्यय एवं जनसामान्य में सरकार की छवि खराब होती है।

अतः राजकीय धन के सदुपयोग हेतु धन आवंटन की वर्तमान व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन निम्नानुसार किया जाना आवश्यक होगाः–

1. सामाजिक प्रोत्साहन योजनायें यथा वृद्धा पेन्शन, विकलांग पेन्शन, विधवा पेन्शन, किसान सम्मान राशि आदि योजनाओं को विभागाध्यक्षों के माध्यम से वर्तमान व्यवस्था के तहत संचालन/धन आवंटन किया जाय।

2. अवस्थापना निर्माण के कार्यों हेतु विभिन्न स्रोतों से धन आवंटन को जिला स्तर पर जिलाधिकारी के अधीन नया मद सृजित करते हुए शासन से सीधे धनराशि हस्तान्तरित की जाय, जिसे जिलाधिकारी प्राथमिकतावार धनावंटन/कार्यों का निष्पादन सुनिश्चित करेंगे एवं निरन्तर अनुश्रवण कर शासन को रिपोर्ट करेंगे।

उक्त के फलस्वरूप जहाँ निर्माण कार्यों में गति आयेगी, वहीं अनुश्रवण प्रभावी होगा तथा धन का अपव्यय रूकेगा एवं प्राथमिकता आधारित कार्यों से कार्य सम्पन्न होंगे।

दिनांक 06.05.2022

दिनेश चन्द्र वर्मा
मकान न0–35, क्रॉस–09,
तपोवन इन्कलेव,
रायपुर रोड़, देहरादून
मो0न0–9412910530

Gmail Uttarakhand Budget <uttarakhandbudget@gmail.com>

बजट 2022 -23 संबंधी सुझाव/ 9.5.2022 pdf is attached

2 messages

himal ngo <himalamission@gmail.com> Mon, May 9, 2022 at 9:21 AM
To: uttarakhandbudget@gmail.com

HimalayanInstitute of Multiple Alternatives for Livelihood (H.I.M.A.L)

(Registered under Society Registration Act, 1860)

Add: Village , Ati, Tehsil Bhanoli, Distt. Almora, Uttarakhand Pin: 263622

Ramesh Kr. Mumukshu, President — Basanti Bahen, V. P. पद्मश्री 2022 — Rajinder Tiwari, Gen. Secretary — Basant 8. Pandey, Treasurer & Contact Person

बजट 2022 -23 संबंधी सुझाव/ 9.5.2022

1. ग्रामीण अंचल में हर घर में वर्षा के जल को रोकने का कार्य मिशन मोड़ पर किया। हर घर के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग जरूरी है। लिए फेरो सीमेंट टैंक, अंडर ग्राउंड और अन्य टैंक जरूरी लगवाए जाए ,ताकि वर्ष भर कुछ तो पानी होना ही चाहिए। घर पर पानी रहे और साथ धरती के भीतर भी पानी रिचार्ज हो ,ऐसी व्यवस्था करनी ही होगी। हर घर नल के साथ सभी पानी के स्रोत भी पुनर्जीवित करने ही होंगे। नौले जो भी बचे है, उनको भी पुनर्जीवित किये जायें। पूरे गांव में रेन वाटर हार्वेस्टिंग होगी तो जल को नियंत्रित करके कृषि और जंगल की आग के लिए उपयोग में भी लाया जा सकता है

2. जड़ी बूटी केंद्र सभी ब्लॉक स्तर पर बनाने होंगे ताकि किसान जो जड़ी बूटी का उत्पादन करें तो उसका समय पर निस्तारण हो सकें। सभी को कोई न कोई जड़ी बूटी उगवानी चाहिए। ऐसा सुनिशित किया जायें। इसके लिए अलग से बजट में प्रवधान रखा जाए।

3. गोशाला खोलने के लिए अक्सर लोग प्रयास करते रहते है। जिस गांव में गोशाला खुले उस गांव में प्रत्येक ग्रामीण परिवार जो गाय नही पाल रहा, वो भी पालना शुरू करें ताकि दुधारू पशु पाल सके क्योंकि पशु ग्रमीण जीवन की जीवन रेखा है। एक गांव में एक गाय के लिए घर की स्त्री हमेशा देखभाल में रहती है। जो लोग गोशाला खोलते है, उनके पास इसी तरह पशु की देखभाल की व्यवस्था हो ,इसको पुख्ता किया जाए। इसलिए गोशाला के साथ हर ग्रामीण को गाय पालना या पशुधन का होना जरूरी होगा। इसके लिए चारा उगाया जाए। गोशाला में केवल वो ही पशु रहे, जो बूढ़े हो गए, दूध नही दे पा रहे। गोशाला और डेरी में अंतर रहे। ग्रामीण का पशुधन रखना बहुत जरूरी है। इससे उसकी आये, सेहत के साथ जैविक कृषि का लक्ष्य भी पूरा हो सकता है। चारा उगाने के लिए मिशन मोड़ पर सरकार काम करें ताकि महिला को घास के अतिरिक्त भी चारा मिल सकें।

4. आपदा उत्तराखंड के लिए सतत होने वाली घटना है। आग लगना, वर्षा के दौरान भूस्खलन , बदल फटना होना ही है। इसके तहत हर गांव में प्रशिक्षित टीम के अतिरिक्त आपदा के समय काम आने वाले इक्विपमेंट भी जरूरी होने चाहिए। जैसे आजकल आग लगी हुई है। ऐसे में आग को बुझाने के लिए प्रशिक्षण के अतिरिक्त आग से बचाने वाली ड्रेस भी और इक्विपमेंट जरूरी तौर पर गांव में उपलब्ध हो। विशेषकर दुरस्त गांव जो टेकिंग रूट पर है, जहां पर सड़क नही है। वहां पर वायरलेस सेट, बचाव सामग्री, आपदा के बाद टैंट आदि हमेशा उपलब्ध हो, एन डी आर एफ/ एस डी आर एफ आदि के इंतजाम होने से पूर्व ही गांव वाले खुद ही बचाव कर सकें। गांव की वन पंचायत के माध्यम से जंगल की आग न लगे ,इसके लिए अल्प समय के किये आग नियंत्रक चौकीदार/ पहरेदार की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाए ताकि जंगल की आग को पूरी तरह संरक्षित रखा जा सकें। जंगल को आग से 100% सुरक्षित रखना होगा। सबसे अधिक आग चीड़ के जंगल में लगती है। चीड़ का उपयोग कर बिजली तक बनाई जा रही है। इसके इसके पत्ते ,पिरूल, के उपयोग जैसे बिजली बनाने आदि के लिए हमेशा के लिए नीति और बजट का प्रावधान रखा जाए।

5. उत्तराखंड में आजकल जमीन की खरीद फरोख्त पर काफी चर्चा हो रही है। भू उपयोग सुचारू रूप से हो । इसके बारें में सरकार निर्णय ले ही लेगी। लेकिन इसके साथ गांव में एक इंच खेती की भूमि अनुपयोग न रहे इसके ठोस कदम उठाने है। तीन वर्ष खेती न होने पर जमीन ग्राम सभा हो जाती है , को इम्प्लीमेंट करने से पूर्व सभी भूमिधरों को कृषि वृक्ष, फलदार, जड़ी बूटी व चारा लगाने के लिए निर्देश जारी करें। कितने लोग दशकों से गांव के बाहर रह रहे है। लेकिन कृषि भूमि उनके नाम ही है। लेकिन वो अनुपयोगी और बंजर भी हो गई है। भूमि देश का सबसे बड़ा संसाधन है। उसका पूरा डेटा एकत्रित करके उत्तराखंड की एक एक इंच जमीन भी अनुपयोगी न रहे मिशन मोड़ पर कार्य कदम उठाए। इसके लिए सरकार ठोस कदम उठाए। उत्तराखंड में बहुत सी खेती की जमीन बिना कृषि के बंजर होने के कगार पर है, और कितनी बंजर हो गई। इस बजट में इसका पूरा प्रावधान रखे ताकि डेटा एकत्र हो सके। कृषि भूमि का 100% उपयोग हो सकें ,इसके लिए कदम उठाने जरूरी है। खेती की जमीन बंजर न हो इसके लिए रणनीति बनाई जाए।

6. प्रत्येक घर सोलर लाइट , गीजर उपलब्ध करवाने के लिए सरकार मिशन मोड़ पर कार्य करे। सोलर से लाइट और पनबिजली पर कम दबाव रहेगा। सभी को लगभग वर्षभर गरम पानी चाहिए , इसीलिए सोलर गीजर की व्यवस्था हर घर में रहे, इसके किये गहन चर्चा जरूरी है।

7. पर्यटन के लिए ब्रिटिश समय के सभी डाक बंगलो के रास्ते इम्प्रूव किये जाए। अभी भी पुराने डाक बंगले मौजूद है। वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सड़क से अभी भी जुड़े हुए है। उन सभी को पुनः दुरस्त करके ट्रेकिंग और हाईकिंग ट्रेक बना सकते है। जो परम्परागत तरीके से निर्मित और बनाये जाएं। ये उत्तराखंड के पर्यटन में बड़ा कदम होगा। यूरोप के देशों ने ऐसे ही हाइकिंग ट्रेक संरक्षित किये है। इसके लिए मिशन मोड़ पर सर्वे करके एक रूप रेखा बनाई जाए। ये प्रदेश केलिए गेम चेंजर होगा।

7 (I) मेरे द्वारा नवधाम यात्रा का प्रस्ताव , संलग्न है , जिसमे 4 धाम के अतिरिक्त नंदा देवी , अल्मोड़ा, जागेश्वर धाम, अल्मोड़ा , हाट कल्याणी , पिथौरागढ़, बाघनाथ , बागेश्वर एवं बैजनाथ , बागेश्वर। इस प्रस्ताव पर भी गौर किया जाए।

9. होम स्टे और रिसोर्ट/ होटल प्रॉपर तरीके से परिभाषित किया जाना जरूरी है। होमस्टे गांव में ही होता है। उसमें होटल और रिसोर्ट के जैसी सुविधा देना कठिन है। होमस्टे में ग्रामीण माहौल सहज रूप से रहना चाहिए। लेकिन आजकल लोग जमीन लेकर रिसोर्ट की तरह बना कर उसको होमस्टे के रूप में प्रचारित करते है। इसपर सरकार को स्पष्ट परिभाषा तय करनी होगी। ये न हो कि खोला होटल लेकिन प्रचारित कर दिया होमस्टे , इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

8. फलदार पेड़ों की बेल्ट लगानी है ताकि व्यक्तिगत स्तर पर भी फलों के पेड़ लगने चाहिए। वृक्ष खेती जिसमे अखरोट, सेब समेत सभी फल। कुछ जंगली फल होते है, जैसे काफल आदि को भी बढ़ावा दिया जा सकता है।ध्यान रखा जाए प्रत्येक ग्रामीण फल के इतने पेड़ लगाए ताकि स्वयं का और कुछ आय तो हो ही जाए।

9. उत्तराखंड में रेशा उद्योग हमेशा ही रहा है। उसको पुनः लाकर एक ओर आय में वृद्धि करेगा और दूसरी ओर पर्यावरण के लिए उपयोग सिद्ध होगा। इसके लिए बजट में प्रावधान रखा जाए।

10. छोटे- छोटे स्टार्टअप के लिए सरकार मिशन मोड़ पर काम करें। ये ग्रामीण स्तर पर ही शुरू हो। जड़ी बूटी, फल, फूल, तुलसी, हल्दी, अदरक, जंगली फल, फूल, आदि युवाओं को फूड प्रोसेस, पैकेजिंग, मार्केटिंग के लिए कमर कस लेनी चाहिए। इत्र, पल्प, रस, जूस, रिंगाल एवं बांस के विभिन्न प्रयोग, कारपेट,दन आदि को मिशन मोड़ पर लाया जाए। ऊन से जुड़े छोटे छोटे स्टार्टअप शुरू करें। कभी धारचूला , बागेश्वर में भी ऊन की मशीनें लगी थी। उसको तेजी से उभारा जाए। इससे से खुशहाली के अतिरिक्त पर्यावरण संरक्षण भी होगा। पहाड़ अपनी पहचान के साथ आगे बढ़ेगा।

11. स्वास्थ्य सुविधाएं अभी भी प्रदेश में कम ही हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को पोलीक्लीनिक में तब्दील किया जाए ताकि विजिटिंग डॉक्टर रूटीन में आ सके और पैथोलॉजी सुविधाओं को बढ़ाया जाए। फिजियोथेरेपी जैसी सुविधाएं भी कहीं उपलब्ध नहीं है। इसके अतिरिक्त एच आई वी अनाथ बच्चो को प्रतिमाह 2000 हज़ार रुपये प्रदान किये जायें ताकि वो गांव में ही रह सके। हालांकि ये बड़ा काम है, इसके लिए सरकार को विस्तार से ही देखना होगा।

12. सरकारी स्कूलों पर अधिक ध्यान दिया जाए। अभी उनमें संख्या कम हो रही है। प्राइवेट स्कूल तेजी से खुल रहे है। प्राइवेट स्कूल खोलने की प्रक्रिया को सक्रिय और पुख्ता किया जाए। बजट में इसके गहन अध्ययन और डेटा एकत्रित किया जाए।

विशेष आग्रह: इन सब के लिए ग्राम प्रधान ,पंचायत और उनकी बैठक जो ग्रामीणों के साथ होती।है, उनको पुख्ता करना होगा। अभी ग्राम पंचायत की खुली बैठक नाम मात्र के होतीहै। इसको तेजी से बढ़ाना होगा। इसके अतिरिक्त कभी महिला मंगल दल, युवक मंगल दल, किशोरी मंगल दल ग्रामीण इलाकों में बहुत सक्रिय हुआ करते थे। गांव की सफाई, जंगल की आग, जागरूकता के विभिन्न कार्यक्रम हुआ करते थे। उनको पुनः एक्टिव किया जाए। विभिन्न समूह अभी भी है, वो कितनी बार लगता है ,केवल पैसा कलेक्शन के लिए सीमित हो चुके है। उनको इसके इलावा भी एक्टिव किया।जाए। इस कार्य में समाज सेवी संस्थाओं का अहम रोल हो सकता है। वर्षों पूर्व आजीविका संवर्द्धन परियोजना के तहत समूह और फेडरेशन तैयार हुए थे। जिनको मार्किट से जुड़ना था। इन सब को पुनः सक्रिय किया जाए। अभी हाल फिलहाल में ग्रामीण स्तर पर किसान समूह गठित किये गए है। उनको भी सक्रिय किया जाए। उपरोक्त सभी एक सूत्र में बांधकर प्रदेश को आगे और ग्रामीणों को साधन संपन्न कर देंगे।

(रमेश कुमार मुमुक्षु)
अध्यक्ष, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मल्टीपल अल्टरनेटिव फॉर लाइवलीहुड (HIMALAYAN INSTITUTE OF MULTIPLE ALTERNATIVE FOR LIVELIHOOD) H.I.M.A.L.हिमाल
ग्राम आटी, पोस्ट : दन्या , जिला अल्मोड़ा, उत्तराखंड : 9810610400
बैंक डिटेल भी दे दे रहे है
श्री बसंत पाण्डेय: 992772481

बजट 2022-23 पीडीएफ़.pdf
560K

---

himal ngo <himalamission@gmail.com>
To: uttarakhandbudget@gmail.com

Mon, May 9, 2022 at 9:25 AM

Nav Dham Yatra doc is attached for Budget 2022-23
[Quoted text hidden]

NAV DHAM YATRA PROPOSAL 2021 pdf.pdf
866K

HimalayanInstitute of Multiple Alternatives for Livelihood (H.I.M.A.L)
(Registered under Society Registration Act, 1860)
Add: Village , Ati, Tehsil Bhanoli, Distt, Almora, Uttarakhand Pin: 263622

Ramesh Kr. Mumukshu	**Basanti Bahen**	Rajinder Tiwari	Basant B. Pandey
President	V. P. पद्मश्री,2022	Gen. Secretary	Treasurer & Contact Person

बजट 2022 -23 संबंधी सुझाव/ 9.5.2022

1. ग्रामीण अंचल में हर घर में वर्षा के जल को रोकने का कार्य मिशन मोड़ पर किया। हर घर के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग जरूरी है। लिए फेरो सीमेंट टैंक, अंडर ग्राउंड और अन्य टैंक जरूरी लगवाए जाए ,ताकि वर्ष भर कुछ तो पानी होना ही चाहिए। घर पर पानी रहे और साथ धरती के भीतर भी पानी रिचार्ज हो ,ऐसी व्यवस्था करनी ही होगी | हर घर नल के साथ सभी पानी के स्रोत भी पुनर्जीवित करने ही होंगे। नौले जो भी बचे है, उनको भी पुनर्जीवित किये जायें। पूरे गांव में रेन वाटर हार्वेस्टिंग होगी तो जल को नियंत्रित करके कृषि और जंगल की आग के लिए उपयोग में भी लाया जा सकता है

2. जड़ी बूटी केंद्र सभी ब्लॉक स्तर पर बनाने होंगे ताकि किसान जो जड़ी बूटी का उत्पादन करें तो उसका समय पर निस्तारण हो सकें। सभी को कोई न कोई जड़ी बूटी उगवानी चाहिए। ऐसा सुनिशित किया जाय। इसके लिए अलग से बजट में प्रवधान रखा जाए |

3. गोशाला खोलने के लिए अक्सर लोग प्रयास करते रहते है। जिस गांव में गोशाला खुले उस गांव में प्रत्येक ग्रामीण परिवार जो गाय नही पाल रहा, वो भी पालना शुरु करें ताकि दुधारू पशु पाल सके क्योंकि पशु ग्रामीण जीवन की जीवन रेखा है। एक गांव में एक गाय के लिए घर की स्त्री हमेशा देखभाल में रहती है। जो लोग गोशाला खोलते है, उनके पास इसी तरह पशु की देखभाल की व्यवस्था हो ,इसको पुख्ता किया जाए। इसलिए गोशाला के साथ हर ग्रामीण को गाय पालना या पशुधन का होना जरूरी होगा। इसके लिए चारा उगाया जाए। गोशाला में केवल वो ही पशु रहे, जो बूढ़े हो गए, दूध नही दे पा रहे। गोशाला और डेरी में अंतर रहे। ग्रामीण का पशुधन रखना बहुत जरूरी है। इससे उसकी आय, सेहत के साथ जैविक कृषि का लक्ष्य भी पूरा हो सकता है। चारा उगाने के लिए मिशन मोड़ पर सरकार काम करें ताकि महिला को घास के अतिरिक्त भी चारा मिल सके।

4. आपदा उत्तराखंड के लिए सतत होने वाली घटना है। आग लगना, वर्षा के दौरान भूस्खलन , बदल फटना होना ही है। इसके तहत हर गांव में प्रशिक्षित टीम के अतिरिक्त आपदा के समय काम आने वाले इक्विपमेंट भी जरूरी होने चाहिए। जैसे आजकल आग लगी हुई है। ऐसे में आग को बुझाने के लिए प्रशिक्षण के अतिरिक्त आग से बचाने वाली ड्रेस भी और इक्विपमेंट जरूरी तौर पर गांव में

उपलब्ध हो। विशेषकर दुरस्त गांव जो टेकिंग रूट पर हैं, जहां पर सड़क नही है। वहां पर वायरलेस सेट, बचाव सामग्री, आपदा के बाद टैंट आदि हमेशा उपलब्ध हो, एन डी आर एफ/ एस डी आर एफ आदि के इंतजाम होने से पूर्व ही गांव वाले खुद ही बचाव कर सके। गांव की वन पंचायत के माध्यम से जंगल की आग न लगे ,इसके लिए अल्प समय के किये आग नियंत्रक चौकीदार/ पहरेदार की व्यवस्था अनिवार्य रूप से की जाए ताकि जंगल की आग को पूरी तरह संरक्षित रखा जा सकें। जंगल को आग से 100% सुरक्षित रखना होगा। सबसे अधिक आग चीड़ के जंगल में लगती है। चीड़ का उपयोग कर बिजली तक बनाई जा रही है। इसके इसके पते ,पिरूल, के उपयोग जैसे बिजली बनाने आदि के लिए हमेशा के लिए नीति और बजट का प्रावधान रखा जाए।

5. उत्तराखंड में आजकल जमीन की खरीद फरोख्त पर काफी चर्चा हो रही है। भू उपयोग सुचारू रूप से हो । इसके बारें में सरकार निर्णय ले ही लेगी। लेकिन इसके साथ गांव में एक इंच खेती की भूमि अनुपयोग न रहे इसके ठोस कदम उठाने है। तीन वर्ष खेती न होने पर जमीन ग्राम सभा हो जाती है , को इम्पलीमेंट करने से पूर्व सभी भूमिधरों को कृषि,वृक्ष, फलदार, जड़ी बूटी व चारा लगाने के लिए निर्देश जारी करें। कितने लोग दशकों से गांव के बाहर रह रहे है। लेकिन कृषि भूमि उनके नाम ही है। लेकिन वो अनुपयोगी और बंजर भी हो गई है। भूमि देश का सबसे बड़ा संसाधन है। उसका पूरा डेटा एकत्रित करके उत्तराखंड की एक एक इंच जमीन भी अनुपयोगी न रहे मिशन मोड़ पर कार्य कदम उठाए। इसके लिए सरकार ठोस कदम उठाए। उत्तराखंड में बहुत सी खेती की जमीन बिना कृषि के बंजर होने के कगार पर है, और कितनी बंजर हो गई। इस बजट में इसका पूरा प्रावधान रखे ताकि डेटा एकत्र हो सके। कृषि भूमि का 100% उपयोग हो सकें ,इसके लिए कदम उठाने जरूरी है। खेती की जमीन बंजर न हो इसके लिए रणनीति बनाई जाए।

6. प्रत्येक घर सोलर लाइट , गीजर उपलब्ध करवाने के लिए सरकार मिशन मोड़ पर कार्य करें। सोलर से लाइट और पनबिजली पर कम दबाव रहेगा। सभी को लगभग वर्षभर गरम पानी चाहिए , इसीलिए सोलर गीजर की व्यवस्था हर घर में रहे, इसके किये गहन चर्चा जरूरी है।

7. पर्यटन के लिए ब्रिटिश समय के सभी डाक बंगलो के रास्ते इम्प्रूव किये जाए। अभी भी पुराने डाक बंगले मौजूद है। वो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की सड़क से अभी भी जुड़े हुए है। उन सभी को पुनः दुरस्त करके ट्रैकिंग और हाईकिंग ट्रेक बना सकते है। जो परम्परागत तरीके से निर्मित और बनाये जाए। ये उत्तराखंड के पर्यटन में बड़ा कदम होगा। यूरोप के देशों ने ऐसे ही हाईकिंग ट्रेक संरक्षित किये है। इसके लिए मिशन मोड पर सर्वे करके एक रूप रेखा बनाई जाए। ये प्रदेश केलिए गेम चैंजर होगा।

7 (I) मेरे द्वारा नवधाम यात्रा का प्रस्ताव , संलग्न है , जिसमें 4 धाम के अतिरिक्त नंदा देवी , अल्मोड़ा, जागेश्वर धाम, अल्मोड़ा , हाट कल्याणी , पिथौरागढ़, बागनाथ , बागेश्वर एवं बैजनाथ , बागेश्वर | इस प्रस्ताव पर भी गौर किया जाए।

9. होम स्टे और रिसोर्ट/ होटल प्रॉपर तरीके से परिभाषित किया जाना जरूरी है। होमस्टे गांव में ही होता है। उसमें होटल और रिसोर्ट के जैसी सुविधा देना कठिन है। होमस्टे में ग्रामीण माहौल सहज रूप से रहना चाहिए। लेकिन आजकल लोग जमीन लेकर रिसोर्ट की तरह बना कर उसको होमस्टे के

रूप में प्रचारित करते हैं। इसपर सरकार को स्पष्ट परिभाषा तय करनी होगी। ये न हो कि खोला होटल लेकिन प्रचारित कर दिया होमस्टे , इस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

8. फलदार पेड़ों की बेल्ट लगानी है ताकि व्यक्तिगत स्तर पर भी फलों के पेड़ लगने चाहिए। वृक्ष खेती जिसमे अखरोट, सेब समेत सभी फल। कुछ जंगली फल होते हैं, जैसे काफल आदि को भी बढ़ावा दिया जा सकता है।ध्यान रखा जाए प्रत्येक ग्रामीण फल के इतने पेड़ लगाए ताकि स्वयं का और कुछ आय तो हो ही जाए।

9. उत्तराखंड में रेशा उद्योग हमेशा ही रहा है। उसको पुनः लाकर एक ओर आय में वृद्धि करेगा और दूसरी ओर पर्यावरण के लिए उपयोग सिद्ध होगा। इसके लिए बजट में प्रावधान रखा जाए।

10. छोटे- छोटे स्टार्टअप के लिए सरकार मिशन मोड़ पर काम करें। ये ग्रामीण स्तर पर ही शुरू हो। जड़ी,बूटी, फल, फूल, तुलसी, हल्दी, अदरक, जंगली फल, फूल, आदि युवाओं को फूड प्रोसेस, पैकेजिंग, मार्केटिंग के लिए कमर कस लेनी चाहिए। इत्र, पल्प, रस, जूस, रिंगाल एवं बांस के विभिन्न प्रयोग, कारपेट,दन आदि को मिशन मोड़ पर लाया जाए। ऊन से जुड़े छोटे छोटे स्टार्टअप शुरू करें। कभी धारचूला , बागेश्वर में भी ऊन की मशीनें लगी थीं। उसको तेजी से उभारा जाए। इससे से खुशहाली के अतिरिक्त पर्यावरण संरक्षण भी होगा। पहाड़ अपनी पहचान के साथ आगे बढ़ेगा।

11. स्वास्थ्य सुविधाएं अभी भी प्रदेश में कम ही हैं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को पोलीक्लीनिक में तब्दील किया जाए ताकि विजिटिंग डॉक्टर रूटीन में आ सके और पैथोलॉजी सुविधाओं को बढ़ाया जाए। फिजियोथेरेपी जैसी सुविधाएं भी कही उपलब्ध नही हैं। इसके अतिरिक्त एच आई वी अनाथ बच्चो को प्रतिमाह 2000 हज़ार रुपये प्रदान किये जायें ताकि वो गांव में ही रह सकें। हालांकि ये बड़ा काम है, इसके लिए सरकार को विस्तार से ही देखना होगा।

12. सरकारी स्कूलों पर अधिक ध्यान दिया जाए। अभी उनमें संख्या कम हो रही है। प्राइवेट स्कूल तेजी से खुल रहे हैं। प्राइवेट स्कूल खोलने की प्रक्रिया को सक्रिय और पुख्ता किया जाए। बजट में इसके गहन अध्ययन और डैटा एकत्रित किया जाए।

विशेष आग्रह: इन सब के लिए ग्राम प्रधान ,पंचायत और उनकी बैठक जो ग्रामीणों के साथ होती।है, उनको पुख्ता करना होगा। अभी ग्राम पंचायत की खुली बैठक नाम मात्र के होतीहै। इसको तेजी से बढ़ाना होगा। इसके अतिरिक्त कभी महिला मंगल दल, युवक मंगल दल, किशोरी मंगल दल ग्रामीण इलाकों में बहुत सक्रिय हुआ करते थे। गांव की सफाई, जंगल की आग, जागरूकता के विभिन्न कार्यक्रम हुआ करते थे। उनको पुनः एक्टिव किया जाए। विभिन्न समूह अभी भी है, वो कितनी बार लगता है ,केवल पैसा कलेक्शन के लिए सीमित हो चुके है। उनको इसके इलावा भी एक्टिव किया।जाए। इस कार्य में समाज सेवी संस्थाओं का अहम रोल हो सकता है। वर्षो पूर्व आजीविका संवर्द्धन परियोजना के तहत समूह और फेडरेशन तैयार हुए थे। जिनको मार्किट से जुड़ना था। इन सब को पुनः सक्रिय किया जाए। अभी हाल फिलहॉल में ग्रामीण स्तर पर किसान समूह गठित किये गए है। उनको भी सक्रिय

किया जाए। उपरोक्त सभी एक सूत्र में बांधकर प्रदेश को आगे और ग्रामीणों को साधन संपन्न कर देंगे।

(रमेश कुमार मुमुक्षु)
अध्यक्ष, हिमालयन इंस्टीटूट ऑफ मल्टीप्ल अल्टरनेटिव फ़ॉर लाइवलीहुड (HIMALAYAN INSTITUTE OF MULTIPLE ALTERNATIVE FOR LIVELIHOOD) H.I.M.A.L.हिमाल
ग्राम आटी, पोस्ट : दन्या , जिला अल्मोड़ा, उत्तराखंड : 9810610400
बैंक डिटेल भी दे दे रहे है
श्री बसंत पाण्डेय: 992772481

Himalayan Institute of Multiple Alternatives for Livelihood (H.I.M.A.L)
(Registered Under Society Registration Act, 1860)

सेवा में   18.12.2021

1. माननीय प्रधान मंत्री महोदय
   भारत सरकार, प्रधानमंत्री कार्यालय,
   रायसीना हिल्स, साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली 110011

2. माननीय मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री महोदय, उत्तराखंड,
   मुख्यमंत्री कार्यालय , देहरादून, उत्तराखंड

विषय: उत्तराखंड में चार धाम यात्रा को बढ़ाकर नव धाम यात्रा घोषित की जाए। नव धाम यमनोत्री- गंगोत्री - केदारनाथ बद्रीनाथ- बैजनाथ धाम मंदिर समूह - बागनाथ- महाकाली/ हाट कल्याणी-जागेश्वर धाम मंदिर समूह- नंदा देवी, अल्मोड़ा

मान्यवर महोदय,

उत्तराखंड की चार धाम यात्रा विश्वपटल पर जानी जाती है। चार धाम यात्रा पर केंद्र और प्रदेश सरकार ने बहुत प्रचार व प्रसार का कार्य विगत कुछ वर्षों में किया है। चार धाम उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल में स्थित है। कुमाऊं मंडल में चार धाम के अतिरिक्त भी धाम स्थित है। ये सभी धाम पौराणिक एवं ऐतिहासिक महत्व के है। इन सभी धामों के मध्य तुलना नही की जानी चाहिए ,सभी विशिष्ट है। मेरा केंद्र सरकार ,उत्तराखंड सरकार और पर्यटन विभाग से अनुरोध है कि उत्तराखंड में चार धाम यात्रा को नवधाम यात्रा के रूप में घोषित किये जाने पर विचार करना चाहिए।वर्तमान में यमनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम को चारधाम के रूप में माना जाता है। ये सभी धाम गढ़वाल मंडल में स्थित है।

मेरा प्रस्तावपाँच,5,धाम बैजनाथ धाम मंदिर समूह - बागनाथ- महाकाली/ हाट कल्याणी-जागेश्वर धाम मंदिर समूह- नंदा देवी, अल्मोड़ा, को कुमाऊं मंडल में सम्मिलित किए जा सकते है। ये दो मंडल उत्तराखंड की पहचान है। निम्न धाम सम्मिलित किये जा सकते है :-

(i) पहला धाम : हल्द्वानी से आगे आने पर पहला धाम होगा , नंदादेवी मंदिर अल्मोड़ा शहर में अवस्थित है। यहीं पर रघुनाथ मंदिर भी स्थित है। नंदा देवी से होते हुए , कसार देवी , गोलुदेवता होते हुए आगे जाना होता है।

Ati

Vill. Ati, Danya, Tehsil Bhanoli, Distt, Almora, UttaraKhand Pin: 263622
9810610400 | 7579132181
himalamission@gmail.com

(ii) दूसरा धाम: वहां से पिथौरागढ़ की ओर जाने पर गोलू देवता, लखुडियार ,प्रागैतिहासिक चित्र रॉक पर अभी भी देखे जा सकते हैं। पेठशाल से पहले स्थित है। उसके बाद दूसरा धाम जागेश्वर धाम मंदिर समूह आता है, यहां पर भी ज्योतिर्लिंग की स्थित है। जागेश्वर धाम से पहले वृद्ध जागेश्वर भी आता है। ये सिद्ध, ऐतिहासिक एवं पौराणिक देवस्थल है। भगवान शंकर के स्थानों में इसका भी विशिष्ट महत्व है।

(iii) तीसरा धाम: जागेश्वर से आगे दन्या होते हुए ,घाट पनार जहां पर पनार और सरयू नदी का संगम है । वहां से आगे जाने पर गंगोलीहाट स्थित तीसरा धाम महाकाली मंदिर एवं स्थानीय बोली में हॉट कल्याणी का मंदिर आता है, तीसरा धाम भी पौराणिक महत्व का धाम है। इसकी स्थापना के लिए आदि शंकराचार्य ने इस स्थान को चुना था। इसके नज़दीक ही चामुण्डा मंदिर एवं पाताल भुवनेश्वर की प्रसिद्ध गुफा भी मौजूद है।

(iv) चौथा धाम: तीसरे धाम के बाद बेरीनाग, चौकोड़ी होते हुए ,चौथा धाम आता है , बागनाथ का मंदिर ,ये गोमती और सरयू नदी के संगम पर स्थित है। स्कन्द पुराण में इसका उल्लेख मिलता है। मार्कण्डेय ऋषि ने बाघ के रूप में यहां पर तप किया था। बागेश्वर जिला मुख्यालय भी है, जहां पर विश्वप्रसिद्ध उतरायणी मेला जनवरी में मकरसंक्रांति के दिन लगता है।

(v) पांचवा धाम: बागेश्वर धाम के आगे पांचवा धाम बैजनाथ मंदिर समूह , जो गरुड़ ,जिसका पुरातन नाम कार्तिकेय पुर कहलाता था, ये कभी चंद्र राजाओं की राजधानी भी स्तिथ थी। ये हमारा पांचवा धाम होगा। जहां पर पार्वती की विलक्षण मूर्ति भी स्थित है। गोमती नदी के तट पर स्थित है।

इस तरह उत्तराखंड में चार धाम की जगह नवधाम यात्रा के रूप में इसको मान्यता मिलनी चाहिए ताकि सम्पूर्ण प्रदेश का एक साथ समान रूप से विकास हो सकें। ये पांचों धाम भी पौराणिक महत्व के है। चमोली जिले के कर्णप्रयाग से पंच धाम , बैजनाथ की ओर आया जा सकता है ,या बैजनाथ से कर्णप्रयाग की ओर चारधाम की ओर आया जा सकता है। इस तरह प्रदेश में चारधाम की जगह नवधाम यात्रा का शुभारंभ हो सकेगा। उत्तराखंड इन सभी धामों के साथ एक विशिष्ट राज्य के रूप में उभर कर आएगा।

प्रार्थना:

माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री ,उत्तराखंड , पर्यटन मंत्री भारत सरकार एवं उत्तराखंड सरकार से अनुरोध है कि इस पर विचार किजिएगा।इनके अतिरिक्त समस्त दलों एवं विपक्ष से भी अनुरोध है , इस प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त करें।नव धाम यात्रा प्रदेश में पर्यटन की संभावना को ठोस आधार देगा, ये तय है। इनका विकास पूर्ण रूप से पर्यावरण संरक्षण को अक्षुण्ण रखते हुए ही किया जाए, इस तथ्य को हम सब ध्यान में रखेंगे तो प्रदेश का विकास सतत विकास की अवधारणा के साथ ही होगा।

आशा ही नही, पूर्ण विश्वास है कि आप इस प्रस्ताव पर कार्यवाही करेंगे।

नोट: सरकार भी अपने मापदंडों के आधार पर इसका मूल्यांकन कर ही लेगी, लेकिन उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए, नव धाम यात्रा को मान्यता मिल ही जानी चाहिए।

धन्यवाद

भवदीय

18-12-2021

(रमेश कुमार मुमुक्षु)
अध्यक्ष, हिमाल, ग्राम आटी, दन्या , जिला: अल्मोड़ा , उत्तराखंड
9810610400
मेल: himalamission@gmail.com

17.12.2021

संपर्क व्यक्ति: श्री बसंत बल्लभ पांडेय , ग्राम आटी, दन्या, जिला , अल्मोड़ा , उत्तराखंड
+919927672481

प्रति: 1.केंद्रीय एवं उत्तराखंड पर्यटन मंत्री

2. जिलाधिकारी अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ एवं बागेश्वर

Gmail Uttarakhand Budget <uttarakhandbudget@gmail.com>

RADHIKA FURNITURE GSTIN-05ATVPD7311B1Z0 Udhyam Registration - UDYAM-UK-07-0000329 Adhaar no-8070 0243 2579 Pan no - ATVPD7311B Address-Chandani Chowk Ghurdaura, Rampur road, Haldwani Pin code-263139 Phone number - 917443929

message

handran singh <rfurniture2018@gmail.com> Tue, May 10, 2022 at 9:19 AM
o: "uttarakhandbudget@gmail.com" <uttarakhandbudget@gmail.com>

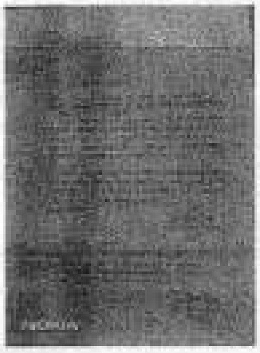

IMG-20220510-WA0002.jpg
71K

प्रेषक,

जिला सहायक निबन्धक,
सहकारी समितियाँ उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सेवा में,

निजी सचिव,
मा0 मुख्य मंत्री जी,
उत्तराखण्ड सरकार देहरादून।

पत्रांक /शिका0-जांच/मु0म0-सन्दर्भ/जनमिलन कार्यक्रम/2021-22/दिनांक 6 अक्टूबर 2021।

विषय- दिनांक 04.09.2021 को माननीय मुख्य मंत्री जी के जनता दरबार कार्यक्रम में प्राप्त शिकायत के निस्तारण के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक दिनांक 04.09.2021 को माननीय मुख्य मंत्री जी, उत्तराखण्ड सरकार के आवास में आयोजित जन मिलन कार्यक्रम में श्रीमती राधा देवी, ग्राम चांदनी चौक, बुदपोखरा, रामपुर रोड, हल्द्वानी का शिकायती पत्र इस कार्यालय के पत्रांक 841-16/मु0म0-सन्दर्भ/जन मिलन कार्यक्रम/2021-22/दिनांक 06.09.2021 द्वारा अग्रेतर कार्यवाही हेतु सचिव/महाप्रबन्धक नैनीताल डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक लि0 हल्द्वानी को प्रेषित की गई।

तत्क्रम में सचिव/महाप्रबन्धक नैनीताल डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक लि0 हल्द्वानी द्वारा प्रेषित कार्यालय पत्रांक 1777/प्रशा0/सूचना/2021-22 दिनांक 14.09.2021 की प्रति संलग्नकों सहित आपकी सेवा में इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया तदनुसार माननीय मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में लाने का कष्ट करें।

संलग्न- उक्तानुसार।

जिला सहायक निबन्धक,
सहकारी समितियाँ उत्तराखण्ड,
देहरादून।

पत्रांक 2002-05 /तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. श्रीमती राधा देवी, ग्राम चांदनी चौक, बुदपोखरा, रामपुर रोड, हल्द्वानी।
2. सचिव/महाप्रबन्धक, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव बैंक लि0 हल्द्वानी।
3. जिला सहायक निबन्धक, सहकारी समितियाँ उत्तराखण्ड, नैनीताल।

जिला सहायक निबन्धक,
सहकारी समितियाँ उत्तराखण्ड
देहरादून।

NOKIA

Gmail — Uttarakhand Budget <uttarakhandbudget@gmail.com>

Fw: आपका बजट, आपका सुझाव बजट 2022 -23
1 message

MOHAN CHANDRA <chandramohansati@yahoo.co.in> — Tue, May 3, 2022 at 10:08 PM
Reply-To: MOHAN CHANDRA <chandramohansati@yahoo.co.in>
To: "uttarakhandbudget@gmail.com" <uttarakhandbudget@gmail.com>

Best regards,

Mohan Chandra Sati
+91-9811390718

----- Forwarded message -----
From: MOHAN CHANDRA <chandramohansati@yahoo.co.in>
To: pmo@govmu.org <pmo@govmu.org>; uttrakhandbudget@gmail.co <uttrakhandbudget@gmail.co>; cm-ua@nic.in <cm-ua@nic.in>; cm-helpline@uk.gov.in <cm-helpline@uk.gov.in>; secretary-vs-uk@gov.in <secretary-vs-uk@gov.in>; pccf_uta@yahoo.com <pccf_uta@yahoo.com>; pccfuk@gmail.com <pccfuk@gmail.com>; DFO Lansdowne <dfo.lansdowne@gmail.com>; cgm-js-ua@nic.in <cgm-js-ua@nic.in>; cgmujs@gmail.com <cgmujs@gmail.com>
Sent: Tuesday, 3 May, 2022, 05:58:45 pm IST
Subject: आपका बजट, आपका सुझाव बजट 2022 -23

माननीय मुख्य मंत्री महोदय,
सर्वप्रथम अक्षय तृतीया की शुभकामनाओं के साथ गोल्ज्यू देवता से से करबद्ध प्रार्थना है कि इस प्रदेश के हित के लिए चम्पावत विधान सभा से प्रचंड बहुमतों से आपके पक्ष में एक अभूतपूर्व ऐतिहासिक सफलता दर्ज़ हो। निस्संदेह आपकी लोकप्रियता से हम पूर्ण रूप सेऐतिहासिक जीत के लिए आश्वस्त हैं, परन्तु कोटद्वार एक बार जनरल साहब के हारने की कीमत दे चूका है, इसलिए प्रभु से प्रार्थना व सावधानी जरुरी है।
उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास के लिए आपकी सराहनीय समर्पणता, ततपरता एवं कर्मण्यता के लिए इस प्रदेश का प्रत्येक जन मानस दिल से आभारी है।इसी क्रम में प्रदेश की समृद्धि व विकास के लिए बजट निर्माण प्रक्रिया में जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आपके प्रयासों से आज मुझे अपने क्षेत्र की जन हित की निम्नांकित महत्वपूर्ण आवेदित व बहुप्रतीक्षित योजनाओं के लिए बजट आबंटन हेतु सुझाव देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है :-

1.लैन्सडौन वन प्रभाग कोटद्वार के अंतर्गत सिगड्डी भाबर क्षेत्र में आरक्षित वन क्षेत्र राजाजी नेशनल पार्क के वन पर्यावरण, वन्य प्राणी, ग्रामीणों की खेती व मवेशियों की जान की सुरक्षा हेतु सिंबलखाल से सिडकुल की बॉउंड्री दीवार तक लगातार जमीन की सतह से 9 फुट ऊँची, जमीन की सतह से 3 फुट गहरी एवं 2 फुट चौड़ी (लम्बाई लगभग 1.6 किलोमीटर), गेटरहित गुणवत्तापूर्ण सुरक्षा दीवार के निर्माण के लिए ग्रामीणों का प्रार्थना पत्र वन विभाग में बजट आबंटन की प्रतीक्षा में विचाराधीन है।

2. वार्ड 36 कोटद्वार में जलसंस्थान एवं पेयजल निगम द्वारा जलजनित बीमारियों से बचाव के लिए व पूरी तरह बुनियादी आवश्यक जरूरतों जैसे स्वच्छ उपचार, जमावट, flocculation, तलछट, फिल्टीरेशन और कीटाणुशोधन उपचारों से युक्त सामुदायिक जल आपूर्ति हेतु लोकमनीपुर में पूर्व में चिन्हित व स्वीकृत स्थान पर ओवर हेड टैंक व पम्पिंग स्टेशन के निर्माण के लिए ग्रामीणों का प्रार्थना पत्र जलसंस्थान एवं पेयजल निगम विभाग में बजट आबंटन की प्रतीक्षा में विचाराधीन है।

3. कोटद्वार - हरिद्वार मुख्य मोटर मार्ग में किशनपुरी व सिगड्डी के बीच में तेलिसोत नदी के ऊपर पुल निर्माण हेतु ग्रामीणों का प्रार्थना पत्र लोक निर्माण विभाग दुगड्डा में बजट आबंटन की प्रतीक्षा में विचाराधीन है।

4. सिगड्डी सोत के शीर्ष (हेड) में गत वर्ष में लगभग 2.7 करोड़ रूपये की लागत लगाकर प्राकृतिक संशाधनो में उपलब्ध पानी को किसानों की खेती की सिंचाई हेतु पहुँचाने के क्रम में ग्राम मनदवेपुर सिगड्डी के प्रार्थी कृषकों के पूर्ण रूप से जीर्ण - क्षींण व विलुप्त कुलावा न० 8, 9, एवं 10 के निर्माण के लिए ग्रामीणों का प्रार्थना पत्र, श्रीमान अधिशाषी अभियंता, सिंचाई खण्ड दुगड्डा कोटद्वार, सिंचाई विभाग, कैनाल विभाग दुगड्डा, तहसील - कोटद्वार, जिला - पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड कार्यालय में विचाराधीन है व बजट आबंटन की प्रतीक्षा में कुलावा निर्माण कार्य अवरोधित है।

5. कोटद्वार भाबर क्षेत्र के अंतर्गत 11 कि0 मी0 लम्बाई के लालढांग - चिलरखाल मोटर मार्ग पर पक्का /ऑल वेदर रोड निर्माण हेतु गत वर्षों में क्रमशः 26.20 करोड़ एवं विस्तृत व पुनरीक्षित विस्तृत आगणन में 46.71 करोड़ रूपये (कुल 72.91 करोड़ रूपये) खर्च / परियोजना की कुल लागत के बावजूद भी मोटर मार्ग की हालत कच्चा एवं जस की तस होने के सम्बन्ध में शुद्ध आंकलन के उपरांत निर्माण हेतु बजट आबंटित करने की कृपा करें ।

Best regards,

Mohan Chandra Sati,Advocate
Social Activist with Nationalist mindset as that of great Modiji
Mandavepur Sigaddi, Kotdwar
+91-9811390718

---

9 attachments

DSCN5585.JPG
6607K

DSCN5605.JPG
6683K

DSCN5608.JPG
6569K

Prman Ptr Sigddi Nahar.docx
23K

PMO (copy) Surksha Dewar.pdf
1071K

Complaint CM Helpline (Jalansthan- Jul,21).pdf
425K

CMHELPLINE (L-4).pdf
342K

PMO Laldhang Road.docx

41K

PWD-RTI (Chilarkhal-Laldhang Road).pdf
759K

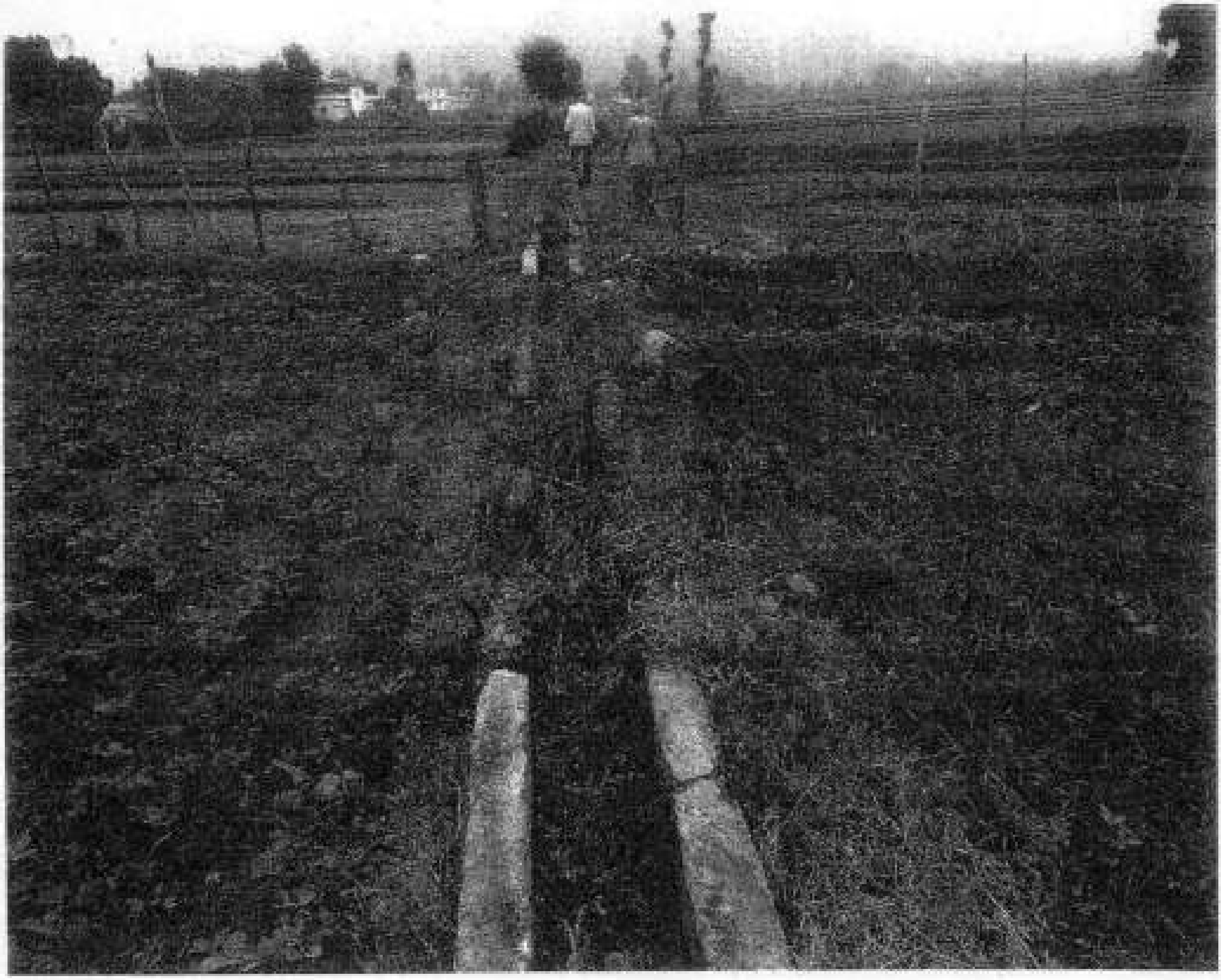

पिछले 9-10 वर्षों से सिगड्डी नहर की बिलकुल भी साफ़ सफाई व मरम्मत न होने के कारण आर्थिक व मानसिक रूप से पीड़ित प्रार्थीगणों द्वारा प्रस्तुत ज्ञापन / प्रमाणपत्र

ध्यान आकर्षण - उत्तराखंड सिंचाई विभाग के समस्त अधिकारीगण व माननीय सिंचाई मंत्री

महोदय / महोदया,

सिंचाई विभाग के अधिकारियों व ठेकेदारों की भ्रष्ट कार्य शैली, अकर्यमणता, मिलीभगत व हेरा फेरी से, पिछले 9 -10 वर्षों से, उपरोक्त नहर की बिल्कुल भी साफ़ सफाई व मरम्मत न होने के कारण, सिगड्डी सोत व मालन नदी के प्राकृतिक स्रोतों में उपलब्ध सिंचाई के पानी से वंचित सिगड्डी भाबर क्षेत्र के आर्थिक, मानसिक एवं शारीरिक रूप से पीड़ित ग्रामीण किसानों द्वारा प्रस्तुत :-

1. हम सभी अधोहस्ताक्षरित कृषकगण सिगड्डी भाबर क्षेत्र के स्थायी निवासी हैं। क्षेत्रीय किसानों के हितों के लिए लगातार कार्यरत श्री मोहन चंद्र सती, अधिवक्ता दिल्ली उच्च न्यायालय, मूल निवासी ग्राम - मनदेवपुर, पट्टी - हल्दूखाता ने सूचना के अधिकार के अंतर्गत, सिगड्डी नहर से संबंधित, सिंचाई विभाग से कुछ महत्वपूर्ण सूचना चाही थी । प्राप्त सूचना को श्री मोहन चंद्र सती ने हम सभी के साथ सांझा किया । सिंचाई विभाग द्वारा प्रदान की गई सूचना में कई निराधार, तथ्यहीन व सिंचाई विभाग के अधिकारियों व ठेकेदारों की मिलीभगत से लाखों रूपये के फ़र्ज़ी बिलों से हेरा फेरी की चौंकाने वाली सूचनायें सामने आयी ।
2. सिगड्डी नहर के नाम पर सिंचाई विभाग ने पिछले एक दशक से कर दाताओं की मेहनत की कमाई से संचित सार्वजनिक निधि के लाखों/करोड़ों रुपयों का दुरपयोग किया है । बजटीय आबंटन से आबंटित धन राशि का विभागीय अधिकारियों एवं ठेकेदारों ने मिलीभगत से लगातार समायोजन किया । इसके विपरीत पिछले 10 वर्षों में धरातल पर किये गये कार्य शून्य हैं । विभाग के भ्रष्ट एवं उदासीन रवैये के कारण आज सिगड्डी नहर की क्षमता शून्य हो चुकी है। इसी की वजह से आज भी मालन नदी से आने वाले सिंचाई हेतु उपयोगी पानी को सिडकुल के नाले के रास्ते सिगड्डी सोत में बहा दिया जाता है ।

6

3. इसी प्रकरण में श्री मोहन चंद्र सती द्वारा प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जाने वाली अपील व संलग्नित ज्ञापन / प्रमाणपत्र के समर्थन में हम सभी कृषकगण अपने हस्ताक्षर करते हैं। पुनः इस तथ्य को दोहराते हैं कि अपील व ज्ञापन/ प्रमाणपत्र की अंतर्वस्तु को हमारी जानकारी व सहयोग से तैय्यार किया गया है। अंतर्वस्तु के प्रत्येक शब्द व वाक्य को हम सभी ने पढ़ा है, सुना है, जाना है और समझा है, जो कि धरातल पर मौजूद परिस्थितियों के अनुसार बिलकुल सत्य है।

जनहित में महोदय से अनुरोध है कि उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर प्रस्तुत प्रकरण की तुरंत प्रभाव से उच्च स्तरीय जांच के आदेश पारित किये जायें। जांचोपरांत, गत 9 - 10 वर्षों से सिगड्डी नहर की साफ़ सफाई व मरम्मत से जुड़े भ्रष्टाचार के इस खेल में लिप्त ठेकेदारों को चिन्हित करके, उन्हें काली सूची में डालते हुए इनके लाइसेंस रद्द किये जायें। इसके अलावा, इस प्रकरण में पाये गये भ्रष्ट कर्मचारियों व ठेकेदारों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करते हुए पिछले 8 - 9 वर्षों में दुरपयोग की गई सार्वजनिक निधि से आबंटित राशि की पुनर्प्राप्ति करके सिगड्डी नहर की सफाई व मरम्मत की जाये । जिससे मालन नदी व सिगड्डी सोत के प्राकृतिक स्रोतों में उपलब्ध पानी को राष्ट्रहित व जनहित में सिंचाई हेतु इस क्षेत्र के अंतिम किसान तक पहुँचाया जा सके।

प्रार्थीगण

संलग्नित सूचियों में हस्ताक्षर करने वाले कृषकगण, परिवारजन व अन्य सभी प्रभावित क्षेत्रीय कृषकगण

दिनांक : 11.10.2020

संलग्नक : प्रार्थीगणों के हस्ताक्षरों की सूचियां (संख्या - 4)

मूलप्रति

R

125

मोहन चंद्र सती पुत्र श्री बाला दत्त सती एवं समस्त अधोहस्ताक्षरित ग्रामीण

ग्राम - मनदवेपुर, पो0 ऑ0 लोकमणीपुर,

पट्टी - हन्दूखाता तहसील - कोटद्वारा,

जिला - पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखंड - 246149

मोबाइल - 9811390718, Email- chandramohansati@yahoo.co.in

प्रधान मंत्री कार्यालय
PRIME MINISTER'S OFFICE
13 JUL 2021
डाक अनुभाग / DAK SECTION

96
CS(UK)

03.07.2021

दिनांक - ~~.......06.2021~~

पत्र व्यवहार का पता:-

मोहन चंद्र सती, अधिवक्ता, दिल्ली उच्च न्यायालय

चैम्बर न0 203, सिविल विंग, तीस हज़ारी कोर्ट दिल्ली - 110054

सेवा में,

1. माननीय, श्रीमान प्रधान मंत्री महोदय
प्रधान मंत्री कार्यालय,
साउथ ब्लॉक, रायसीना हिल, नयी दिल्ली – 11011
Email Address - indiaportal@gov.in connect@mygov.nic.in

2. माननीय मुख्य सचिव महोदय,
उत्तराखंड सरकार,
4-सुभाष रोड, उत्तराखंड सचिवालय देहरादून उत्तराखंड -248001
cs-uttaranchal@nic.in

3. श्रीमान प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, उत्तराखंड सरकार, 85 - राजपुर रोड, देहरादून, उत्तराखंड - 248001 Email Address ltgc-forest-uk@nic.in

4. श्रीमान जे0 एस0 सुहाग, महोदय
चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन, उत्तराखण्ड, 85 - राजपुर रोड, देहरादून, उत्तराखंड - 248001, Email- cwlwua@yahoo.co.in

5. श्रीमान प्रभागीय वनाधिकारी, लैंसडौन वन प्रभाग, कोटद्वार,
जिला - पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड - 246149

जगदीश सिंह
पार्षद
वार्ड नं० 36 लोकमणिपुर

विषय: लैन्सडौन वन प्रभाग कोटद्वार के अंतर्गत सिगड्डी भाबर क्षेत्र में आरक्षित वन

क्षेत्र राजाजी नेशनल पार्क के वन पर्यावरण, वन्य प्राणी, ग्रामीणों की खेती व मवेशियों की जान की सुरक्षा हेतु सिंबलखाल से सिडकुल की बॉउंड्री दीवार तक लगातार जमीन की सतह से 9 फुट ऊँची, जमीन की सतह से 3 फुट गहरी एवं 2 फुट चौडी गेटरहित गुणवत्तापूर्ण सुरक्षा दीवार के अविलम्ब निर्माण के लिए ग्रामीणों का प्रार्थना पत्र

महोदय /महोदया,

उपरोक्त विषयक, अधोहस्ताक्षरित ग्रामीण सुरक्षा दीवार का अविलम्ब निर्माण कार्य प्रारम्भ करने हेतु अपना पक्ष निम्नतः रखते हैं :-

1. वन विभाग की जान बुझ कर अनदेखी के कारण वन सम्पदा व ग्रामीण किसानों की जान माल एवं खेती की सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इस सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य वर्षों से लंबित है। आरक्षित वन क्षेत्र में इको सेंसिटिव जोन के अंतर्गत सिगड्डी सौत से रेत, बजरी, पत्थर एवं वनों की सम्पदा की अवैध निकासी से लगातार अनुचित लाभ पाने के लिए विभाग के भ्रष्ट अधिकारीगण इस सुरक्षा दीवार का निर्माण नहीं करवाते।

2. विगत माहों में वन्य प्राणियों द्वारा ग्रामीणों की फसलों के अत्यधिक नुकसान की शिकायत पर, अस्थायी हल के तौर पर कुछ जगहों पर वन विभाग ने सिम्बलखाल से सिडकुल की बॉउंड्री तक खाई खुदवाई है, जो कि वन्य प्राणियों एवं क्षेत्रवासियों के मवेशियों के लिए मौत की खाई सिद्ध हो रही है।

3. निहित स्वार्थों को साधने के उद्देश्य को लेकर विभागीय अधिकारीयों द्वारा जान बुझ कर सुरक्षा दीवार निर्माण की अनदेखी की कीमत आरक्षित वन क्षेत्र के बेजुबान वन्य प्राणियों, ग्रामीणों एवं उनके मवेशियों को चुकानी पड़ रही है। विगत महीनों में सिगड्डी एवं झंडीचौड़ में दो हाथियों की मौत, क्षेत्र में चार ग्रामीणों की हाथियों द्वारा मौत व ग्रामीणों के मवेशियों की वन क्षेत्र में घुसने पर मौतें, विभागीय अकर्मण्यता का परिणाम है। हाथियों के मौत के आरोप में दो व्यक्ति एवं उनके परिवार बर्बाद हो गए हैं। दोनों आरोपी जेल में हैं, बचाव के लिए कानूनी प्रक्रिया में दोनों गरीब ग्रामीणों की जमीनें बिक गयी हैं।

4. प्राकृतिक संसाधनों के अवैध दोहन के लिए वन माफिआओं व खनन माफिआओं की गोद में बैठा हुआ वन विभाग उपरोक्त ह्रदय विदारक दुर्घटनाओं से बिलकुल भी विचलित नहीं होता। सिगड्डी भाबर क्षेत्र के पीड़ित स्थानीय ग्रामीणों ने दक्षिण दिशा

में ग्राम गंदरियाखाल क्षेत्र से जुड़े वन क्षेत्र एवं उत्तर दिशा में जुड़े वन क्षेत्र में दशकों पूर्व दोनों सुरक्षा दीवारों के निर्माण की मांग एक ही साथ उठाई थी। ग्राम गंदरियाखाल की सुरक्षा दीवार का निर्माण तो उसी वक्त हो गया परन्तु वन सम्पदा एवं खनन बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण उत्तर दिशा वन क्षेत्र की ओर सिंबलखाल से सिडकुल बॉउंड्री तक की सुरक्षा दीवार के निर्माण को वन विभाग के अधिकारियों ने अपने निहित स्वार्थों के लिए जान बूझ कर वन माफिआओं व खनन माफिआओं के अनुचित प्रभाव से रोक कर रखा हुआ है।

5. दिनांक 25 -08-2020 को श्री मोहन चंद्र सती जी, अधिवक्ता दिल्ली उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में समाज सेवी, श्री गणेश चंद्र जोशी जी (जयदेवपुर) के निवास स्थान पर क्षेत्र की ज्वलंत समस्याओं की सुनवाई के लिए एक बैठक आयोजित हुई। बैठक के मुख्य अतिथि कैबिनेट एवं वन मंत्री श्री डा० हरक सिंह रावत को क्षेत्रवासियों ने एक सामूहिक ज्ञापन के माध्यम से उपरोक्त सुरक्षा दीवार के अविलम्ब निर्माण की आवश्यकता की मांग को रखा। (प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि संलग्नित है।)

6. इसी क्रम में माननीय वन मंत्री महोदय ने जनहित एवं वन्यपर्यावरण हित में ग्रामीणों की उपरोक्त समस्या को गंभीरता से लेते हुए सिम्बलखाल से लगातार सिडकुल की बॉउंड्री तक जमीन की सतह से 9 फुट ऊँची, जमीन की सतह से 3 फुट गहरी एवं 2 फुट चौड़ी गेटरहित गुणवत्तापूर्ण सुरक्षा दीवार के अविलम्ब निर्माण कार्य को स्वीकृत एवं प्रारम्भ करवाने के आश्वासन भी दिए थे।

7. समाजसेवी एवं पर्यावरणविद श्री देवेंदर सिंह की जनहित याचिका, देवेंदर सिंह बनाम उत्तराखंड सरकार एवं अन्य में माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल ने माननीय सर्वोच्च न्यायलय के आरक्षित वन क्षेत्र एवं इको सेंसिटिव जोन से संबंधित दिशा निर्देशों, के आधार पर आरक्षित वन क्षेत्र से 10 किलोमीटर की दुरी के अंदर किसी भी प्रकार की प्रदूषणकारक गतिविधि को प्रतिबंधित करते हुए याचिकाकर्ता के पक्ष में अंतरिम आदेश पारित किये हैं। समस्त प्रेषितियों की जानकारी हेतु माननीय उच्च न्यायालय की दो प्रासंगिक कार्यवाही का अंग्रेजी विवरण निम्नतः है :-

(I) IN THE HIGH COURT OF UTTARAKHAND AT NAINITAL

Writ Petition (PIL) No. 168 of 2019

Devendra Singh Adhikari ....Petitioner

Vs.

State of Uttarakhand and others ....Respondents

'Presents:- Mr. V.K. Shukla, learned Advocate for the petitioner.

Date:- 17th October, 2019

Coram: Hon'ble Ramesh Ranganathan, C.J. Hon'ble Alok Kumar Verma, J.

Ramesh Ranganathan, C.J. (Oral)

1. Mr. V.K. Shukla, learned counsel for the petitioner, would submit that location of Stone Crusher Units within 10 kms of the territorial limits of the reserve forest is prohibited in terms of the law laid down by the Supreme Court; and the 5th respondent is running the Stone Crusher Unit, located within 10 Km distance from the reserve forest, throughout the night which is impermissible.

2. Mr. Pradeep Joshi, learned Standing Counsel, would submit, on instructions, that the Stone Crusher Unit is functioning as per norms; and the fifth-respondent/Stone Crusher Unit is located within 6.4 kms through the aerial route, from the limits of the Rajaji National Park, but is located at a distance of 13 kms by road.

3. It is not in dispute that no Stone Crusher Unit can be operated at night. The District Magistrate, Pauri Garhwal, shall, therefore, take necessary steps to ensure that the fifthrespondent/Stone Crusher Unit does not carry on operations at night, pending further order from this Court. 2

4. Since no order can be passed behind the back of the fifth-respondent. Mr. V.K. Shukla, learned counsel for the petitioner, is permitted to take out notice on respondent Nos.5 and 6, by registered post acknowledgment due, and by dasti, and to file proof of service within two weeks.

5. Mr. Pradeep Joshi, learned Standing Counsel, takes notice on behalf of the State of Uttarakhand / respondent Nos.1, 2 and 4. Ms. Neetu Singh, learned Standing Counsel, takes notice for the

3rd respondent. Both of them seek two weeks' time to file their respective counter affidavits.

6. List this Writ Petition "for admission" in the daily list on 04.11.2019.

(Alok Kumar Verma, J.) (Ramesh Ranganathan, CJ.)

17.10.2019

(II) WPPIL No.168 of 2019

Hon'ble Ravi Malimath, A.C.J. Hon'ble R. C. Khulbe, J.

Shri V.K. Shukla, learned counsel for the writ petitioner.

Shri C.S. Rawat, learned additional chief standing counsel for the State/ respondent nos.1,2 and 4.

Shri Vipul Sharma, learned counsel for respondent nos.5 and 6.

Shri C.S. Rawat, learned additional chief standing counsel appearing for the State/respondent nos.1,2 and 4, submits that subsequent to the order passed by the second respondent, the stone crusher unit of respondent no.6 is closed. On a specific question being re-asked, Shri Rawat reiterates that the stone crusher unit is physically closed. The submission made by him is placed on record. Learned counsel for respondent nos.5 and 6 submits that on fulfilling certain conditions, he will be entitled to re-open the stone crusher unit.

On hearing him, we are of the considered view that even if he fulfills the conditions, as mentioned by the respondent-State, the stone crusher unit shall not be allowed to operate until and unless permitted by this Court.

Call after two weeks.

(R.C. Khulbe, J.) (Ravi Malimath) A.C.J.

09.10.2020"

उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायहित में वन्यपर्यावरण एवं ग्रामीणों के हितों के सुरक्षा करते हुए निम्नांकित अनुतोष प्रदान करने की कृपा की जाए:-

a) सिम्बलखाल से लगातार सिडकुल की बॉउंड्री तक जमीन की सतह से 9 फुट ऊँची, जमीन की सतह से 3 फुट गहरी एवं 2 फुट चौड़ी गेटरहित गुणवत्तापूर्ण सुरक्षा दीवार के अविलम्ब निर्माण की स्वीकृत एवं निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाए।

b) विभाग द्वाराकम से कम दश वर्षों की निर्दिष्ट अवधि के लिए निष्पादित कार्य दायी एजेंसियों/ठेकेदारों की दोष देनदारियों के घटक को शामिल करते हुए, गुणवत्तापूर्ण सुरक्षा दीवार के अविलम्ब निर्माण की स्वीकृति सुनिश्चित की जाये, जिससे वन पर्यावरण, ग्रामीणों के हित एवं सार्वजनिक निधि के सदुपयोग सुरक्षित सुनिश्चित हों।

c) सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य प्रारम्भ होते ही, वन्य प्राणियों द्वारा ग्रामीणों की फसलों के अत्यधिक नुकसान की शिकायत पर, अस्थायी हल के तौर पर कुछ जगहों पर वन विभाग द्वारा सिम्बलखाल से सिडकुल की बॉउंड्री तक खोदी गयी खाई, जो कि वन्य प्राणियों एवं क्षेत्रवासियों के मवेशियों के लिए मौत की खाई सिद्ध हो रही है, को बंद किया जाये।

d) माननीय सर्वोच्च न्यायलय के आरक्षित वन क्षेत्र एवं इको सेंसिटिव जोन से संबंधित दिशा निर्देशों, के आधार पर आरक्षित वन क्षेत्र से 10 किलोमीटर की दुरी के अंदर किसी भी प्रकार की प्रदूषणकारक गतिविधि को प्रतिबंधित करते हुए उपरोक्त याचिकाकर्ता के पक्ष में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों (संदर्भ ज्ञापन के बिंदु 7, I व II) का सम्मान करते हुए प्रतिबंधित क्षेत्र में जैव विविधता व वन्यपर्यावरण, को क्षति पहुँचाने वाली खनन गतिविधियों, खनन भंडारण को स्वीकृति प्रदान न की जाए तथा पूर्व में प्रदान स्वीकृतियों को तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाए।

प्रार्थीगण – मोहनचन्द्रभट्ट

सिगड्डी भाबर क्षेत्र के समस्त पीड़ित किसान व उनके आश्रितजन।

प्रतिलिपि:-

1) माननीय केंद्रीय मंत्री, श्रीमान प्रकाश जावड़ेकर महोदयपर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय पांचवा तल, वायु विंग इंदिरा पर्यावरण भवन जोर बाग,नयी दिल्ली-110003

Email Address- moef@gov.in

2) माननीय मुख्य मंत्री महोदय, उत्तराखंड सरकार,
4-सुभाषरोड,उत्तराखं सचिवालय, देहरादून उत्तराखंड
cm-ua@nic.in

3) श्रीमान डा0 हरक सिंह रावत, माननीय वन मंत्री, उत्तराखंड सरकार
उत्तराखंड सचिवालय, 4 - सुभाष रोड, देहरादून, उत्तराखंड 248001

4) इंस्पेक्टर जनरल ऑफ़ फारेस्ट, बी-1 विंग, 7th फ्लोर,
पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन,
CGO काम्प्लेक्स लोधी रोड नई दिल्ली -110003
Email Address- ig-ntca@nic.in

संलग्नक:-

a) प्रस्तुत ज्ञापन के समर्थन में पीड़ित क्षेत्रवासियों के हस्ताक्षरों की सूचियाँ।
(12 पृष्ठों में 219 हस्ताक्षरकर्ताओं की सूचियां) – मूलप्रतियां।

b) ग्रामीणों द्वारा माननीय वन मंत्री/ क्षेत्रीय विधायक को 25.08.2020 सुरक्षा दीवार बनवाने हेतु सौंपा गया प्रार्थना पत्र।

महोदय,
सभी प्रेषितियों को प्रस्तुत ज्ञापन ई-मेल द्वारा भी भेजा गया है।

सुरक्षा दीवार निर्माण के लिए प्रार्थना पत्र के समर्थन में

प्रार्थीगणों के हस्ताक्षर की सूचि

(1)

क्र० सं०	प्रार्थीगण	पिता का नाम	ग्राम	मोबाइल नं०	हस्ताक्षर
1-	Mohan Chandra Sati	Sh Bala Dutt Sati	Mandarpur	9811390718	[signature]
2-	Devendra Singh Adhikari	Sh. Ranjeet S. Adhikari	Dalippur, Ward No. 36	98875-69323	[signature]
3.	भावना देवी	देव सिंह	"	7668154149	Bhawna
4-	रणजीत सिंह	[illegible] सिंह	दलीपपुर	9837270553	[signature]
5-	[illegible]	[illegible]	दलीपपुर	7016637986	[signature]
6-	[illegible] देवी	श्री [illegible]	दलीपपुर	801692451	[signature]
7-	हरेन्द्र सिंह	[illegible] सिंह	दलीपपुर	9870918040	[signature]
8-	महिपाल सिंह	[illegible] सिंह	दलीपपुर	9927019188	[signature]
9	चन्दन सिंह	[illegible] सिंह	दलीपपुर	9927435582	चन्दन सिंह
10	Deepak Mehra	Mr H.S Mehra	Bhawanipur	8630193546	Deepak
11	[illegible] सिंह	स्व. [illegible] सिंह	दलीपपुर	—	[signature]
12	[illegible] सिंह	श्री [illegible] सिंह	"	9568528005	[signature]
13	[signature]	[illegible] सिंह	दलीपपुर	—	[signature]
14	[illegible] सिंह	[illegible]	"	—	[signature]
15	Mohabbat Singh	[illegible] सिंह	"	—	[signature]
16	Balam Singh	Dewan Singh	"	9837137804	[signature]
17	नरेन्द्र मेहरा	रामसिंह	"		[signature]
18	नीमा बिष्ट	[illegible]	"	9012789478	[signature]
19	[illegible] मेहरा	हरेन्द्र	"	[illegible]	[signature]

PTO

GRIEVANCE STATUS

मोबाइल नंबर	9643846090	शिकायत क्रमांक :	213595

GRIEVANCE AMENDMENT

मोबाइल नंबर	मोबाइल नंबर	शिकायत क्रमांक :	शिकायत क्रमांक

सी.एम. हेल्पलाइन - शिकायत विवरणी

[illegible]

शिकायत क्रमांक	213595 दिनांक - 26-07-2021
शिकायत का प्रकार	[illegible]
शिकायत कर्ता का नाम	MOHAN CHANDRA SATI
पता	Mandavpur, Ward No. 36 Kotdwar
मोबाइल न.	9643846090, 9811350718
जिला	पौड़ी गढ़वाल
क्षेत्र	[illegible]
शिकायत का कारण	[illegible]
शिकायत का विवरण	[illegible]
निस्तारण	[illegible]
शिकायत की स्थिति	[illegible]
संलग्नक	Download

प्रिंट करें

शिकायत की स्थिति

दिनांक	शिकायत की स्थिति
30 Jul 2021	[illegible]
28 Jul 2021	[illegible]
28 Jul 2021	[illegible]
26 Jul 2021	[illegible]
26 Jul 2021	[illegible]

[illegible]

© 2021 CMHELPLINE UTTARAKHAND | [illegible]

GRIEVANCE STATUS

[illegible]	9643846090	शिकायत क्रमांक :	213595

GRIEVANCE AMENDMENT

सी.एम. हेल्पलाइन - शिकायत विवरणी

शिकायत क्रमांक	213595 दिनांक - 26-07-2021
[illegible]	[illegible]
शिकायत कर्ता का नाम	MOHAN CHANDRA SATI
पता	Mandanpur, Ward No. 36 Kotdwar
फोन न.	9643846090, 9811390718
जिला	पौड़ी गढ़वाल
क्षेत्र	[illegible]
शिकायत का सम्बन्ध	[illegible]
शिकायत का विवरण	[illegible]
शिकायत की स्थिति	[illegible]
संलग्नक	Download Download Download Download

शिकायत की स्थिति

दिनांक	शिकायत की स्थिति
19 Aug 2021	[illegible]
19 Aug 2021	[illegible]
19 Aug 2021	[illegible]
19 Aug 2021	[illegible] 97.28 [illegible]
11 Aug 2021	[illegible]
11 Aug 2021	[illegible]
07 Aug 2021	[illegible]
07 Aug 2021	[illegible] 97.28 [illegible]
30 Jul 2021	[illegible]
30 Jul 2021	[illegible]
30 Jul 2021	[illegible]
28 Jul 2021	[illegible]
28 Jul 2021	[illegible] 97.28 [illegible]
28 Jul 2021	[illegible]
26 Jul 2021	[illegible]

प्रार्थीगण-

मोहन चंद्र सती, अधिवक्ता दिल्ली उच्च न्यायालय,
चैम्बर न० 203, सिविल विंग, तीस हज़ारी कोर्ट, दिल्ली - 110054
एवं संलग्नित हस्ताक्षरित सूचि में कोटद्वार भाबर क्षेत्र व उत्तराखंड राज्य के क्षेत्रवासी

मूल निवासी - ग्राम मनदेवपुर, पो०ऑ० लोकमणीपुर, पट्टी - हल्दूखाता, तहसील कोटद्वार, जिला- पौड़ी गढ़वाल उत्तराखण्ड - 246149
सम्पर्क सूत्र - 9811390718
Email- chandramohansati@yahoo.co.in
दिनांक - 05.03.2021

सेवा में,

1. माननीय, श्रीमान प्रधान मंत्री महोदय
   प्रधान मंत्री कार्यालय,
   साउथ ब्लॉक, रायसीना हिल, नयी दिल्ली - 11011
   Email Address - indiaportal@gov.in connect@mygov.nic.in

2. माननीय मुख्य सचिव महोदय,
   उत्तराखंड सरकार,
   4-सुभाष रोड, उत्तराखंड सचिवालय देहरादून उत्तराखंड -248001
   cs-uttaranchal@nic.in

विषय- कोटद्वार भाबर क्षेत्र के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग दुगड्डा एवं वन विभाग कोटद्वार द्वारा 11 कि0 मी0 लम्बाई के लालढांग - चिलरखाल मोटर मार्ग पर पक्का /ऑल वेदर रोड निर्माण हेतु गत बारह वर्षों में क्रमशः 26.20 करोड़ एवं विस्तृत व पुनरीक्षित विस्तृत आगणन में 46.71 करोड़ रूपये (कुल 72.91 करोड़ रूपये) खर्च / परियोजना की कुल लागत के बावजूद भी मोटर मार्ग की हालत कच्चा एवं जस की तस होने के सम्बन्ध में

माननीय महोदय,

उपरोक्त विषयक, प्रार्थी एवं संलग्नित हस्ताक्षरित सूचि में कोटद्वार भाबर क्षेत्र व समस्त उत्तराखण्ड के क्षेत्रवासी, जनहितार्थ निम्नतः प्रार्थना करते हैं :-

1. उत्तराखण्ड राज्य की सीमा के अन्तर्गत राज्य की राजधानी देहरादून को धर्म नगरी हरिद्वार से होते हुए कोटद्वार, कालागढ़ एवं कुमाऊं क्षेत्र के रामनगर, हल्द्वानी, रुद्रपुर, नैनीताल इत्यादि शहरों से जोड़ने वाले एक मात्र मोटर मार्ग का निर्माण दशकों से लम्बित चल रहा है। क्षेत्रवासियों के लिए इस मोटर मार्ग की महत्वपूर्ण उपयोगिता एवं देहरादून व हरिद्वार से अनुयोजिकता के कारण यह मोटर मार्ग ब्रिटिश शासनकाल से अस्तित्व में है। क्षेत्रवासियों की जानकारी एवं प्रार्थीगणों के पास उपलब्ध अभिलेखों के अनुसार प्रश्नगत वन मोटर मार्ग वर्ष 1970 - 80

में पूर्ण रूप से डामरीकृत था। आज की तिथि में केवल उपयुक्त मौसमानुसार ही इस कच्चे मार्ग पर सुचारु रूप से आवा जावी सम्भव है।

2. महोदय उत्तराखण्ड राज्य के पुनर्गठन के बाद व उससे पहले से ही यह मोटर मार्ग हमेशा चुनावी मुद्दा बना रहा। लोक निर्माण विभाग एवं वन विभाग उत्तराखण्ड द्वारा प्रार्थी को दी गयी प्रमाणित जानकारी के अनुसार गत 12 वर्षों में लोक निर्माण विभाग को इस मोटर मार्ग के पक्का /आल वैदर निर्माण हेतु 26.20 करोड़ रुपयों का अनुदान प्राप्त हुआ है और इसी राशि का पूर्ण रूप से व्यय भी हुआ है। इसी क्रम में लोक सूचना अधिकारी, प्रिंसिपल चीफ कंजर्वेटर, पर्यावरण एवं वन विभाग कार्यालय से पूछी गयी सूचना के उत्तर में प्रभागीय वनाधिकारी, लैंसडौन वन प्रभाग कोटद्वार द्वारा दी गयी सूचना में विस्तृत आगणन एवं पुनरीक्षित विस्तृत आगणन के अभिलेखों में इसी परियोजना की कुल लागत 46.71 बताई गयी है । विगत वर्षों में राजनितिक - शासन प्रशासन भ्रष्ट गठजोड़ से करोड़ों रुपयों की धनराशि के समायोजन हेतु इस मोटर मार्ग पर अनुदान प्राप्त करने व उस राशि को व्यय दिखाने हेतु न्यायालय / विभागीय आपत्तियों /अनापत्तियों का सिलसिला लगातार चलता रहता है, लेकिन आम जनहित के इस महत्वपूर्ण कार्य को जान बुझ कर पूरा नहीं किया जाता और आज भी यह मोटर मार्ग पूर्णतः कच्चा है।

3. आज दिन तक इस कच्चे मोटर मार्ग पर मोटर वाहनों की आवा जावी सुचारु रखने हेतु यथास्थिति बनाये रखने के लिए, सिगड्डी सोत नदी व महली सोत नदी से उठाये गए पत्थरों, आर0 बी0 एम0 व मिट्टि से प्रति वर्ष थोड़ा बहुत कार्य होता रहा है । यदि धरातल पर इस आंशिक कार्य का आंकलन ईमानदारी व पारदर्शिता से हो, तो किन्हीं भी

परिस्थितियों में इस कार्य पर कुल व्यय राशि की लागत लो0 नि0 वि0 तथा वन विभाग द्वारा अभिलेखों में दिखाए गए करोड़ों रुपयों की व्यय राशि का लगभग सूक्ष्म प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता।

4. उत्तराखण्ड राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने, प्रदेश के प्रमुख नगरों में समस्त नागरिकों की सुगम आवा जावी एवं राज्य के सर्वांगीण विकास में मील का पत्थर साबित होने वाले इस मोटर मार्ग का विगत वर्षों में पक्का/आल वैदर निर्माण न होने में केंद्र व राज्य सरकार में अलग -अलग राजनितिक दलों की सरकारें होने के कारण सामन्जस्य का अभाव भी रहा ।
5. गढ़वाल एवं कुमाऊं क्षेत्र के क्षेत्रवासियों के विकास के लिए इस मोटर मार्ग का निर्माण इसलिए भी नितांत आवश्यक है, क्योंकि इस मार्ग के पक्का /आल वैदर मार्ग निर्माण से उत्तराखण्ड के विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों (सिडकुल) जैसे देहरादून सेलाकुई, हरिद्वार, सिगड्डी कोटद्वार एवं रुद्रपुर में राज्य के अंदर ही सीधे तौर पर पारस्परिक अनुयोजिकता स्थापित हो जायेगी। इस आल वैदर मोटर मार्ग की महत्वपूर्ण अनुयोजिकता के स्थापित होने से सिडकुल की विभिन्न बीमार औद्योगिक ईकाइयों को बल मिलेगा और उत्तराखण्ड के लाखों युवाओं के लिए और अधिक रोज़गार के अवसर पैदा होंगे, जो कि हमारे माननीय यशस्वी प्रधान मंत्री के उत्तराखण्ड राज्य के सर्वांगीण विकास हेतु अथक प्रयासों के लिए और अधिक ऊर्जा प्रदान करेगा।

उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों व लोक निर्माण एवं वन विभाग द्वारा मोटर मार्ग निर्माण से संबन्धित अनुदान व व्यय की दी गयी प्रमाणिक सूचना का संज्ञान लेते हुए महोदय से विनम्र निवदेन है कि:-

a. जनहित में शीघ्रातिशीघ्र क्षेत्रवासियों के सर्वांगीण विकास हेतु लालढांग - चिलरखाल मोटर मार्ग का पक्का /आल वैदर उपयोगिता के लिए निर्माण पूरा करवाने की कृपा करें।

b. इस मोटर मार्ग निर्माण के प्रथम चरण में सिगड्डी सोत व महली सोत में पुलों के निर्माण को प्राथमिकता न देकर 11 किलो मीटर मोटर मार्ग पर सर्व प्रथम गुणवत्ता पूर्ण डामरीकरण करवाने की कृपा करें तथा उक्त दोनों बरसाती नदियों में गुणवत्ता पूर्ण रपटा बनवाकर दशकों से इंतज़ार कर रही प्रदेश की जनता की सुगम आवा जावी सुनिश्चित करने की कृपा करें ।

c. द्वितीय चरण में, सिगड्डी सोत नदी एवं महली सोत के ऊपर विवेकहीन, अनुभवहीन, तर्कहीन एवं विशेषज्ञताहीन डिज़ाइन से पुलों के निर्माण को तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जाए । भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सिगड्डी सोत एवं महली सोत पर पुलों का निर्माण कोटद्वार - सिगड्डी के बीच मालन एवं सुखरौ नदी के ऊपर बने हुए पुलों की तर्ज़ पर किया जाए। इस परियोजना के लिए "राज्य राजमार्गों के एक / दो लेन के लिए निर्धारित मानक और विशिष्टताओं के मैनुअल: एसपी :73 (आई0 आर0 सी0 2007)" डिजाइन मानकों का अनुपालन किया जाए। इसके अलावा उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा अधिसूचित विशिष्टताएं डिजाइन मानक, "सड़क और पुल कार्य के लिए विनिर्देश" और विभिन्न प्रासंगिक आई0 आर0 सी0 मानक और बी0 आई0 एस0 मानकों का पूर्ण रूप से अनुपालन की अनिवार्यता सुनिश्चित की जाए ।

d. मोटर मार्ग निर्माण में लोक निर्माण व वन विभाग द्वारा कुल व्यय राशि एवं धरातल पर किये गए सड़क निर्माण का भौतिक सत्यापन करने के बाद तुलनात्मक समीक्षा एवं उच्च स्तरीय जांच करवाने की कृपा करें।

e. विषयक मोटर मार्ग निर्माण की कार्यवाही की सच्चाई और निष्क्रियता की सच्चाई की समीक्षा एवं उच्च स्तरीय जांच में यदि अनियमितताएं पाई गयीं तो धन का कपटपूर्ण विनियोग करने वाले उत्तरदायी विभागीय अधिकारियों/कर्मियों एवं संबंधित राजनितिक सेवकों को चिन्हित करके, उन पर अनुशासनिक कार्यवाही करते हुए दुरपयोग / गबन किये गए पब्लिक फण्ड की पुनर्प्राप्ति की प्रक्रिया शुरू करने की कृपा की जाए।

प्रार्थीगण:-

—

सलग्नित हस्ताक्षरों की सूचि अनुसार

प्रतिलिपि-

1. श्रीमान नितिन गडकरी
   माननीय केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री,
   रूम न0 501, परिवहन भवन, संसद मार्ग नई दिल्ली - 110001
   Email Address- nitin.gadkari@nic.in
2. माननीय केंद्रीय मंत्री, श्रीमान प्रकाश जावड़ेकर महोदय,
   पर्यावरण,वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
   पांचवा तल, वायु विंग इंदिरा पर्यावरण भवन जोर बाग़, नयी दिल्ली
   Email Address- moef@gov.in
3. माननीय, श्रीमान अध्यक्ष महोदय,

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT)
फरीदकोट हाउस, कोपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली - 110001
Email Address- rg.ngt@nic.in ngtpb.pg@gmail.com

4. माननीय मुख्य मंत्री महोदय,
उत्तराखंड सरकार,
4 - सुभाष रोड, उत्तराखंड सचिवालय, देहरादून उत्तराखंड -248001
cm-ua@nic.in

5. श्री अनिल बलूनी, माननीय सांसद, राज्य सभा
बंगला न0 20 , गुरुद्वारा रकाबगंज रोड, नई दिल्ली -1
Email Address - anil.baluni@sansad.nic.in

6. इंस्पेक्टर जनरल ऑफ़ फारेस्ट,
बी.-1 विंग, 7th फ्लोर, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन,
CGO काम्प्लेक्स लोधी रोड नई दिल्ली -110003
Email Address- ig-ntca@nic.in

7. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन विभाग, उत्तराखंड सरकार,
85 - राजपुर रोड, देहरादून, उत्तराखंड - 248001
Email Address **itgc-forest-uk@nic.in**

संलग्नक -

a. लोक सुचना अधिकारी, कार्यालय अधिशासी अभियंता, निर्माण खण्ड, लो0 नि0 वि0 दुगड्डा (गढ़वाल) द्वारा गत 12 वर्षों में मोटर मार्ग निर्माण हेतु अनुदान प्राप्त एवं व्यय राशि के बारे में दी गयी आधिकारिक सूचना।

b. लोक सुचना अधिकारी, कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, लैंसडौन वन प्रभाग, कोटद्वार द्वारा गत 12 वर्षों में मोटर मार्ग निर्माण हेतु अनुदान प्राप्त एवं व्यय राशि के बारे में दी गयी आधिकारिक सूचना।

कोटद्वार भाबर क्षेत्र, उत्तराखण्ड के 1296 क्षेत्रवासियों की हस्ताक्षरित सूचियां एवं उपरोक्त संलग्नक (a) व (b), सभी प्रेषितियों को भारतीय डाक की रजिस्ट्री सेवा के द्वारा दिनांक 05.03.2021 में भेज दी हैं।

PMOIN/R/E/20/06313
PMOIN/A/E/20/00883
FAA mail recd.: 10.12.2020

RTI File No. : RTI/9174/2020-PMR
Name of the Applicant : Shri Mohan Chandra Sati, Uttarakhand
Date of Application : 15.09.2020

S. No.	Information Sought	Response
	An application in public interest was sent to the Hon'ble PMO on 07 June 2018 through registered post and also through Email at 09:03 PM. In view of the above, the following information is sought:-	As per computerized records of Public Wing of PMO, letter dated 07.06.2018 mentioned in RTI application of the applicant has not been received in this office. However, another letter dated 25.06.2018 of the applicant on the same subject received in PMO on 27.06.2018 has been forwarded for action as appropriate to Chief Secretary, Government of Uttarakhand, Dehradun vide this office registration No. PMOPG/D/2018/0234986 dated 29.06.2018 (copy enclosed). Processing of letters received from Public in Public Wing of PMO is fully computerized and the software does not have any provision for file noting concerning to this office. Redressal of grievance is under the purview of appropriate authority dealing with subject specified. Therefore, information sought relates to the authority concerned to which the complaint was forwarded. The status of action on the petition can be accessed from web portal www.pgportal.gov.in by using above mentioned registration Number.
(a)	Please provide the action taken report at the Hon'ble PMO office, on the request of applicant for the construction of much awaited and needed above road in the interest of general public.	
(b)	Please provide the information about any inter department and inter governmental correspondence in above action taken report.	
(c)	Please provide the total allocated budget by the forest department / PWD / CPWD / PMGSY or by any other source for the construction of this road, year wise for last 15 years, along with year wise complete details of part / complete utilization of the allocated budget.	
(d)	Please provide the information about the DPR(s), if any for this road.	
(e)	Please provide the information about the present status and obstructions pertaining to the construction of the road and probable date of completion of the construction.	
(f)	Please provide the photo copies of all the letters, leaflets, and file notings pertaining to the inter departmental / governmental correspondence in above sought information, point (a) to (e).	

28/12/20

PARVEEN KUMAR
Under Secretary & CPIO
Prime Minister's Office
New Delhi

प्रधान मंत्री कार्यालय

Prime Minister's Office

नई दिल्ली- 110011
New Delhi- 110011
Dated:29/06/2018

No:PMOPG/D/2018/0234986

To

CHIEF SECRETARY,
GOVERNMENT OF UTTARAKHAND,

Sub:Petition of SHRI MOHAN CHANDRA SATI
DELHI HIGH COURT
CHAMBER NO 203 CIVIL WING TIS HAZARI COURT
NEW DELHI
DELHI-110054

Sir,

I am desired to forward herewith a letter/gist of oral representation dated 25/06/2018 received in this office from SHRI MOHAN CHANDRA SATI for action as appropriate. Reply may be sent to the Petitioner and a copy of the same may be uploaded on the portal.

Yours faithfully,

[ALOK SUMAN]
SECTION OFFICER

Copy for information to :
SHRI MOHAN CHANDRA SATI
DELHI HIGH COURT
CHAMBER NO 203 CIVIL WING TIS HAZARI COURT
NEW DELHI
DELHI-110054

Note:- Status of the grievance can be tracked through internet at https://pgportal.gov.in/status after entering registration no. PMOPG/D/2018/0234986

सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत दिए गए दस्तावेज/अभिलेख की सत्यापित प्रति।
... RTI Act

28/12/20

/CPIO
(प्रधान मंत्री कार्यालय/Prime Minister's Office)

Gmail Uttarakhand Budget <uttarakhandbudget@gmail.com>

बजट 2022 - 23 हेतु सुझाव

1 message

dr.nautiyal jayanti prasad <dr.nautiyaljp@gmail.com> Thu, May 5, 2022 at 3:18 PM
To: "uttarakhandbudget@gmail.com" <uttarakhandbudget@gmail.com>

आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी
माननीय मुख्य मंत्री, उत्तराखंड सरकार
आपके अनुरोध पर जनभागीदारी सुनिश्चित करने के लिए मैं बजट हेतु सुझाव संलग्न कर रहा हूं। पावती दीजियेगा,
सादर,

Regards,

Dr. Jayanti Prasad Nautiyal,

Deputy General Manager (Retired)

9900068722

Manojay Bhawan

115, Vishnulok Colony, Tapovan Road

Dehradun,248008, Uttarakhand.

2 attachments

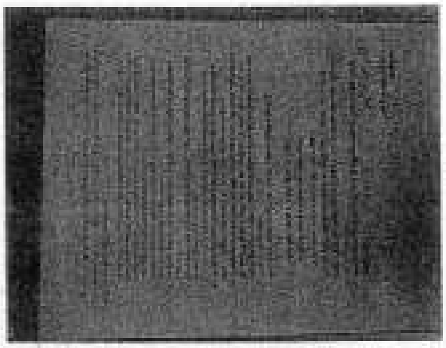

IMG_20220505_151001.jpg
560K

IMG_20220505_150913.jpg
606K

बैंकिंग, वित्तीय शिक्षा एवं शोध का वैश्विक संस्थान, देहरादून
Global Institute of Banking, Financial Education & Research, Dehradun

Dr. [illegible]

- Accredited Resource Person of SEBI

दिनांक Date

दिनांक 5.5.2022

श्री पुष्कर सिंह धामी जी,

माननीय मुख्य मंत्री, उत्तराखंड सरकार

बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय उत्तराखंड सचिवालय

देहरादून, उत्तराखंड

माननीय महोदय

विषय : बजट 2022-23 हेतु सुझाव

सर्वप्रथम मैं [illegible] बजट 2022-23 [illegible]

महोदय, मैं [illegible] (Top Management Grade) [illegible] (World Records) [illegible]

महोदय [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

27/05/2022, 18:24 - Messages and calls are end-to-end encrypted. No one outside of this chat, not even WhatsApp, can read or listen to them. Tap to learn more.
27/05/2022, 18:24 - +91 74095 59011: <Media omitted>

28/04/2022, 12:56 - Messages and calls are end-to-end encrypted. No one outside of this chat, not even WhatsApp, can read or listen to them. Tap to learn more.
28/04/2022, 12:56 - +91 94601 73004: Please specify nursing and pharmacy vacancy budget
Contractual policy ko khatam karo
NHM ka or contractual ka cadre banao
Old pension lagu karo
28/04/2022, 12:56 - +91 94601 73004: Nursing vacancy ke rule regulations banao seniority ka bola tha abhi Tak GO nhi bana
28/04/2022, 12:57 - +91 94601 73004: Vacancy ko complete karne ko guarantee act banao

27/05/2022, 21:25 - Messages and calls are end-to-end encrypted. No one outside of this chat, not even WhatsApp, can read or listen to them. Tap to learn more.
27/05/2022, 21:25 - +91 82187 81306: राज्य के प्रत्येक जिले में अच्छी सुविधाओं वाले पुस्तकालयों के निर्माण के लिए बजट में विशेष प्रावधान होना चाहिए
हरिद्वार जैसे बड़े मैदानी जिले में एक भी पब्लिक लाइब्रेरी नहीं है और जो हैं वें जर्जर अवस्था में हैं.

शिक्षा के क्षेत्र में प्रगति से ही हम अपने उत्तराखंड को प्रगति के रास्ते पर ले जा सकते हैं.

अक्षय शर्मा
रोशनाबाद हरिद्वार

27/05/2022, 21:19 - Messages and calls are end-to-end encrypted. No one outside of this chat, not even WhatsApp, can read or listen to them. Tap to learn more.
27/05/2022, 21:19 - +91 81716 67036: आगामी वित्तीय वर्ष 2022 23 के बजट हेतु मेरे सुझाव निम्न वत हैं -
1. प्रत्येक ब्लॉक में टूरिस्ट डेस्टिनेशन प्वाइंट होना चाहिए तथा उसके लिए बजट में व्यवस्था होनी चाहिए।
2. विभिन्न स्रोतों से पंचायतों को धनराशि प्राप्त होती है जैसे मनरेगा, राज्य वित्त, 15 वा वित्त। परंतु धनराशि के सापेक्ष कार्यों का आवंटन नहीं किया गया है जैसे ग्राम पंचायत भी क्षेत्र पंचायत भी और जिला पंचायत भी एक ही जैसे कार्य करते हैं खड़ंजा निर्माण हो या अन्य निर्माण हो, जबकि ग्राम पंचायत के कार्य क्षेत्र पंचायत के कार्य एवं जिला पंचायत के कार्य भिन्न-भिन्न होने चाहिए तथा उसी के आधार पर धनराशि वितरित होनी चाहिए।
3. उत्तराखंड आपदा की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र है तथा आपदा के समय आपदा पीड़ित व्यक्ति सर्वप्रथम ग्राम प्रधान ब्लाक प्रमुख या जिला पंचायत तक पहुंचता है परंतु वर्तमान में पंचायतों में आपदा के समय आकस्मिक धन की व्यवस्था नहीं है। इस बजट में मुख्यतः ब्लाक प्रमुख एवं जिला पंचायतों को आपदा के समय तत्काल राहत देने के लिए आकस्मिक निधि की व्यवस्था होनी चाहिए।
4. वर्तमान में कई ब्लॉक विधानसभा क्षेत्र के बराबर हैं जबकि ब्लाक प्रमुख के लिए प्रमुख निधि की कोई व्यवस्था नहीं है। इस बजट में प्रमुख निधि की व्यवस्था की जानी चाहिए।

सादर।
डॉ दर्शन दानू।
ब्लॉक प्रमुख देवाल चमोली।
प्रदेश अध्यक्ष प्रमुख संगठन उत्तराखंड

27/05/2022, 20:24 - Messages and calls are end-to-end encrypted. No one outside of this chat, not even WhatsApp, can read or listen to them. Tap to learn more.
27/05/2022, 20:24 - +91 94581 76526: 1. सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं में धनराशि मुहैया कराई जाती है परंतु वह धनराशि संबंधित लाभार्थी तक पहुंचती है या नहीं पहुंचती है इसकी समुचित व्यवस्था नहीं की जाती है जबकि आगामी वित्तीय वर्ष में बजट की व्यवस्था संबंधित मध्य में तभी होनी चाहिए जब पूर्व की धनराशि संबंधित लाभार्थियों को ही पहुंची हो 1
2. मूलभूत आवश्यकताएं चाहे रोटी हो कपड़ा और मकान हो या फिर वर्तमान में गैस सिलेंडर के दाम ऐसी स्थिति में रेट बढ़ने के समय बजट में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि आम आदमी को इसकी मार ना पड़े, आकस्मिक निधि होनी चाहिए 1
3. किसी भी योजना को संपूर्ण रूप से लागू करने के लिए मॉनिटरिंग अति आवश्यक होती है जबकि बजट में मॉनिटरिंग के लिए धनराशि का प्रावधान न्यूनतम होता है जिस कारण योजनाएं सफल नहीं हो पाती 1

सुभाष सिंह
Race course Dehradun.

27/05/2022, 20:21 - Messages and calls are end-to-end encrypted. No one outside of this chat, not even WhatsApp, can read or listen to them. Tap to learn more.

27/05/2022, 20:21 - +91 89792 19119: 1. किसानों की आय दोगुनी करने के लिए अति आवश्यक है कि किसानों द्वारा उत्पादित सामान एवं प्रोडक्ट कि सही समय पर मार्केटिंग हो इसके लिए आवश्यक है कि सरकार को मार्केटिंग के क्षेत्र में आना होगा जिस तरह से वन डिस्टिक वन प्रोडक्ट के माध्यम से सरकार प्रोडक्ट के उत्पादन को प्रमोट कर रही है तथा मार्केटिंग को बढ़ावा दे रही है ठीक उसी प्रकार सभी प्रकार के प्रोडक्टों के लिए भी सरकार को आगे आना होगा तथा मार्केटिंग के लिए धनराशि की व्यवस्था करनी होगी। उत्पादों की बिक्री हेतु राष्ट्रीय कैंटीन, राजकीय कैंटीन, में सामान किसानों से खरीदे जाने की व्यवस्था करनी होगी।

मनीष कुमार

रुड़की, हरिद्वार।

27/05/2022, 20:09 - Messages and calls are end-to-end encrypted. No one outside of this chat, not even WhatsApp, can read or listen to them. Tap to learn more.
27/05/2022, 20:09 - +91 6395 472 602: 1. कृषि में सुधार के लिए मृदा काड को उर्वरक सब्सिडी से जोड़ना चाहिए जिससे उर्वरक सब्सिडी के लिए धनराशि कम की जाए एवं मृदा काड को बढ़ावा देने के लिए धन राशि बढ़ाई जाए।
27/05/2022, 20:12 - +91 6395 472 602: 2. बजट में यह व्यवस्था होनी चाहिए कि किसानों की मांग के अनुसार ही खाद बीज एवं रसायन उपलब्ध कराया जाए उसी के आधार पर धनराशि आहरित की जाए।
27/05/2022, 20:12 - +91 6395 472 602: 3 फसल बीमा को अनिवार्य किया जाए तथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ फसल बीमा को जोड़ा जाए। इससे जहां फसलों की सुरक्षा एवं फसलों के नुकसान में खर्च होने वाली धनराशि बचेगी वहीं बीमा के माध्यम से धनराशि सरकार तक पहुंचेगी।
27/05/2022, 20:13 - +91 6395 472 602: Thanks and with regards
Karan chauhan
Laksar
Haridwar

28/04/2022, 16:17 - Messages and calls are end-to-end encrypted. No one outside of this chat, not even WhatsApp, can read or listen to them. Tap to learn more.
28/04/2022, 16:00 - +91 98026 03763: <Media omitted>
28/04/2022, 16:00 - +91 98026 03763: <Media omitted>
28/04/2022, 16:00 - +91 98026 03763: <Media omitted>
28/04/2022, 16:00 - +91 98026 03763: <Media omitted>
29/04/2022, 18:41 - +91 98026 03763: <Media omitted>
30/04/2022, 08:38 - +91 98026 03763: <Media omitted>
02/05/2022, 07:53 - +91 98026 03763: <Media omitted>
02/05/2022, 07:53 - +91 98026 03763: <Media omitted>
02/05/2022, 07:53 - +91 98026 03763: <Media omitted>
02/05/2022, 07:53 - +91 98026 03763: <Media omitted>
02/05/2022, 07:53 - +91 98026 03763: <Media omitted>
24/05/2022, 08:16 - +91 98026 03763: <Media omitted>
24/05/2022, 08:16 - +91 98026 03763: <Media omitted>
24/05/2022, 08:16 - +91 98026 03763: हरे कृष्ण !

श्री चैतन्य गौड़ीय मठ संस्था भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु जी की शिक्षाओं पर आधारित है। परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण जी की उपासना, सनातन धर्म का प्रचार एवं जन साधारण के आत्म कल्याण हेतु भारत में मठ की २४ शाखाएँ हैं। संस्था के सभी महात्मा बिना जात-पात एवं ऊंच नीच के भेदभाव के भारतीय सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए अनथक प्रयास कर रहे हैं जिसके फलस्वरूप भारत के एवं विदेश के लाखों लोग अपने आत्मकल्याण एवं अन्य जनसाधारण के कल्याण के कार्यों में लगे हैं। हमारे मठ की मायापुर धाम की शाखा में श्रीगुरुदेव जी की स्मृति में ब्रह्मचारी एवं देश विदेश से आने वाले नवयुवकों को सनातन धर्म के प्रचार प्रसार हेतु तैयार करने के लिए प्रशिक्षण केन्द्र निर्माण किया जा रहा है। इस समाधि मन्दिर (प्रशिक्षण केन्द्र) निर्माण कार्य में आर्थिक सेवा प्रदान कर श्रीगुरु एवं भगवान का आशीर्वाद भाजन बन परम मंगल का मार्ग प्रशस्त करें।

SEVA Marble and sand stone cliding seva 1600 /- rupees per sqrft Total Area 40000 sqrft 1. 101 sqrft 161601 2. 125 sqrft 200000 3. 250 sqrft 400000 4. 350 sqrft 560000 500 sqrft 800000

क्यों कि बूंद बूंद से सागर भरता है इसलिए सभी भक्तों से निवेदन है कि अपनी शुभ कमाई से एवं साथ साथ अपने बन्धु- बान्धवों द्वारा मंदिर निर्माण सेवा कार्य में सहयोग प्रदान करवा कर सन्तों एवं भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने परम मंगल के द्वार खोलें। श्री गुरुदेव एवं भगवान् श्रीकृष्ण जी का अधम सेवक

त्रिदण्डि स्वामी भक्ति विबुद्ध मुनि
श्री चैतन्य गौड़ीय मठ
9216511765 ,8777072576
24/05/2022, 08:16 - +91 98026 03763: Sree Chaitanya Gaudiya Math
Axis Bank, Rashbehari Avenue, Kolkata
Acc No: 915010021970515
IFSC Code: UTIB0000253

09/05/2022, 09:32 - Messages and calls are end-to-end encrypted. No one outside of this chat, not even WhatsApp, can read or listen to them. Tap to learn more.
09/05/2022, 09:32 - +91 98106 10400: <Media omitted>
09/05/2022, 09:33 - +91 98106 10400: बजट 2022-23 संबंधी सुझाव मेल द्वारा भी प्रेषित कर दिए गए है।
रमेश मुमुक्षु
अध्यक्ष हिमाल
9810610400
23/05/2022, 12:29 - +91 98106 10400: श्री मनमोहन जी
बजट 2022- 23 के लिए प्रावधान। ये उत्तराखंड के जीवन को बहुत परिवर्तन ला सकता।
1. रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग , अल्मोड़ा शहर और हर जिले में एक गांव ले सकते है।
अल्मोड़ा में पायलट प्रोजेक्ट की शुरूवात हो सकती है । जिसके अंतर्गत सरकारी बिल्डिंग, स्कूल , कॉलेज आदि की छत पर पनाला लगा कर आरम्भ कर सकते है। छत का पानी एक सीमेंट की टंकी या फेरोसीमेंट की टंकी में एकत्र करके पाइप द्वारा उसको किसी बड़े टैंक या रिजर्वायर में डाल सकते है।
2. इस वर्षा के एकत्रित पानी को नहाना ,कपड़े धोने , पौधों में डालने , इस्तेमाल किया जा सकता है।
जो पानी इस्तेमाल के बाद बह जाता है, उसके लिए अगले चरण में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अदि को सोचा जा सकता है।
3. अल्मोड़ा के कितने नौले ठीक है, ठीक हो सकते है, उसका भी लिखा जोखा इस बजट में रखा जा सकता है।
B. एक एक गांव गढ़वाल और कुमाऊं का पायलट प्रोजेक्ट की तरह रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग के किये इस्तेमाल कर सकते है। गांव के घर में टैंक और टैंक भर जाए तो किसी बड़े टैंक या रिजर्वायर में एकत्रित किया जा सकता है।
3. वनाग्नि के लिए रूफटॉप रेनवाटर हार्वेस्टिंग बनाई जा सकती है। पानी के टैंक को जंगल में बनाया जाए और उसकी छत को गहरा और थोड़ा बड़ा बनाया जाए, छत पर पाइप के द्वारा पानी टैंक में जाने का प्रोविशन रखा जाए। ये टैंक किसी पेड़ के नीचे न बनाये क्योंकि उस पर पेड़ के पत्ते गिरते रहेंगे। इस पानी को आग लगने पर इस्तेमाल किया जा सकता है। नल लगाने से कोई निकाल सकता है। इसलिए जहां से पानी जाता है उसी छेद या आउटलेट से पानी।लिया जा सकता है।
रमेश मुमुक्षु
अध्यक्ष,हिमाल
9810610400
22.5.2022
23/05/2022, 12:30 - +91 98106 10400: ये श्री मन मोहन जी को प्रेषित कीजियेगा। उनसे मेरी बात हुई थी। उसके आधार पर मैंने ये लिखा है।
रमेश मुमुक्षु
9810610400

10/05/2022, 22:18 - Messages and calls are end-to-end encrypted. No one outside of this chat, not even WhatsApp, can read or listen to them. Tap to learn more.
10/05/2022, 22:18 - +91 89794 57772: बजट 2022 23 मैं जनभागीदारी हमारे राज्य उत्तराखंड को पटरी पर लाना है तो सबसे पहले भ्रष्टाचार को हर जगह से समाप्त करना होगा। हमारी सरकार की आमदनी कैसे बढ़े, इसके लिए कुछ कदम उठाने होंगे ।
1०: सरकार को फ्री में किसी को कुछ नहीं देना होगा।
2०: बड़े अधिकारी चाहे किसी भी डिपार्टमेंट में हो सरकारी वाहन का उपयोग अपने निजी कार्य में ना करें ।
3०:सरकारी कार्यालयों में एसी का उपयोग कम से कम हो ।
4०:हमारे माननीय मंत्री विधायक गण अपने खर्चे कम करें, राज्य समृद्धि व विकास की ऊंचाइयों पर तभी जाएगा जब सरकार की आमदनी बढ़ेगी ।
5०:परिवहन व्यवस्था को दोबारा पटरी पर लाना होगा रोडवेज में जो माल ढुलाई होती है कंडक्टर उसका भी यात्रियों की टिकट की तरह माल ढुलाई का भी टिकट दे ,वह पैसा सरकार के खाते में जाएगा ।
6०:उत्तराखंड में सरकार को अल्कोहल पर रेट बढ़ाकर पेट्रोल डीजल में वेट कम करना चाहिए अलकोल में रेट बढ़ाकर इसकी पूर्ति हो जाएगी ।
7०:सरकार को राशन की दुकानों में गेहूं चावल की तरह मार्केट से कम रेट पर 2 लीटर सरसों का तेल ,2 लीटर रिफाइंड सोया ऑयल ,पांच नहाने के साबुन ,पांच कपड़े धोने के साबुन और 1 किलो वॉशिंग पाउडर व
1 टूथपेस्ट मुफ्त में नहीं बल्कि कम रेट पर देना चाहिए।
8०: सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना पड़ेगा सरकारी आदमी या बड़े बिजनेसमैन महंगाई की मार सहन कर जाते हैं, पर रोज कमाने -खाने वाले वह प्राइवेट नौकरी करने वाले को बहुत परेशानी होती है।
इसके लिए सरकार को कुछ सोचना चाहिए इसके लिए सरकार तभी सोच सकती है जब सरकार की आमदनी बढ़ेगी । 9०:हमारे उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में जहां बच्चे बहुत कम हैं और कम बच्चे होने के बाद भी अध्यापक वहां पर बने हुए है इन बच्चों को दूसरे स्कूलों में एडमिशन देना चाहिए ।
10०:जहां तक हमारे गढ़वाल और कुमाऊं मंडल की बात है रोजगार के लिए हमारी काठगोदाम रानी बाग मैं बंद पड़ी एचएमटी की जगह खाली है राज्य सरकार अपने स्तर से केंद्र सरकार से बात कर उस जगह का उचित उपयोग कर सकती है वहां पर कुमाऊं गढ़वाल के जितने भी उत्पाद हैं भिन्न भिन्न प्रकार की जड़ी बूटियां ,खाने के उत्पाद ,अचार पैकिंग पूजा-पाठ की सामग्री के लिए धूप अगरबत्ती पैकेजिंग और मार्केटिंग, आदि कई तरह के रोजगार से संबंधित कार्य को शुरू कर सकते हैं जिससे हमारे बहुत से लोगों को रोजगार मिलेगा ।
11०:बजट में हमारे उत्तराखंड के खिलाड़ियों के लिए भी विशेष पैकेज की व्यवस्था करनी होगी । इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं धन्यवाद
जय देवभूमि ,जय उत्तराखंड ,जय भारत ,वंदे मातरम,
जनभागीदारी में मैं तारा दत्त पांडे कुसुमखेडा हल्द्वानी नैनीताल।
मोबाइल नंबर 8979457772
20/05/2022, 07:58 - +91 89794 57772: मानव संबंधों में,
सबसे बड़ी गलती,
हम आधा सुनते हैं,
चौथाई समझते हैं!
शुन्य सोचते हैं लेकिन,
प्रतिक्रिया दुगनी करते हैं!!
॥ सुप्रभात ॥
21/05/2022, 08:40 - +91 89794 57772: <Media omitted>
22/05/2022, 07:50 - +91 89794 57772: <Media omitted>
22/05/2022, 07:51 - +91 89794 57772: <Media omitted>
22/05/2022, 07:51 - +91 89794 57772: <Media omitted>
22/05/2022, 07:52 - +91 89794 57772: <Media omitted>
22/05/2022, 17:55 - +91 89794 57772: IMG-20220522-WA0003.jpg (file attached)

28/04/2022, 12:22 - Messages and calls are end-to-end encrypted. No one outside of this chat, not even WhatsApp, can read or listen to them. Tap to learn more.
28/04/2022, 12:22 - +91 89582 95854: जय केदारेश्वर जय उत्तराखंड धामी जी की सरकार
उत्तराखंड देवभूमी
जिला पिथौरागढ़ तहसील बेरीनाग क्षेत्र के पिलखी नैनी के बीच में पौराणिक केदारेश्वर शिव मंदिर है रामगंगा नदी किनारे स्थित है यहां पर महासीर मछलियों को संरक्षित किया जा रहा है और यहां पर जनवरी के महिने में पुषुड़िया घुघती के दिन मेला लगता है जिसके लिए हमें बजट की आवश्यकता पड़ती है कई बार हमने क्षेत्र के प्रतिनिधियों से गंगोलिहाट के विधायक जी से बात किपी पर पर केदारेश्वर के लिए कोई बजट नहीं मिला
आपसे सर उमीदें हैं बहुत
गाँव निवासी पिलखी
मेला समिति केदारेश्वर अध्यक्ष राकेश चंद मो० 8958295854
14/05/2022, 16:47 - +91 89582 95854: Uttarakhand Breaking - यहां दिनदहाड़े भाजपा मंडल महामंत्री की गोली मारकर हत्या , मचा हड़कंप

https://newstodaynetwork.com/uttarakhand/Uttarakhand-Breaking-BJP-Mandal-General-Secretary-was-shot/cid7396064.htm
18/05/2022, 14:53 - +91 89582 95854: रूद्रप्रयाग के बृजेश सिंह रावत की चमकी किस्मत , DREAM11 में जीते 1 करोड़ रुपये

https://newstodaynetwork.com/uttarakhand/Brijesh-Singh-Rawat-of-Rudraprayag-wins-Rs-1-crore-in/cid7424093.htm

29/04/2022, 22:03 - Messages and calls are end-to-end encrypted. No one outside of this chat, not even WhatsApp, can read or listen to them. Tap to learn more.
29/04/2022, 22:03 - +91 98739 19252: नमस्कार
10/05/2022, 00:14 - +91 98739 19252: अगर संभव है तो उत्तराखंड में वन डिस्टिक वन प्रोडक्ट योजना लागू की जाए
10/05/2022, 00:15 - +91 98739 19252: इससे वहां के लोगों को वहां लोकल उत्पाद पैदा करने में मदद मिलेगी तथा रोजगार मिल जाएगा
10/05/2022, 00:36 - +91 98739 19252: तथा पलायन भी नहीं हो पाएगा
13/05/2022, 23:34 - +91 98739 19252: उत्तराखंड में हिमाचल प्रदेश की तरह चकबंदी सिस्टम लागू किया जाए
13/05/2022, 23:37 - +91 98739 19252: जिससे उन्हें अपने घर के आस पास की काफी जमीन मिले और वह उसे कुछ सकारात्मक उत्पादन के लिए उपयोग कर सके
13/05/2022, 23:38 - +91 98739 19252: इससे हिमाचल तरह उतरा खंड में भी पलायन रुकेगा

28/04/2022, 08:55 - Messages and calls are end-to-end encrypted. No one outside of this chat, not even WhatsApp, can read or listen to them. Tap to learn more.
28/04/2022, 08:55 - +91 78180 94608: Jay ma durga
28/04/2022, 08:55 - +91 78180 94608: Jay shree ganesh
28/04/2022, 09:05 - +91 78180 94608: जिन के पास जमिन अथवा सरकारी नौकरी नही है उनको विना वैज 1लाख तक का सरकारी लोन मिलने चाहिए इससे गरीबों को भला हो जाते, धन्यवाद
28/04/2022, 09:09 - +91 78180 94608: विश्व चीत रा॑य
28/04/2022, 09:09 - +91 78180 94608: रुद्रपुर
28/04/2022, 09:09 - +91 78180 94608: उत्तराखंड
28/04/2022, 09:09 - +91 78180 94608: ऊधम सिंह नगर
28/04/2022, 09:35 - +91 78180 94608: <Media omitted>

Uttarakhand Budget for F.Y. 2022-23

We, the people of land of Gods and Goddess are blessed with a magnificent landscapes which are providing us a safe heavenly abode. The utmost motto and aim of our state government should always be betterment and upliftment of the people of this land. I am very much concerned about the fact that in spite of enrichment in resources we, are lacking in development.

With due respect , I would like to submit the following suggestion for annual budget of Govt of Uttarakhnad for F.Y. 2022-23.

Budget Suggestion:-

(a) **Revenue Receipt**

Revenue receipt is mother of development. Our state is lacking in revenue generation. Our annual expenditure is about 60,000 crores whereas we are able to generate only 15,000 Cr. of revenue i.e. only 26% of revenue in respect of annual expenditure and rest of expenditure in met out of Central Govt Funds. We are expending more on expenditure of revenue nature and less on Capital outlay. Unless we do not make capital investment/expenditure in good proportion , how can we expect good revenue generation in coming years.

(b) **Horticulture** -We need dedicated planned capital outlay for exploring Horticultural programmes. MOU can be made with domestic and foreign investors. We have GB Pant Agriculture University at Pantnagar. We should utilise it for making necessary research and developing fruit breeds which may suitably grown in Uttarakhand. A vast awareness programme for promoting Horticulture and extending helping hands to the people to start horticultural activities in hills villages are required to be done by State Ministry of Agriculture.

(c) **Water resources management In Hills-** A dedicated planned capital outlay for water resources management particularly in hill districts is needed. Each village in entire Uttarakhand region must have water abundance . Our state is still in dismay condition despite of facts that all the majors rivers of this nation are originating from here. Fulfilment requirement of irrigation in hill villages will automatically forbid migration and will generate opportunity for self employment. Presently, villagers are not able to grow even vegetables due to shortage of water and most of the land in villages in hill area is lying barren since rainy season pattern has changed and there is scarcity of drinking and irrigation water.

(d) **Revenue Expenditure Vs Capital Expenditure-** Government should minimise revenue expenditure and optimise Capital expenditure. Only capital expenditure will give fruitful results in coming years. As per the annual budget of F.Y. 2021-22 , we have revenue expenditure of Rs. 44,000 crores whereas capital expenditure is only 14,000 Crore. We do

not have sufficient fund to carry out development programmes. This trends will put us in a pathetic situation in coming years.

(e) Forestry and Forest based Indutries:- There is abundant scope for developing forest based industries. We are enough fortunate that we have a good forest cover. Many timber and furniture based industries can be developed in the state. Ministry of Forest should explore such avenues.

(f) Basic Infrastructure: We are still far behind in road connectivity, rail connectivity and health Infrastructure. Road connectivity is root of all other facilities. All the major roads need complete overhauling. One of the best example we can quote is that , we do not have a rail connectivity at SIDCUL, Sitarganj. All the industries situated at Uttarakhnad have their subsidiary units so they need much more transportation activities to carry out day today business. It's a surprising fact that without rail connectivity, we are expecting that SIDCUL may prosper in future.

(g) Tourism- Though whole of Uttarakhand is a tourist destination but due to lack of publicity and lack of infrastructure, we could not promote tourism as much as it required. Tourism may become one of the major revenue generation sector and provide sufficient employment opportunities to people of Uttrakhand. We need much efforts in this sector. We are gifted with the many places like Munsyari, Dharchula, Chokori in Kumaon and Chamoli, Uttarkahsi ete in Garhwal, a chain of snowy Himalayan mountains where many more adventurous activities can be established to attract domestic and tourist from overseas. But due to poor infrastructure, these places are unknown. One of the place called Boom, Near Tanakpur (Champawat) may also be developed as par with JIM Corbett , Ramnagar and Rishikesh as well. KMVN and GMVN must be given free hand to explore tourism activities.

(h) Panel of Intellectual Senior Citizens: State govt should form various panels of Intellectual senior citizens who have been expert in their fields to give suggestions/recommendation to govt in respect to the sector which they have worked. No need to employee them as an employee and pay salary/remuneration. They will definitely provide their services for betterment of our state provided they should be approached by the state govt machinery and give basic necessary facility to them to carry out their activities. We have no. of Retired Military Officers/Administrative Officers/ Researchers/Scientists between age of 60 to 70.

Thanking in anticipation

Yours faithfully

28-04-22

(Nandan Singh Dhauni)
Sheesh Mahal, Naintal Raod, Kathgodam, Haldwani
Distt- Nainital
Mob-8005445261
e-mail- nasa1537@gmail.com

उत्तराखण्ड प्रदेश के विकास के लिये सुझाव (बजट 2022-23)

उत्तराखण्ड प्रदेश के विकास के लिये केन्द्र सरकार द्वारा चलाये जा रहे कार्यों के साथ-साथ पलायन रोकना और पर्यटन बढ़ाना आवश्यक है।

पलायन रोकना:- प्रदेश के सीमावर्ती गांवों में पलायन रोकना और लोगों को बसाना हमारे देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिये भी जरूरी है। किसी भी स्थान पर लोगों को बसाने और पलायन रोकने के लिये वहां पर बुनियादी सुविधाओं का होना और रोजगार मिलना आवश्यक है।

पहाड़ों पर जगह-जगह पर प्रदेश विकास केन्द्र खोलें, जहां पर सारी सुविधायें बनवाने के लिये नोडल अधिकारी नियुक्त किये जायें। शुरू में ऐसे स्थानों को चुना जाये जहां पर सुचारू यातायात, पर्याप्त जल स्रोत तथा रहने की व्यवस्था का विस्तार तथा भिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट लगाने के लिये पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो सके। ऐसे केन्द्रों के बनवाने से आस-पास के 15-20 गांवों का भी विकास होगा और खुशहाली आयेगी।

शुरूआत ऐसे स्थानों से करें जहां पर ज्यादा से ज्यादा सुविधायें आसानी से उपलब्ध करायी जा सकती है, बाद में सीमावर्ती स्थानों की तरफ बढ़ते हुये जा पायेंगे। केन्द्रों पर सेवायें उपलब्ध करवाने के लिये उद्यमियों को आमंत्रित करने के साथ-साथ उचित मूल्य और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करें, जिससे किसी का एकाधिकार न हो सके।

बड़ी संख्या में माईक्रो जल विद्युत व सौर उर्जा बनाकर राज्य को आपूर्ति करने के बाद ग्रीड को बिजली बेच कर राजस्व अर्जित कर सकते हैं। छोटी यूनिटों में 5-6 माह में ही उत्पादन किया जाता है।

प्रदेश विकास केन्द्रों पर निम्नलिखित सेवायें प्रदान कर सकते हैं तथा परिस्थिति के अनुसार कम ज्यादा किया जा सकता है।

1. कृषि प्रशिक्षण, जड़ी बूटी की उपज, मसालों की खेती, छोटे किसानों की आय बढ़ाने के लिये उन्नत बीज व उपज की जानकारी और प्रशिक्षण दिया जाये। मानव संसाधन केन्द्र बने। यहां पर टैक्निकल व्यक्ति तैयार किये जाये।
2. प्रदेश के उत्पादों का एक्सपोर्ट केन्द्र- फल, सब्जी व हैण्डिक्राफ्ट को सीधे या उनकी सैल्फ लाईफ बढाकर पैक कर देश विदेश भेजे। उनकी जरूरत के अनुसार उत्पादों को बढाने की शिक्षा दें।
3. डेरी फार्म लगवाने की आवश्यकता है।

4. स्वास्थ्य केन्द्र व औषधि विक्रय केन्द्र।
5. कुटिर व लघु उद्योग लगवाने के लिए स्थानीय व अन्य उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाये।
6. योग व प्राकृतिक चिकित्सा को बढ़ावा देने से नागरिकों का स्वास्थ्य सुधरेगा और पर्यटन बढ़ेगा।
7. स्वयं सहायता समूह बनाने के लिये ग्रामवासियों को प्रेरित करें।
8. गेस्ट हाऊस, पार्क, पिकनिक स्थल नौकायन इत्यादि की व्यवस्था।
9. वनों को आग से बचाने के उपाय बताना और लोगों को बचाव के साधन अपनाने के लिये प्रेरित करना।
10. पेय जल व्यवस्था तथा बरसात का पानी तालाबों में रोकना।
11. आपत्ति कालीन व सुरक्षा केन्द्र बनाना।
12. थाना/कोतवाली बनवाना।
13. उच्च क्वालिटी के आलू की उपज को बढावा देना।

पर्यटन बढाने के लिये:- पर्यटन स्थलों का सौन्दर्यकरण व सफाई। बांधों को भी पर्यटक स्थलों के रूप में विकसित करने की जरूरत है और यह कार्य बहुत कम खर्च में ही हो जायेगा। बांध का बेसिक डाटा बताने से, पर्यटकों की उन स्थानों में रूचि बढ़ेगी। ऐसे स्थानों पर नौकायन और पार्क व गेस्ट हाऊस भी आसानी से बनवाये जा सकते हैं।

सबकी इच्छा होते हुये भी हरिद्वार से नैनीताल सडक मार्ग सुगम नहीं बन पाया है यह रास्ता बिना उत्तर प्रदेश में जाये और सुगम हो। प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों पर जाम और पार्किंग की समस्या का समाधान सरकार की इच्छा शक्ति से ही दूर किया जा सकता है। जाम न होने से पर्यटन स्थल से थोडी दूरी पर भी पर्यटक रूक सकते है। घरों में भी पर्यटक आवास सुविधा का फायदा ले सकते हैं। उत्तराखण्ड की टैक्सियों पर उत्तर प्रदेश में टैक्स आधे से भी कम करवाये जा सकते है।

दिनांक 10.05.2022

वेद प्रकाश गुप्ता
पता- 506, मॉडल कालोनी
हरिद्वार
मो.नं. 9837302808

Goat a future animal

Goat as poor man's cow

Mahatma Gandhi recognized goat as future animal.

Our political class and bureaucrats need to understand, *goat is kept as ruminant animal till date.*

Time has come to consider this ruminant as animal. At ground zero, there is no support to goat farmers. Simple policy change, to Bring **goat** in the same category to which cows and buffalos belong. This will be a frugal attempt. Infra such as doctors, hospitals, etc, will be available to goat farmer, without much investment.

We have great hopes from present leadership. I expect it will be implemented on ground.

Definitely things will change in case above.

Present Scenario

99% of goat farmers i.e. 200 lakh small and marginal farmers are engaged in goat farming by extensive methods. They are doing it with virtually no capital, resources and no formal training.

How we can improve

Incase **semi intensive method**is adopted and implemented, 25% more farmer will adopt goatry. By upgrading their present stock, current 250 lakh farmers, their income will be doubled. That means 320 lakh farmers will be engaged in this profession which is side business for them.

By upgrading present goat stock, rural Bharat.

Benefits are:

- Generated employment and increased revenue will hamper farmer suicides and their agitation.
- Empowering women.
- Improve children health; Goat milk is a boon for child nourishment.
- Its meat is most liked and expensive in India.
- I suggest Bharat can produce and its India counterpart is ready to take any quantity at premium price.

Undersign: Sh. Karamjeet Singh Randhawa,Ranibagh, Haldwani
(NATIONAL AWARD WINNER)

Mobile: 9719522201
Email: ksrtrucker@gmail.com

I appeal our leadership please give some time to Bharat, this step will create maximum number of employment than any other schemes, run by government, till date.

I also look forward; present government will be serious on this subject and will take prompt action.

That is 8% GDP from livestock sector can be doubled to 16%. Also this step wills double the existing 4% rural employment through it.

It is to be noted that landless labour depends on goat partially or completely.

I suggest creation of self-help groups at village level, co-operatives.

Lesson from past

In 70ies, our agriculture minister late sh. Babu Jagjivan Ram, had upgraded pigs, across India by importing two ship load of breading stock from Scotland. They were distributed in all states.

Today the results are apparent, on ground.

About My Self

Undersigned is an NRI came to India with great hope, in 70ies from Germany. Being to 20 countries, right from Afghanistan to Germany. Well-traveled across India. Currently running a logistics business, has given concept to white good industries and tyre companies.

Fought Bangladesh war without an APO number, 1971 along with my vehicle, served mostly "90 Mountain Artillery Battery"

Note: I have ground breaking practical ideas like

- Air ventilated vehicles, insulated vehicles and refrigerated vehicles, using agriculture left over waste from fields. Helping farmer and food processing industry.
- Use of grafting method in agriculture using different root stocks, very adaptive and practical for farmers.

Undersign: Sh. Karamjeet Singh Randhawa,Ranibagh, Haldwani
(NATIONAL AWARD WINNER)

Mobile: 9719522201
Email: ksrtrucker@gmail.com

01/05/2022, 10:41 - Messages and calls are end-to-end encrypted. No one outside of this chat, not even WhatsApp, can read or listen to them. Tap to learn more.
01/05/2022, 10:37 - +91 6397 945 273: माननीय महोदय सर्वप्रथम मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आप ने वित्तीय वर्ष 2022- 23 के बजट निर्माण प्रक्रिया में सुझाव देने के लिए आमंत्रित किया ।

माननीय महोदय मेरा सुझाव यह है कि जो हमारे राज्य की शिक्षा प्रणाली है उसमें परिवर्तन करने की बहुत आवश्यकता है आज हमारे सरकारी स्कूलों (प्राथमिक अथवा माध्यमिक स्कूलों) की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है । मान्यवर इस बजट में शिक्षा व्यवस्था पर जोर देना होगा। इसमें कुछ बातें शामिल किया जाए जो निम्न प्रकार से हैं।

मान्यवर विद्यालय को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने की जिम्मेदारी विद्यालय के प्रधानाचार्य की होती है यदि विद्यालय में सभी शिक्षकों को यह आदेश जारी किया गया कि वह समय पर विद्यालय पहुंचे और प्रतिदिन विद्यालय में मौजूद रहे लेकिन देखा यह जाता है कि कुछ विद्यालयों में ना तो शिक्षक रहते हैं और ना ही प्रधानाचार्य । महोदय कुछ स्कूल/ विद्यालय ऐसे हैं जिनमें बच्चों की संख्या लगातार घटती जा रही है। ऐसा भी नहीं है कि सभी स्कूलों/ विद्यालयों की हालत खराब ही हो कुछ विद्यालय है ऐसी भी है जिनमें प्रधानाचार्य और शिक्षकों की सूझ - बूझ से काफी हद तक विद्यालयों की स्थिति ठीक है।

मेरे विचार से इसका दोष सिर्फ और सिर्फ हमारी शिक्षा व्यवस्था और हमारे शिक्षक वर्ग की है। महोदय एक आदेश यह भी जारी किया जाए की जो भी शिक्षक सरकारी स्कूलों में पढ़ाते हैं उनको अपने बच्चों को भी सरकारी स्कूलों में ही प्रवेश दिलाना होगा और समय-समय पर गांव व शहरों में जन संपर्क करके लोगों को अपने बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूलों में कराने के लिए प्रेरित करना होगा।

अतः अधिक ना लिखते हुए मैं अपनी शब्दों को यहीं समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय महोदय आप इस विषय में ठोस कदम उठाएं और उत्तराखंड राज्य को 100% शिक्षित/साक्षर राज्य बनाएं।

धन्यवाद

विजय काला
ग्राम व पोस्ट - मांडई
ग्राम सभा- बिजनूर
जिला- पौड़ी गढ़वाल
उत्तराखंड 246144
दूरभाष -6397945273

सेवा में,

माननीय मुख्यमंत्री महोदय
उत्तराखण्ड सरकार
देहरादून।

विषयः—शिक्षण एवं मार्गनिर्देशन केन्द्र धारचूला(पिथौरागढ़)में कार्यरत संविदा कर्मचारियो के मानदेय भुगतान नही होने के सबध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संबध में सादर अवगत कराना है कि जिला सेवायोजन कार्यालय पिथौरागढ़ के नियंत्रणाधीन शिक्षण एवं मार्गनिर्देशन केन्द्र धारचूला जो कि टी0एस0पी0(ट्राइबल सब प्लान) के अर्न्तगत संचालित है के संविदा कर्मचारियो को विगत 8 माह से मानदेय का भुगतान एवं वर्ष 2020 सितम्बर से प्रोत्साहन भत्ते का भुगतान शासन द्वारा बजट आवंटन नही होने के कारण नही हो पाया है।जिसके कारण कर्मियो को जीविकापार्जन करने में एवं बच्चो के भरण पोषण करने बड़ी ही कठिनाईयो का सामना करना पड़ रहा है।एवं कर्मी एवं उसके परिजन भुखमरी के कगार पर है।

अतः महोदय से सादर निवेदन है कि शासन से उक्त केन्द्र जो कि टी0एस0पी0(ट्राइबल सब प्लान) के अर्न्तबत संचालित है के कर्मियो के मानदेय एवं भत्ते हेतु बजट आवंटन कराने कि महती कृपा कीजियेगा।

दिनांक :— 04.मई.2022

प्राथीयान
1 धन सिंह धामी (अनुदेशक)
2 महेश चन्द्र पांडे (अनुदेशक)
3 विजेन्द्र पाल (अनुदेशक)
4 नारायण सिंह धामी(अनुसेवक)

30/04/2022, 20:24 - Messages and calls are end-to-end encrypted. No one outside of this chat, not even WhatsApp, can read or listen to them. Tap to learn more.
30/04/2022, 20:24 - +91 85068 61763: हमें हमारे उत्तराखंड में अपने लोगों को नौकरी देनी चाहिए जिससे वह अपनी मातृभूमि में ही रहे और लोगों के लिए अस्पताल बनाए जाएं और अच्छी शिक्षा प्रदान की जाए जिससे उन्हें शहर ना आना पड़े
30/04/2022, 20:31 - +91 85068 61763: अगर यह काम हमारे उत्तराखंड में ना होते हैं तो यह भी हो सकता है कि हमारे उत्तराखंड में जितने भी लोग रहते हैं वह सब शहरों की ओर आ जाएं और हमारे गांव सोने पर जाऐ
30/04/2022, 20:32 - +91 85068 61763: A

30/04/2022, 14:23 - Messages and calls are end-to-end encrypted. No one outside of this chat, not even WhatsApp, can read or listen to them. Tap to learn more.
30/04/2022, 14:23 - +91 96341 22314: राम राम जी
महोदय आपने आमजन से बजट पर सुझाव मांगे है उसके लिए आपका बहुत-बहुत साधुवाद
महोदय जी वेसे तो बहुत कुछ है पर हम अपने राज्य की आर्थिक स्थिति जानते है इसलिए ज्यादा नही कहोगे कुछ सुझाव है
1. पुलिस विभाग - महोदय पूरे राज्य मे जितने भी चौकी,थाने, कोतवाली है सबमे वाहन होने चाहिए बजट की कमी को देखते हुए समस्त पर्वतीय क्षेत्र मे जो वाहन 4-5साल पूराने हो गये हो उन्हे मैदानी जगहो मे भेज दिया जाय ओर पर्वतीय क्षेत्र मे अन्य वाहन के साथ महिन्द्रा कैम्पर जैसे वाहन भी हो जिसमे क्षेत्रनुसार 4×4 एव A/C हो जो बहुउद्देशीय लाभकारी होगा एक प्रकार से यह पंचवर्षीय योजना है हर 5 वर्ष मे वाहन मैदानी भाग मे ओर 10 साल बाद नीलाम इससे एकसाथ ज्यादा आर्थिक भार भी नही पडेगा ओर हर चौकी तक वाहन व्यवस्था वाला पहला राज्य भी बन जायेगा ।ओर हर संवेदनशील जगह के लिए ड्रोन ।।
2.एक स्टेडियम का निर्माण स्टेडियम है लेकिन अव्यवस्थित जगह भी सरकारी है एक बडा मैदान है उसके बराबर मे छोटा मैदान है वहा पर एक कैन्टीन व डियर पार्क स्थापित है वहां एक बालीबाल 2 बैडमिंटन और दो कबड्डी मैदान ओर एक कैन्टीन बन सकती है ओर बडे मैदान मे फुटबाल,क्रिकेट,हाकी के लिए साथ मे चैनजिग रूम शौचालय जगह भी शानदार है ओर पास के सभी राज्य भी भाजपा शासित है वह भी सहयोग कर सकते है महोदय इससे यह क्षेत्र सदेव आपका आभारी रहेगा (डाकपतथर विकासनगर विधानसभा)
व्यक्तिगत निवेदन-महोदय यदि स्टेडियम का निर्माण आप करा दे तो हमारी अभिलाषा है कि स्टेडियम का नाम महावीर जसवंत सिंह रावत जी व CDS दोनो के नाम पर दोनो हो ओर शिलान्यास बॉक्सर मैरीकोम करे ।।
अतिरिक्त--चार धाम यात्रा मार्ग पर भण्डारा स्थल जैसे धारीदेवी के पास मलैया रुद्रप्रयाग से केदारनाथ के बीच जोशीमठ से चमोली के बीच गोविन्दघाट मे गोलूदेव मन्दिर आदि कहने को तो यह भण्डारा स्थल होगा पर होगा बहुउद्देशीय नीचे पार्किंग शौचालय कूडेदान ऊपर भण्डारा स्थल पर ऐसी जगह बने जहां लैण्ड स्लाइड न हो बाजार या आबादी न हो पानी की व्यवस्था ठीक हो इसमे केन्द्र सरकार मदद कर सकती है ।।
हो सकता है हम अपनी बात सही से न रख पाये हो कुछ गलत लगै तो माफ करना आपका राज्य वासी
-- हर हर महादेव --

30/04/2022, 09:21 - Messages and calls are end-to-end encrypted. No one outside of this chat, not even WhatsApp, can read or listen to them. Tap to learn more.

30/04/2022, 09:21 - +91 84493 72261: इस बार हमारे बजट में वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के लिए कुछ राशि होनी चाहिए। प्रत्येक जिले के 5 गांवों को पूरी तरह से सौर ऊर्जा स्रोत से सम्पन्न करने हेतु बजट होना चाहिए। ये एक पायलट प्रोजेक्ट की तरह होगा और आने वाले सालों में हमारे राज्य 50%
ऊर्जा वैकल्पिक स्रोत प्राप्त करता है
तो यह आपके लिए और हमारे लिए बड़ी उपलब्धि होगी
हिमांशु अग्रवाल
जिला- नैनीताल
फ़ोन नंबर- 8449372261

28/04/2022, 09:40 - Messages and calls are end-to-end encrypted. No one outside of this chat, not even WhatsApp, can read or listen to them. Tap to learn more.

28/04/2022, 09:40 - +91 98687 89787: 🙏 मनरेगा बजट जो गांव के विकास के लेप रखा जाता है उसमें से कृषि वर्क (खेत मैं हल लगाना)को शामिल करें तो किसान को लाभ होगा। हल जोतने की मजदूरी व फसल से अनाज मिलने पर पलायन भी रुकेगा। हर किसान की कुल कृषि भूमि पर मजदूरी मुहिया करना।अभी तक भूमि विकाश में केवल खेत के उजड़े भिड़ा को ही ठीक करते है इसको मर्ज कर सकते है हल जोतने मैं।

28/04/2022, 14:00 - +91 98687 89787: 🙏 पर्वतीय क्षेत्रों के पके मकानों की रजिस्टरी हो व हाउस टैक्स लागू करें।

उत्तरखंड मैं पर्वतीय इलाकों मैं बिजली के मीटरो मैं लगे BPL/APL में कालांतर मै भेड़ चाल में लगाये गए बिना वेरिफाई के है।व बिजली के बिलों मैं मीटर रीडर(कांटेक्ट)वाला मन मर्जी से बिल की रीडिंग शो करता है कुछ ले दे कर। इन छेत्रो मैं बिजली चोरी(काटा)अधिक मात्रा मैं हो रही है लाइन मैन(असविन्दा) के सहयोग से। मीटर को रिवीज़न वेरीफाई करने की पहल करे।

30/04/2022, 09:30 - +91 98687 89787: 🙏 उत्तराखंड विकास के बजट मैं लोकडौन के दौरान अपने अपने गाँव घर पहुचे लोगो के लेप सुनिश्चित व्यस्था स्थानीय सासन प्रसाशन व पुलिस चौकियों करें उनके उजड़े परिवार को बसने के लेप।

29/04/2022, 18:35 - Messages and calls are end-to-end encrypted. No one outside of this chat, not even WhatsApp, can read or listen to them. Tap to learn more.
29/04/2022, 18:35 - +91 88595 43359: 🙏
29/04/2022, 19:33 - +91 88595 43359: हमरा राज्य uk मे रोजगार का एक ही साधन है सिर्फ टूरिस्ट को प्रमोट करना अगर जयधा से जयधा प्रदेश मे टूरिस्ट प्लेस को बढ़ा कर रोजगार बढ़ा सकते है क्यू की लोग गर्मीयों घूमने k लिए सबसे जयधा पहाड़ों की और आते है सबसे जयधा इकॉनमी को बूस्ट करता है

29/04/2022, 18:49 - Messages and calls are end-to-end encrypted. No one outside of this chat, not even WhatsApp, can read or listen to them. Tap to learn more.

29/04/2022, 18:49 - +91 89540 70809: नमस्कार

जैसा कि उत्तराखंड का 86% भाग पहाड़ी क्षेत्र में समाहित है एवं पहाड़ी राज्य होने के नाते यहां रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है और इससे एक दूसरी समस्या पैदा हो गई जिसका नाम है पलायन/

यहां के युवाओं को रोजगार मिले एवं इसके लिए हमें यहां पर *सेवा क्षेत्र के उद्योगों* को बढ़ावा देना चाहिए जिसमें आधारभूत ढांचे की इतनी आवश्यकता नहीं होती है एवं हमारे पास भारी उद्योग लगाने के लिए आधारभूत ढांचा है भी नहीं इसलिए मैं सेवा क्षेत्र के बात कर रहा हूं, जिसमें हमें *B.P.O promotion scheme* लानी चाहिए , इस प्रकार की योजना केंद्र सरकार द्वारा पहले से संचालित है क्योंकि इस प्रकार की योजना में सिर्फ *बेहतर इंटरनेट* की सुविधा चाहिए होती है किसी भी आईटी क्षेत्र की कंपनी को अपना *बीपीओ* स्थापित करने के लिए और कौन व्यक्ति नहीं चाहता पहाड़ों पर रहकर मैं काम करूं इससे बाहरी व्यक्ति यहां आएगा एवं उत्तराखंड का युवा

भी यहीं रुकेगा

२. पर्यटन क्षेत्र को और बढ़ावा देने के लिए उससे संबंधित बुनियादी ढांचे में और विकास की जरूरत है तथा इसके लिए अलग से *पूंजीगत खर्च* में *बजटीय प्रावधान* करने की जरूरत है जिससे बेहतर पार्किंग, हवाई सेवाएं इत्यादि विकसित की जा सके।

सादर

राजेंद्र सिंह बिष्ट

हल्द्वानी संपर्क सूत्र 8954070809

29/04/2022, 18:47 - Messages and calls are end-to-end encrypted. No one outside of this chat, not even WhatsApp, can read or listen to them. Tap to learn more.
29/04/2022, 18:47 - +91 97591 61035: Sir ji UPNL से लगे सभी कार्मिकों सुप्रीम कोर्ट में लगी SLP वापस ली जाए और सभी कार्मिकों को समान काम का समान वेतन दिया जाए

29/04/2022, 18:39 - Messages and calls are end-to-end encrypted. No one outside of this chat, not even WhatsApp, can read or listen to them. Tap to learn more.

29/04/2022, 18:39 - +91 97567 08571: सर प्रणाम सर आप से विनम्र निवेदन है कि 22 हजार उपनल कर्मचारियों के हित मे एक फैसला जरूर ले सर आप ने जो सब कमेटी बनवायी थी इस पर भी कोई अच्छा सुझवा ले सर 22 हजार उपनल कर्मचारी और उनके परिवार सदैव आपके आभारी रहेंगे सर

29/04/2022, 18:21 - Messages and calls are end-to-end encrypted. No one outside of this chat, not even WhatsApp, can read or listen to them. Tap to learn more.
29/04/2022, 18:20 - +91 96345 15700: भारतीय संविधान ने राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य की संज्ञा दी है लोक कल्याणकारी राज्य में समानता के अधिकार के तहत उपनल संविदा कर्मचारियों को भी पद का न्यूनतम वेतन भुगतान किया जा सके उसके लिए बजट में प्राविधान किया जाय वर्तमान महंगाई सूचकांक के आधार पर मानदेय भुगतान हो ऐसा बजट में प्राविधान कर उपनल कर्मचारियों को सम्मान जनक मानदेय पाने की व्यवस्था हो। वर्तमान में मात्र 10 से 12 हजार प्रति माह मानदेय में उपनल संविदा कर्मचारी अपने तथा परिवार का भरण-पोषण कर रहे है जो समय से मिलता तक नहीं महंगाई के इस दौर में जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा है।

29/04/2022, 18:15 - Messages and calls are end-to-end encrypted. No one outside of this chat, not even WhatsApp, can read or listen to them. Tap to learn more.
29/04/2022, 18:15 - +91 86505 94979: माननीय मुख्यमंत्री जी को नमस्कार.
महोदय उपनल कर्मचारी काफी लंबे समय से अपने वेतन बढ़ोतरी हेतु निवेदन कर रहे हैं आपसे विनम्र अनुरोध है कि उनका सम्मानजनक वेतन दिया जाए.

29/04/2022, 13:55 - Messages and calls are end-to-end encrypted. No one outside of this chat, not even WhatsApp, can read or listen to them. Tap to learn more.

29/04/2022, 13:55 - +91 96347 48120: बड़े भाई साहब प्रणाम

29/04/2022, 14:00 - +91 96347 48120: मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं एक तो इनकी मनमानी खत्म हो मैंने बहुत जगह देखा है जब बच्चे का एडमिशन होता है एडमिशन से लेकर और फर्स्ट क्लास तक की ड्रेस अलग होती है और 1 क्लास है 5 तक की क्लास के ड्रेस अलग होती है और 6 लेकर 12 की ड्रेस अलग होती है हर साल फीस में बढ़ोतरी रहती है और कहते हैं कि हम तो सेवा कर रहे हैं अरे क्या सेवा कर रहे हैं हर साउथ में फीस बढ़ा देते है तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री से यही अनुरोध है एडमिशन होता है और 1तक की फीस कम से कम 400 से लेकर 500 होनी चाहिए

और 1 क्लास से लेकर फाइव क्लास तक सिक्स हंड्रेड होनी चाहिए और 6 क्लास से लेकर ट्वेल्थ क्लास तक 800 से लेकर 1000तक होनी चाहिए

29/04/2022, 14:02 - +91 96347 48120: और मेरा मान्य मुख्यमंत्री से निवेदन है कि कि जब से हमारी सरकार बने कुछ लोग परेशान हैं कि गैस के दाम बढ़ गए हैं गैस के दाम पर कुछ कम करने की कृपा करें मैं भी एक भाजपा कार्यकर्ता हूं और जनता के बीच में रहता हूं और जनता वही कहती है कि आप की सरकार तो बनी बाद में पहले मै महंगाई कर दी तो मेरा निवेदन है कि घरेलू गैस सिलेंडर है इसमें कम से कम 200 से लेकर 300 तक कम करने की कृपा करें धन्यवाद जय श्री राम भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद

29/04/2022, 14:03 - +91 96347 48120: This message was deleted

29/04/2022, 14:03 - +91 96347 48120: <Media omitted>

29/04/2022, 14:08 - +91 96347 48120: जब ऋषिकेश में एम्स खुला था तो सुन के बहुत अच्छा लगा था कि उत्तराखंड में भी एक एम्स खुल गया है पर उस एम्स की व्यवस्था को देखकर हम लोगों के लिए बहुत बेकार है अगर किसी की सिफारिश है तो उसका काम हो जाता है जिसकी सिफारिश नहीं है वह बेचारा लावारिस की तरह रहता है मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं की एम्स की व्यवस्था को सही करें हो सके जितने हमारे उत्तराखंड के लोग हैं बेचारे को कौरना से घर बैठे हुए हैं उन को रोजगार मिले जिसमें जिसमें हम भी शामिल है जबसे कौरना आया तब हम लोग भी घर बैठे हुए है

29/04/2022, 14:13 - +91 96347 48120: <Media omitted>

आपका बजट, आपका सुझाव

No.

Date

सबसे प्रथम नियोजन एवं संशोधन निदेशालय को अभिनन्दन। हम सब मिलकर एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। GNCTDelhi में 1972 से 2009 तक योजना विभाग की सेवा की और (2009-15) लिए 6 वर्ष AS Advisor सहयोग किया। इस तुच्छ अनुभव के आधार पर, कुछ सलाह देने की कोशिश कर रहा हूँ

1) बजट निर्धारण के लिये बजट बनाने से पूर्व जनभागीदारी प्राप्त करना एक अच्छा प्रयास है लेकिन आज के समय में जब हम Planning Process को बदल कर कुल बजट निर्धारण के युग में हैं, तब इस पद्धति को एक निरंतर कार्यरत प्रणाली के रूप में लेना ज्यादा लाभकारी व ज्ञानवर्धक होगा।

No.

Date

2) मेरा आशय है कि Subject-/Sector wise workshop/Seminar करवाकर हर क्षेत्र के लिये सामान्य जन, विशेषज्ञों, विषय निपुण लोगों से उनके सुझाव व अनुभव लेते रहे और उन पर सम्बन्धित विभाग पूरे वर्ष नीति निर्धारण प्रक्रिया संचालित करते रहे। इन निष्कर्षों पर आकर यदि हर विभाग अपनी बजट राशी का अनुमान लगाये और वित्त एवं योजना विभाग को Associate करते हुये Sectoral targets निर्धारित कर उनके Financial estimate बनाये जाय तो शायद Short Period में लिये गये सुझावों से ज्यादा उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं।

No.

Date

5- प्राइवेट स्कूलों का आकर्षण क्या Govt. School education System को कहां ले जायेगा, पूरे Perspective में सोचना पड़ेगा।

6- वर्तमान Health Infrastructure को सही मायनों में useful functional unit बनाने के लिये क्या क्या आवश्यक संसाधनो को जुटाना है और किस तरह सम्भव कर सकेगें, हर कदम को चिन्हित कर लक्ष्य निर्धारित करने होंगे

7- चीड़ वन सम्पदा उत्तराखण्ड के लिये अभिशाप है, ~~[illegible]~~ वन वैज्ञानिक, Env. Experts, सामान्य जन हर फोरम पर कह चुके है। क्या मनरेगा में चीड़वनो को कटवाकर उपयुक्त

No.

Date

3- सुझाव मांगने / workshop / Seminar करवाने के लिये Sectorwise Background Paper सम्बन्धित विभाग उपलब्ध करवाते तो सुझाव देने वालों को सही सुझाव देने में में सुविधा होगी

4- क्या उत्तराखण्ड में मनरेगा अपने लक्ष्य प्राप्त कररहा है यह समझने के लिये Background Paper जरूरी है।

क्यों लोग पैतृक व्यवसाय कृषि से दूर जारहे हैं? organic Farming का Full scope होते हुये हम हिमाचल से पीछे क्यों है? Horticulture, Animal Husbandry क्यों युवाओं को Self-Employment के लिये प्रोत्साहित करने के बजाय नाकाम रहा?

चौड़ी पत्ती के पौधारोपण द्वारा हम निर्धारित लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं? दार्जिलिंग, सिक्किम, असम, मेघालय का पर्यटन चौड़ीपत्ती के वनो से आच्छादित प्राकृतिक सौन्दर्य पर निर्भर है, हम सब जानते ही हैं।

8 – उत्तराखण्ड का काफी बड़ाभूभाग वन क्षेत्र है केवल इस तथ्य से सन्तुष्ट होकर नहीं रहा जा सकता है। ऐसे बहुत क्षेत्र हैं जिनपर वृक्षारोपण की बहुत आवश्यकता है। कम से कम इन गैर-वनस्पति भू-भागों पर चौड़ी पत्ती के वृक्षारोपण करके उपयोगी वन सम्पदा तैयार की जा सकती है जो उन क्षेत्र के निवासीयो की जरूरतें भी पूरी करे और Environment, Soil Conservation के लक्ष्य प्राप्त करें।

No.

Date

9— राज्य के आर्थिक संसाधनों को बढ़ाना जरूरी है लेकिन सामान्य जन व्यवहार को भी ध्यान में रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है। आज उत्तराखण्ड में शराब का Consumption जिस गति और ढंग से बढ़ रहा है उसपर भी उचित दृष्टिकोण अपनाने की अति आवश्यकता है। Prohibition Unit को उचित Role Play करना आवश्यक हो गया है। सभी सम्मानित लोगों के साथ मिलकर एक जन अभियान निरंतर चलाना होगा जो शराब के उपभोग को अनुचित सिद्ध कर किशोरों को सही मार्गदर्शन कर सके।

10 आप कह सकते हैं यहाँ तक बजट सुझाव नहीं, समस्यायें हैं। इसीलिये मेरा अनुरोध है कि पूरे वर्ष ऐसे विषयों पर उचित फोरम के माध्यम से विचार विमर्श चलता रहना चाहिये ताकि समस्याओं के समाधान के लिये उचित योजनायें बनायी जा सके और बजट राशी का उपयोग सही ढंग से किया जा सके। केवल यही समस्यायें नहीं हैं। रोजगार एक अपने आप में सबसे प्रमुख समस्या है। स्वरोजगार ही उत्तराखण्ड के लिये सबसे कारगर सिद्ध हो सकता है, इसे चिन्हित करने के लिये उपयुक्त Background Paper होना जरूरी है, नहीं तो

सही समाधान देने के लिये
बहुत महान ज्ञानी इस समय हाजिर हैं
Background Paper में बेकार लोगों की
शैक्षिक योग्यता, रुचिकर व्यवसाय, उपलब्ध
संसाधन, अनुभव, आदि Sample Basis
पर सर्वे कर देना जरूरी है। Estimated
number भी हर Catogary के लोगों का होतो
सही योजनायें बन सकती हैं।

II — आपका उत्तर अगर मिल गया तो
कुछ और अधिक समय मिल बैठकर लगा सकते हैं।
हिन्दी भाषा का उपयोग यहां नहीं होने के कारण अब
ऐसा लगता है कि न हिन्दी सीखी न English।
तो भाषा की गलतियों के लिये क्षमा प्रार्थी हूं

Mob:- 9810514530
Rawat 23/04/12
(B.S. RAWAT), C-234, SFS Flat
Divya Jyoti Aptt., Sector-19, Rohini, Delhi-110

29/04/2022, 10:55 - Messages and calls are end-to-end encrypted. No one outside of this chat, not even WhatsApp, can read or listen to them. Tap to learn more.
29/04/2022, 10:55 - +91 94107 93490: माननीय मुख्यमंत्री जी महोदय उत्तराखंड सरकार हम सभी सरपंचों से यह निवेदन है कि आप से सभी सरपंच को मानदेय एवं बीमा एवं मेडिकल की सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में और जिस तरह से ब्लॉक प्रमुख की निधी होती है उसी तरह से भी सरपंचों का भी निधि बनाने का कष्ट कीजिएगा

हिमाँशु सिंह भाट
पोस्ट अफिस कालिका
तहसील धारचूला
जिला पिथौरागढ
पिन 262676

29/04/2022, 10:59 - +91 94107 93490: जंगल में आग बुझाते समय या किसी समय भी दुर्घटना हो सकती है सरपंचों को इसलिए रात दिन लगे होते हैं जबकि इन मानदेय कुछ भी नहीं है

29/04/2022, 11:32 - Messages and calls are end-to-end encrypted. No one outside of this chat, not even WhatsApp, can read or listen to them. Tap to learn more.
29/04/2022, 11:32 - +91 75791 95781: पदि सरकार योगी आदित्यनाथ जी की तर्ज पर एक जिला एक उत्पाद तथा गौ पलको को मान देय देती है तो युवाओ को रोजगार भी मिलेगा और पलायन भी रुकेगा , इससे भी बड़ा कदम यह होगा, कि चक बंदी हो जय, चक बंदी एसी हो कि गाँव जमींन दो हिस्सा कर अब्बल एवं दूइम् बाट कर, सभी परिवारों को दो चेको मे जमीन दे दी जाए 1

28/04/2022, 09:02 - Messages and calls are end-to-end encrypted. No one outside of this chat, not even WhatsApp, can read or listen to them. Tap to learn more.

28/04/2022, 09:02 - +91 70170 02796: मान्यवर आपका यह कार्य सराहनीय है जैसा कि मैंने पिछले तीन-चार वर्षों में देखा हमारी प्राइमरी स्कूलों के लिए बजट नहीं है मेरा आपसे अनुरोध है की प्राइमरी स्कूलों के रखरखाव के लिए उनकी छतों पर सोलर पावर प्लांट लगाए जाए और इसके लिए धन माइक्रो इरिगेशन के पास है जिन स्फूर्ति योजना में सोलर वाटर पंप केंद्र सरकार के आए हैं जिसका उत्तराखंड के पहाड़ों पर उपयोग नगण्य है अगर इस फंड को हम अपने स्कूलों की छतों पर लगाते हैं हमारे बच्चे बिजली में पढ़ेंगे और स्कूल की कुछ अतिरिक्त आय भी होगी जिससे स्कूल के रखरखाव में कार्य होगा मान्यवर से मेरा एक अनुरोध यह भी है कि हम अपनी लायबिलिटी या कम करें और ऐसैट्स को बढ़ाएं हमारे बजट में ज्यादातर लायबिलिटी असेट्स कम होते जा रहे हैं हम ₹100 में ₹ ₹88 खाली समाज को खुश करने में खर्च कर दे रहे हैं हम विकास कैसे करेंगे हम भिखारी होते जा रहे हैं अगर हमें पहाड़ पर खुशहाली और रोजगार पैदा करने हैं तो हमें स्थाई कॉल सेंटर खोलिए प्रत्येक जनपद में हमारे बच्चे हिंदी अच्छी बोल लेते हैं केंद्र सरकार से हम अपने कॉल सेंटर्स के लिए काम मांग सकते हैं सारे कॉल सेंटर अभी बेंगलुरु से चल रहे हैं

28/04/2022, 09:05 - +91 70170 02796: मान्यवर हमारे प्रदेश का युवा अच्छा शिक्षित है और अपने जनपदों में कार्य भी करना चाहता है अगर आप बिजली और ऑप्टिकल फाइबर का नेटवर्क दे दे उत्तराखंड को खाली कॉल सेंटर के बल पर हम विश्व से डॉलर भी कमा सकते हैं और आपसे अनुरोध है आपने सही सलाहकार रखिए इस उत्तराखंड को बर्बाद करने वाले सलाहकार ही हैं मैं वालंटियर अपनी सेवाएं दे सकता हूं इसके बदले में ना मुझे टेंडर चाहिए और ना ही कोई पद आपके प्रदेश का एक समर्पित नागरिक जय हिंद वंदे मातरम

29/04/2022, 10:36 - +91 70170 02796: 1

29/04/2022, 10:39 - +91 70170 02796: साथियों सादर प्रणाम अभी मेरे संज्ञान में आया है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में और कई अन्य राज्यों में उच्च शिक्षा के के अध्यापकों की रिटायरमेंट की आयु सीमा 60 साल से सात से बढ़ाकर 65 साल कर दी गई है यह सभी वामपंथी अध्यापक हैं जिन्होंने हमारी शिक्षा व्यवस्था में सिर्फ बेरोजगार पैदा किया है और आतंकी पैदा किए हैं और हमारी सरकार है इनको रिटायर नहीं कर रही हैं क्योंकि इनके कार्यकर्ता यहीं से मिलते हैं और हमारे नए युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है जो आज की आधुनिक शिक्षा के लिए बिल्कुल योग्य है अतः आप से मेरा अनुरोध है कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सरकार पर अत्यधिक दबाव डालकर इन्हें तत्काल प्रभाव से रिटायर कराया जाए और नई भर्ती खोली जाए जिससे हमारे युवा भाइयों को रोजगार मिले और बच्चों को आधुनिक शिक्षा का अवसर हमारे बुजुर्ग अध्यापक आधुनिक शिक्षा से मिलो दूर हैं और उनकी एक की तनख्वाह में हमें 3 अध्यापक मिल जाएंगे जो कंप्यूटर और आधुनिक शिक्षा से लैस होंगे जिससे हमारा युवा रोजगार के लिए भटके का नहीं रोजगार देगा अतः मेरा आपसे अनुरोध है सारे अध्यापकों का ऑडिट कराएं और जितने भी नकारा अध्यापक हैं उनको वीआरएस यार नियमावली के तहत रिटायरमेंट तत्काल प्रभाव से दे दे जिससे हम उत्तराखंड का भविष्य बचा पाए जय हिंद वंदे मातरम

29/04/2022, 09:22 - Messages and calls are end-to-end encrypted. No one outside of this chat, not even WhatsApp, can read or listen to them. Tap to learn more.
29/04/2022, 09:22 - +91 94103 42779: 🙏🙏👏👏
29/04/2022, 09:25 - +91 94103 42779: सेवा में ,, महोदय अपना परिचय है--
रमेश उपाध्याय
जिला -बागेश्वर
मो0--9410342779 ।
29/04/2022, 09:28 - +91 94103 42779: अपने राज्य में बजट की अत्यधिक आवश्यकता है -
बजट उतना ही आवंटन करें जितना धरातल पर कार्य हो
साथ ही कार्य पारदर्शी भी हो ,
29/04/2022, 09:32 - +91 94103 42779: कृपया अनावश्यक बजट आवंटन नहीं करे ।
जिसमें कार्य नहीं हो पाता है
और बजट को खपाने की चर्चाए होती हैं ।।
जब तक कि पुराना बजट धरातल पर पूर्ण रूप से खर्च नहीं हो जाता है ।
तब तक नया बजट आवंटन नहीं करें 🙏🙏

29/04/2022, 08:35 - Messages and calls are end-to-end encrypted. No one outside of this chat, not even WhatsApp, can read or listen to them. Tap to learn more.
29/04/2022, 08:35 - +91 84493 29073: मा० मुख्यमंत्री जी
बजट 2022-2023 के लिए मेरी राय है कि बजट में बेरोजगार युवा जो स्नातक और उससे ऊपर शिक्षित हैं, उन युवाओं को *10000* से *15000* *प्रति माह* तक *गुजारा* *भत्ता* प्रदान किया जाय।

Name - Ameer Chand Ramola
Add॰- Vill- Silari PO- Gairi
Tehsil- Pratapnagar
Tehri Garhwal
249196
mob॰- 8449329073

29/04/2022, 06:08 - Messages and calls are end-to-end encrypted. No one outside of this chat, not even WhatsApp, can read or listen to them. Tap to learn more.
28/04/2022, 23:58 - +91 90451 26698: 1- सरकारी दफ़्तरो में काम करने वाले अधिकारी/कर्मचारियों को निजी वहनो के प्रति लगाव कम करने के लिए साइकल से आने जाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिये, जिससे ईधन कि खपत पर असर होगा वही दूसरी ओर, लोगों में अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। इस हेतु जनजागरुकता कार्यक्रम करने चाहिए विभागवार विभागाध्यक्ष साइकल के प्रति जागरूकता हेतु कार्यक्रम किराए जाये। सरकारी कर्मचारियों को इस ओर आकर्षित करने हेतु अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि वेतन में दिए जाने पर भी विचार किया जा सकता है।
2- सरकारी अधिकारी/कर्मचारियो को वार्षिक फ़िज़िकल फ़िटनेस देना चाहिए, तथा फ़ील्ड में काम करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को इस संबंध में स्क्रीनिंग में सख़्ती से सख़्त निर्णय लेने चाहिये।
3- सरकारी अधिकारी/कर्मचारी को अपने राजकीय अथवा निजी आवाश में सोलर के माध्यम से विधुत उत्सर्जन पर विशेष कार्यक्रम चलाया जा सकता है। जिस हेतु सब्सिडी का प्रावधान देना चाहिये, जिसके प्रतिफल भविष्य में अच्छे मिलेंगे।
4- सरकारी विभागों में सामग्री क्रय हेतु GEM PORTAL को पूर्ण रूप से बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
4- समस्त कार्य ई-निविदा के माध्यम से कराए जाने चाहिये, ताकि राष्ट्रीय स्तर से निविदादाता प्रतिभाग कर सके व गुणवत्तापरक कार्य किए जा सके।

शेखर चन्द्र जोशी
वन विभाग, गोपेश्वर, चमोली
उत्तराखंड

29/04/2022, 07:12 - Messages and calls are end-to-end encrypted. No one outside of this chat, not even WhatsApp, can read or listen to them. Tap to learn more.
29/04/2022, 07:12 - +91 97602 04519: उत्तराखंड बजट में उत्तराखंड को हरा और स्वच्छ रखने के लिए आवश्यक कदमों को ध्यान रखना चाहिए-
1. प्लास्टिक और थर्माकोल के पत्तल, गिलास और प्लेट पूरी तरह बैन होना चाहिए। हरे पत्तल की उपलब्धता के लिए प्रयास होने चाहिए।
2. प्लास्टिक के ये सामान बैन होने से न प्लास्टिक कचरा होगा। न उसके निस्तारण की समस्या आयेगी और न उत्तराखंड प्रदूषित होगा।
3. वेस्ट डिस्पोजल के लिए ठोस नीति बनाने की जरूरत है। चाहे गढ़वाल हो या कुमाऊं, नगर निगम तक की गाड़ियां शहर से कूड़ा उठाकर जंगलों में या नदी के किनारे ही फेंकती हैं।
द्वारा- मनु हतेली।

28/04/2022, 20:57 - Messages and calls are end-to-end encrypted. No one outside of this chat, not even WhatsApp, can read or listen to them. Tap to learn more.
28/04/2022, 20:56 - +91 90588 88345: अगर बजट की हालत सुधारनी है तो सबसे पहले नेताओं को मिलने वाली बेहिसाब भत्तों like रहने का खाने का मोबाइल रिचार्ज यात्राओं etc. को बंद करना होगा और तनख्वाह mai भी भारी कटौती करने की जरूरत है. यहां आम इंसान पहले to नौकरी नहीं मिलती है अगर मिल भी जाए तो आठ 10,000 मिल रही है आजकल mostly cases mai private job mai.... और उस पर भी मोबाइल का बिल भरना टीवी का बिल भरना पानी का बिल भरना बिजली का बिल भरना घर के अंदर राशन भरना इन सब को भरते भरते आम इंसान का भर्ता निकल रहा है.. ये कहां का न्याय है ki करोड़ों की संपत्ति और लाखों रुपए सैलरी लेने वाले नेताओं को हर चीज फ्री में और आठ 10,000 कमाने वाले आम इंसान को रगड़ों के सिवाय कुछ नहीं..😔
इस तरह के फालतू खर्चा को बंद कर दीजिए और इससे बचे हुए पैसों को शिक्षा के क्षेत्र में लगाने की सख्त आवश्यकता है क्योंकि देश में नेशनल level k or Prestigious इंस्टिट्यूट को छोड़कर बाकी सारे कॉलेज डिग्री कॉलेज सब जगह फर्जी पढ़ाई हो रही है इन कुकरमुत्तों की तरह बने हुए स्कूल कॉलेज में पढ़ कर इंसान का बेड़ा गर्क हो रहा है यहां से डिग्री लेने के बाद ही इंसान ya to बेरोजगार बनता है ya 5000 10k से ज्यादा की नौकरी नहीं मिल रही है.. कम से कम ye स्कूल कॉलेज ऐसे होनी चाहिए jha जॉब & skill ओरिएंटेड पढ़ाई हो jo कुछ स्किल डेवलप करे इंसान के अंदर जिससे wo इतना काबिल बन पाए कि सरकार को टैक्स दे सके..
आज अगर आप लोग शिक्षा पर इन्वेस्ट करोगे तो wo भविष्य में Revenue बनकर आपके पास ही आएगा
28/04/2022, 21:00 - +91 90588 88345: or bi bhut सारी सलाहे हैं if u want then contect me i am available 24*7
aman negi
Contect no. 9058888345

28/04/2022, 20:51 - Messages and calls are end-to-end encrypted. No one outside of this chat, not even WhatsApp, can read or listen to them. Tap to learn more.
28/04/2022, 20:51 - +91 94103 66361: महोदय... मेरा एक सुझाव है शिक्षा के क्षेत्र में मिलने वाले बजट मे वृद्धि कर ग्रामीण निकाय के ऐसे विद्यालय जहां के छात्र-छात्राओं को ट्यूशन सुविधाएं नहीं मिल पाती वहां किसी पॉलिसी के तहत अतिरिक्त कक्षाएं संचालित की जाए ताकि ग्रामीण निकाय के विद्यालय कि छात्र-छात्राओं को मुक्त शिक्षा मिल सके व वहां अतिरिक्त कक्षाएं संचालित करने हेतु नजदीकी ग्रामीण इलाके से कोई युवा आगे आए व उस खर्चे का वहन राज्य सरकार करें

.... धन्यवाद.....

28/04/2022, 20:52 - +91 94103 66361: name : Soban kumar
28/04/2022, 20:53 - +91 94103 66361: Add: Village kyari kham Ramnagar(244715) Nainital

28/04/2022, 20:22 - Messages and calls are end-to-end encrypted. No one outside of this chat, not even WhatsApp, can read or listen to them. Tap to learn more.
28/04/2022, 20:21 - +91 95997 03842: कृपया अपने बजट मै इस बार उत्तराखण्ड के राज्य कर्मचारियों का पेंशन के उपर ध्यान दें, उन्हें रिटायर करने का मतलब ये नहीं कि सरकार उनका ध्यान देना ही छोड़ दें। नौकरी आप युवाओं को वैसे ही नहीं देते कम से कम बुजुर्गों पे तो रहम किजये इस महंगाई मे। याद रखिए उपर सबको जवाब देना है और करनी भी यहीं भुगतनी पड़ेगी।
धन्यवाद्। एक उत्तराखंडी।

28/04/2022, 19:16 - Messages and calls are end-to-end encrypted. No one outside of this chat, not even WhatsApp, can read or listen to them. Tap to learn more.
28/04/2022, 19:16 - +91 75008 21123: *उपनल कर्मचारियों की वेतन बढ़ोतरी हेतु बजट प्रस्ताव 2022-23 लागू करने हेतु*
अकुशल श्रेणी = 18,000
कुशल श्रेणी = 20,000
उच्च कुशल श्रेणी = 22,000
नाम = योगेन्द्र सिंह रावत
उपनल कर्मचारी

28/04/2022, 17:06 - Messages and calls are end-to-end encrypted. No one outside of this chat, not even WhatsApp, can read or listen to them. Tap to learn more.
28/04/2022, 17:05 - +91 89803 34925: उत्तराखंड माटीकला बोर्ड का पुनर्गठन कर योग्य व्यक्ति को चेयरमैन बनाएं व माटी शिल्प को आधुनिक बनाने हेतु इसके लिए पर्याप्त बजट का प्रावधान हो। जिससे कि माटीशिल्प को जीवनदान मिल सके।
आज तक माटीकला बोर्ड ओपचारिकता मात्र रहा है।
28/04/2022, 17:10 - +91 89803 34925: सत्यनारायण प्रजापति
संस्थापक , भारतीय प्रजापति हीरोज ओर्गेनाइजेशन रजि.
व संस्थापक संचालक, आल इंडिया कुम्हार प्रजापति पॉलिटिकल फेडरेशन रजि .

संपर्क नंबर 8980334925

BALBIR SINGH DHARMWAN , M.Sc(GEOLOGY), MISS (LM) , CHINHIT RAJAY PRAPTI ANDOLANKARI, VILLAGE – MANGOLI , OMKARESHWAR WARD NO-3 , UKHIMATH , DISTRICT -RUDRAPRAYAG , UTTARAKHAND , PIN CODE -246 469, TEL : 99187 97813 , 79822 73900, E mail : dharmwanbalbir50@gmail.com

To [illegible] Dated : 22.04.2022

Mr. Pushkar Singh Dhami,

Chief Minister of Uttarakhand, 4 Subhash Road, Uttarakhand Secretariate (Temporary) new Building 4th Floor,

Dehradun – 248 001 ,

Subject : My recent visit , observations and suggestions to Government of Uttarakhand.

Dear Sir,

During my recent visit I was at village for ten days , I visited many places and observed / told following

1.Most of the government employee are leaving their work place on Friday and coming back on Monday evening or on Tuesday , if somebody ask about their whereabout then to staff saying [illegible] went for [illegible] , further if public enquire then some of them are taking leave for whole week or remain absent and people are facing problems .

2.Chardham Yatra will start from next Month , I show there are many [illegible] and other problems on roads . Work of All Weather Road is in progress which has faulty design specially they are constructing "[illegible] Drains" at both side of road width at some places the drains are not at the end of the acquired land where [illegible] are not upto 10 feets , I show in these drains not a single drop of water is going all water from hill is coming on roads , during rain roads look like a nala / drain.

3.Chardham Yatra is about to start but there is no mobile network even on highway roads up to 10 kms which is very serious issue ?

4.There is no particular place for bus and taxi stop, drivers are stopping vehicles after every 5 – 10 m, due this problem 1.0 km distance is crossed in 1 Hr.

5. People done encroachment on roads by putting their articles , constructed building structure so that people are facing problem in travelling.

6. Before year 2000 at Ukhimath Tehsil HQ Government hospital, Surgery and plastering etc. use to be there , but now for these , people are going Srinagar or Dehradun and Ukhimath hospital became referal hospital only.

7.There is no proper electric supply , people don't know when the light will come and go.

My suggestion's to you:

1. Shift the state capital to "Gairsain (Permanent Capital)" where from over 7 years Vidhansabha [illegible] and residence for all are ready, then why shifting of capital is pending from Temporary Capital to Permanent Capital by delaying this you are fooling the people of Hills and cheating to souls of those who lost their lives for creation of Uttarakhand.

2.Don't allow the air travel of any MLA's , Minister / [illegible] & Government [illegible] [illegible] [illegible] by road in hills, Doing this they will get acquainted with problems in hills for which there are [illegible] [illegible] [illegible] people. Uttar Pradesh was much better than now, at least there were [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

Yours faithfully

Copy to :

1. Mr. Satpal Maharaj, Tourism Minister.
2. DM Rudraprayag.

(Balbir Singh Dharmwan)

M.Sc (Geology) , Ex Research Fellow , i) Garhwal University, Srinagar & ii) School of Environmental Sciences , JNU , New Delhi, Ex. Consultant of Ministry of Environment and Forest (MoEF)

For : i) Team Leader for Monitoring Tree Plantation of Dist. Badaun , U.P. & ii) Ex. Lady Domain Consultant for Soil & Geology. iii) Chinhit Rajya Prapti Andolnkari.

28/04/2022, 15:07 - Messages and calls are end-to-end encrypted. No one outside of this chat, not even WhatsApp, can read or listen to them. Tap to learn more.
28/04/2022, 14:51 - +91 79835 52314: सर/मैडम
सादर प्रणाम

मेरा सुझाव यह उत्तराखंड बजट 2022-23 के लिए की यह सुझाव है कि मेरा क्षेत्र पोखाल मंडल के अन्तर्गत मालिनी क्षेत्र आज भी विकास के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है, न ही पक्की सड़क, नही संचार सुविधा, और नही स्वास्थ्य, शिक्षा
ऊपर से हर साल बेरोजगारी से पलायन,
भूमि बंदोबस्ती भी इस बजट में होना चाहिए ।

धन्यवाद
सुशील मैठाणी
ग्राम सभा - बिजनूर
पोस्ट ऑफिस- मांडई
विकासखंड- दुगड्डा
तहसील -कोटद्वार
जिला - पौड़ी गढ़वाल
36 यमकेश्वर विधानसभा
उत्तराखंड
246144

28/04/2022, 15:07 - Messages and calls are end-to-end encrypted. No one outside of this chat, not even WhatsApp, can read or listen to them. Tap to learn more.
28/04/2022, 14:41 - +1 (818) 335-8454: I am from USA.
Here are my 2 Cents.

Water and Tourism.

I was in Uttarakhand just 2 weeks back. Being a tourist heaven, need somewhat better roads.

2nd is Water. Most of Rainwater gets wasted in Uttarakhand. Because of which the irrigation land is limited. If the Govt can capture more rainwater, it will help farmers, people and the state.

Allow me, if I can help, as I am working on a unique way of Capturing Rain water runoff.

I am in India till May 3rd.

This is a USA number, so only Wattsapp please.

Manmohan Chopra
28/04/2022, 14:43 - +1 (818) 335-8454: mkchopra@yahoo.com
28/04/2022, 14:44 - +1 (818) 335-8454: www.helpsaveavillage.org

28/04/2022, 14:03 - Messages and calls are end-to-end encrypted. No one outside of this chat, not even WhatsApp, can read or listen to them. Tap to learn more.
28/04/2022, 14:03 - +91 94115 44144: उत्तराखंड सरकार का आभार आम नागरिक को लेकर बजट बनना चाहिए

28/04/2022, 14:02 - Messages and calls are end-to-end encrypted. No one outside of this chat, not even WhatsApp, can read or listen to them. Tap to learn more.
28/04/2022, 14:02 - +91 96505 47980: कमल महरा।
पिथौरागढ़।
१. राज्य की नौकरियां राज्य के नौजवनों के लिए आरक्षित की जाए , जब कई बड़े राज्य जैसे मध्य प्रदेश , हरियाणा ऐसा कर रहे हैं तो हमारा राज्य जिसका निर्माण ही इस वादे के साथ हुआ था ऐसा क्यों नहीं कर सकता ।।

२. कठोर भूमि कानून निर्माण किया जाए ताकि बाहरी लोगों का यहां जमीन लेना रुके इससे होने वाले अपराधों में भी कमी आएगी और जमीन की कीमतों में कमी आएगी।।

३. बाहर से आने वाले पर्यटकों पर २००-५०० रुपए तक का टोल हर जिले में जाने पर लगाया जाए या बाहरी पर्सनल गाड़ियों को सीमा पर रोककर वहां से उत्तराखंड की गाड़ियों को चलाया जा सकता हैं , इससे एक तो यह जाम की समस्या रुकेगी , प्रदूषण घटेगा, और उत्तराखंड को अतिरिक्त राजस्व की प्राप्ति भी होगी।।।

28/04/2022, 13:32 - Messages and calls are end-to-end encrypted. No one outside of this chat, not even WhatsApp, can read or listen to them. Tap to learn more.
28/04/2022, 13:32 - +91 95369 44990: Hi
28/04/2022, 13:32 - +91 95369 44990: Berojgaro ko berojgari btta de
28/04/2022, 13:33 - +91 95369 44990: Brejgar Ghar se Paisa lekar kb tk form bherega ya idhar udhar jayega
28/04/2022, 13:33 - +91 95369 44990: Batta jarur milna chahiye

28/04/2022, 13:19 - Messages and calls are end-to-end encrypted. No one outside of this chat, not even WhatsApp, can read or listen to them. Tap to learn more.

28/04/2022, 13:19 - +91 95572 77450: मेरा नाम आयुष त्रिपाठी जिला चंपावत उत्तराखंड

28/04/2022, 13:22 - +91 95572 77450: आपसे निवेदन है कि इस बजट में इस समय जो सबसे ज्यादा घाटे में चल रही उत्तराखंड परिवहन निगम है जिसके मुकाबले कोई और विभाग घाटे में नहीं है उसको ज्यादा महत्व देने की जरूरत है पहाड़ की लाइफ लाइन कही जाने वाली रोडवेज आज खत्म की कगार पर है निवेदन है रोडवेज में युवाओं की भर्ती करी जाए जो कांग्रेस के टाइम से नहीं करी गई युवाओं को इस विभाग से बहुत लगाव है

28/04/2022, 13:04 - Messages and calls are end-to-end encrypted. No one outside of this chat, not even WhatsApp, can read or listen to them. Tap to learn more.
28/04/2022, 13:04 - +91 78383 94393: Excellent initiative
28/04/2022, 13:04 - +91 78383 94393: एक उत्तराखंडी होने के नाते मैं इस पहल की सराहना करता हूं 👍 🙏 👏 👏

यूपी बजट 2022 की दस बड़ी बातें

1. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि साल 2019 में पीएम मोदी ने पांच ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा था. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री [illegible] का योगदान अहम है इसलिए प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने तथा एक ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है.

2. वित्त मंत्री बजट पेश करते हुए कहा कि [illegible] का लक्ष्य रखा गया है. सूक्ष्म एवं लघु उद्यम [illegible] कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं की सुरक्षा एवं [illegible] के लिए 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है.

3. यूपी में दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान की धनराशि जो साल 2017 के पहले मात्र 300 रुपये प्रतिमाह प्रति व्यक्ति थी, उसे अब बढ़ाकर 1000 [illegible] दिया गया है. इससे प्रदेश के 11 लाख से अधिक दिव्यांगजन लाभान्वित हो रहे हैं. वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट में योजना के लिए 1000 करो[illegible] प्रस्तावित है.

4. [illegible] प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान [illegible] कृषकों के खेतों पर सोलर पम्पों की स्थापना कराई जा रही है. कृषि क्षेत्र में 5.1 प्रतिशत विकास दर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है. [illegible] निराश्रित गोवंश एवं बेसहारा पशुओं के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित किया गया है.

5. बता दें योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपने पहले बजट में कुंभ मेला प्रयागराज हेतु 100 करोड़ रुपए की घोषणा की है. [illegible] करोड़ रुपये और बुंदेलखंड की विशेष योजना के लिए 500 करोड़ रुपये की घोषणा की है.

6. [illegible] वित्तीय वर्ष 2022-2023 के बजट में [illegible] 650 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.

7. इस बार वृद्धावस्था पेंशन 500 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए की गई है. [illegible] 2,000 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है.

8. इस बार के बजट बाढ़ नियंत्रण के लिए 2700 करोड़ रुपये का बजट [illegible]

अवगत [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] 15 दिन [illegible]

6\. राज्य के बाहर का कोई [illegible] विद्यालय [illegible] के लिए [illegible] है तो [illegible] आवेदन करें।

8\. [illegible] के लिए [illegible]

[illegible]

निर्धारित प्रारूप पर [illegible] करें।

[illegible] सकती है।

पुलिस विभाग किसी विवाद के [illegible]

सकती है।

[illegible]

[illegible]

भवदीय

[illegible]

उत्तराखण्ड राज्य बजट हेतु सुझाव

माननीय वित्त मंत्री जी विज्ञापन से विदित हुआ कि राज्य के बजट हेतु सुझाव मांगे गये हैं। अतः अति संक्षिप्त शब्दों में निम्न सुझाव प्रेषित हैं।

पहाड़ी राज्य का बजट सर्वप्रथम पलायन रोकने वाला, भूमि सुधार शामिल अनिवार्य चकबन्दी करने, जंगल पहाड़ का जमीन तराई की जखानी पूरे राज्य की योजना सम्मिलित हो, समय का सदुपयोग हो, ईमानदारी के साथ निर्णय करने का मजबूत नीति हेतु बजट बनाने की नीति नीयत के साथ निर्णय लेने का संकल्प हो। सरकारी व अति आवश्यकता के अतिरिक्त, आरक्षित हाथ संचय हो आकांक्षी व जनप्रतिनिधियों से आशा है कि चुनावी वर्ष व चुनाव पूर्व होने पर, लोक लुभावन व प्रलोभन वाला न हो, रोजगार मुख हो, रचनात्मक बजट को प्राथमिकता दी जाय।

लेखक
पूर्व सं० केशवदत्त पुरोहित
उडेरखानी

NOKIA

मान मुख्यमंत्री जी,

आपसे अनुरोध है कि कृपया करके हरिद्वार पार्किंग व्यवस्था

ठीक करना है क्योंकि सारी जगह पानी, नालियां, रेहड़े, पटरे

कई जगह व रास्ते टूटे फूटे हैं। अगर आप थोड़े

तीर्थ स्थान की गरिमा और बढ़ जायेगी

धन्यवाद

राजेन्द्र

9520820683

BALBIR SINGH DHARMWAN , M.Sc(GEOLOGY), MIGS (LM) , CHINHIT RAJAY PRAPTI ANDOLANKARI, VILLAGE – MANGOLI ,OMKARESHWAR WARD NO.-3 , UKHIMATH , DISTRICT -RUDRAPARAYAG , UTTARAKHAND , PIN CODE -246 469, TEL .: 96187 87431 , 79028 73900, E-mail. : dharmwanbalbir60@gmail.com

To   Speed Post   Dated : 22.04.2022

Mr. Pushkar Singh Dhami

Chief Minister of Uttarakhand, 4 Subhash Road, Uttarakhand Secretariate (Temporary), New Building 4th Floor,

Dehradun – 248 001

Subject : My recent visit , observations and suggestions to Government of Uttarakhand .

Dear Sir,

During my recent visit I was at village for ten days , I visited many places and observed / find following:

1.Most of the government employee are leaving their work place on Friday and coming back by Monday evening or on Tuesday , if somebody ask about their whereabout then co staff say he /she went for meeting, further if public enquire then some of them are taking leave for whole week or remain absent and people are facing problems.

2.Chardham Yatra will start from next Month , I show there are many pits and other problems on roads . Work of All Weather Road is in progress which has faulty design specially they are constructing "Covered Drains" at both side of road width at some places the drains are not at the end of the acquired land where land is left out upto 10 feets , I show in these drains not a single drop of water is going all water from hill is coming on roads , during rains roads looks like a nala / drain ?

3.Chardham Yatra is about to start but there is no mobile network even on highway roads up to 30 Kms, which is very serious issue. ?

4.There is no particular place for bus and taxi stop, drivers are stopping vehicle after every 5 – 10 m due this problem 3.0 Km distance is crossed in 1 Hr.

5. People done encroachment on roads by putting their articles , constructed building structure so that people are facing problem in travelling.

6. Before year 2000 at Ukhimath Tehsil HQ Government hospital, surgery and plastering etc. use to be there , but now for these people are going Srinagar or Dehradun and Ukhimath hospital became referal hospital only.

7.There is no proper electric supply , people don t know when the light will come and go ?

My suggestion's to you:

1. Shift the state capital to "Gairsain (Permanent Capital)" where from over 7 years Vidhansabha Bhawan and residence for all are ready, then why shifting of capital is pending from **Temporary Capital to Permanent Capital** by delaying this you are fooling the people of Hills and cheating to souls of those who lost their lives for creation of Uttarakhand.

2.Don't allow the air travel of any MLA's , Minister / Neta's & Government employ . Everybody must travel by roads in Hills, doing this they will get acquainted with problems in hills for which Uttrakhand was demanded, otherwise for general people Uttar Pradesh was much better than now, at least there were much more job opportunities etc.

Your's Faithfully,

Copy to :

1. Mr. Satpal Maharaj,Tourism Minister.
2. DM Rudraprayag.

Balbir 22/04/2022

(BALBIR SINGH DHARMWAN)

M.Sc(Geology) , Ex. Research Fellow : i) Garhwal University , Srinagar & ii) School of Environmental Sciences , JNU , New Delhi,Ex. Consultant of : Ministry of Environment and Forest (MoEF)

For : i) Team Leader for Monitoring Tree Plantation of Dist. Badaun , U.P. , & ii) EIA/EMP Domain Consultant for Soil & Geology. & Chinhit Rajya Prapti Andolnkari.